राष्ट्रीय संस्करण



मुक्केबाज लवलीना पदक से एक कदम दूर >>12

दैनिक जागरण

वर्ष 5 अंक 48

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, बुधवार, 28 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

त्वचा बनकर वर्न इंजरी को संक्रमण से बचाएगी पट्टी



कानपुर : जलने पर मरीज के सामने सबसे बड़ा खतरा संक्रमण का होता है। कई बार संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि मरीज की जान पर बन आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में घाव में संक्रमण नहीं फैलेगा और वह तेजी से ठीक भी होगा। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

भारत-अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देगी ब्लिंकन से वार्ता

नई दिल्ली : अमेरिका-भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा कैसी होगी, इसे तय करने में बुधवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच की बैठक अहम होगी। बतौर विदेश मंत्री ब्लिंकन पहली भारत यात्रा पर मंगलवार देर शाम नई दिल्ली पहुंचे। इसबीच अमेरिका ने भारत को एक मजबूत रणनीतिक साझीदार बताया गया है।

राजनीति ▶ पृष्ठ 4

बासवराज बोम्मई होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री

बेंगलुरु : बासवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक होटल में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। वह उत्तरी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं और लिंगायत समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। वह बुधवार को 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे।

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 7

पाजिटिव निकले क्रुणाल पांड्या, दूसरा टी-20 स्थगित

नई दिल्ली : आलराउंडर क्रुणाल पांड्या के कोरोना पाजिटिव पाए जाने के बाद भारत व श्रीलंका के बीच मंगलवार को कोलंबो में होने वाला दूसरा टी-20 क्रिकेट मैच स्थगित कर दिया गया। अब यह मैच बुधवार को खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी टी-20 मैच गुरुवार को होगा।

असम-मिजोरम विवाद सुलझाने को केंद्र ने की पहल

- गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाई
- गृह मंत्री शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों से शांति बनाए रखने की अपील की

नई दिल्ली, प्रेट्र : असम और मिजोरम की सीमा पर सोमवार को हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मोर्चा संभाला है। मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बुधवार को बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर शांति बनाए रखने की अपील की है। सोमवार शाम मिजोरम पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में असम पुलिस के पांच जवानों समेत छह लोगों की मौत हो गई थी। 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मंगलवार को दोनों राज्यों की सीमा पर शांति रही।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, जिससे फिर हिंसा की स्थिति न बने। केंद्र सरकार दोनों सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है और हालात को शांत रखने का प्रयास कर रही है। टकराव वाली जगह पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की छह कंपनियों को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप ने बताया कि हालात शांतिपूर्ण हैं।



अमित शाह। फाइल/इंटरनेट मीडिया

इस बीच, संसद में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा, राज्यों के बीच के सीमा विवाद आपसी सहयोग से ही सुलझाए जाते हैं। केंद्र इन मामलों में केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा, सीमाओं के निर्धारण के बाद से कई राज्यों में इस संबंध में विवाद हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, हरियाणा-हिमाचल, लद्दाख-हिमाचल, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल, असम-नगालैंड, असम-मेघालय और असम-मिजोरम के बीच सीमा विवाद हैं।

स्थायी समाधान के लिए पूर्ण सीमांकन की जरूरत पेज>>5

गृह मंत्री की सतर्कता ने संभाले हालात

एएनआइ से बातचीत में सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की तत्परता व सीआरपीएफ के हस्तक्षेप ने मामले को बिगड़ने से बचाया। उन्होंने कहा, सौभाग्य से सीआरपीएफ की दो कंपनियां असम और मिजोरम के बीच टकराव वाले लैलापुर-वैरेंगत क्षेत्र में दोनों राज्यों के पुलिसबलों के सहयोग के लिए तैनात थीं। हिंसा भड़कते ही सीआरपीएफ के आला अफसरों ने गृह मंत्रालय से बात की। इसके बाद सीआरपीएफ के जवान हालात संभालने में जुट गए। गृह मंत्री स्वयं पूरे मामले की निगरानी कर रहे थे।



सीमा विवाद को लेकर हुए संघर्ष में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों को कछार स्थित एसपी कार्यालय में श्रद्धांजलि देते असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा। प्रेट्र

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सरमा: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने राज्य के फारेस्ट रिजर्व को अतिक्रमण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, सेटेलाइट की तस्वीरों से देखा जा सकता है कि किस तरह यहां अतिक्रमण हो रहा है। सरमा ने कहा, यह राजनीतिक नहीं सीमा विवाद है। जब दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं, तब भी यह मुद्दा था। उन्होंने मिजोरम से लगी सीमा पर 3000 जवानों की तैनाती की बात भी कही है। असम सरकार ने मिजोरम से समझौते के पालन की अपील की है।

असम में तीन दिन का शोक : मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के सम्मान में असम में तीन दिन का शोक घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री सरमा ने मृतक पुलिसकर्मियों के स्वजनों को 50-50 लाख रुपये और सभी घायलों को एक-एक लाख रुपये की मदद देने का भी एलान किया है। सरमा ने कहा, फायरिंग के दौरान उन्होंने मिजोरम के सीएम जोरमथंगा से बात की थी। उन्होंने घटना के लिए माफी मांगते हुए वार्ता के लिए बुलाया है।

विपक्ष को बेनकाब करें भाजपा सांसद : मोदी

आक्रामक रुख ▶ संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने दिया निर्देश

पीएम ने कहा, कोरोना समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एक सप्ताह से अधिक का वक्त गुजर चुका है और संसद का कामकाज ठप है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों को निर्देश दिया है कि विपक्ष और खासकर कांग्रेस को जनता के सामने बेनकाब करें। उन्हें बताएं कि जान-बूझकर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। मनगढ़ंत आरोप लगाया जाता है। कोरोना जैसे अहम मुद्दे पर बैठक का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बहिष्कार करती है। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसे सिर्फ हंगामा अच्छा लगता है।

मंगलवार को संसदीय दल की बैठक में पीएम का निर्देश था कि जनता व मीडिया के सामने विपक्ष को तथ्यों के साथ बेनकाब करना चाहिए। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनुसार, मोदी ने कहा, कोरोना जैसे मुद्दे, जिससे पूरा देश जूझ रहा है, पर संसद के भीतर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा के दौरान विपक्ष को सरकार की कमियों को उजागर करने का मौका मिलता। वहीं सरकार को इससे निपटने के लिए उठाए गए कदमों को रखने का अवसर भी मिलता।

- सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष को हंगामा अच्छा लगता है
- कोरोना जैसे मुद्दे पर संसद के भीतर व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी



नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बाहर निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

इसलिए ज्यादा दम दिखा रहा विपक्ष

संसद का मानसून सत्र राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इसके पहले बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, जिससे विपक्ष उत्साहित है। आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव है। यही कारण है कि विपक्ष कुछ ज्यादा दम दिखा रहा है।

मानसून सत्र के पहले दिन से हंगामा

मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के नए मंत्रियों का परिचय भी नहीं कराने दिया था। उसके बाद से विपक्ष पेगासस मुद्दे पर संबंधित मंत्री का बयान तक नहीं होने दे रहा है।

सरकार की तरफ से जारी है बातचीत

संसद में विपक्ष द्वारा उत्पन्न गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से बातचीत जारी है। लेकिन संकेत है कि इस सप्ताह भी विपक्ष कामकाज को ठप ही रखना चाहता है।

जल्द रास्ता नहीं निकला तो उग्र होगा टकराव

- पहले दिन भी मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार में महिला, अनुसूचित जाति, ओबीसी, आदिवासी मंत्री बढ़े हैं। कांग्रेस को यह नहीं पच रहा है।
- साफ है कि बहुत जल्द सरकार और विपक्ष के बीच कोई रास्ता नहीं निकला तो टकराव और उग्र हो सकता है। ऐसे में पूरा सत्र कुछ मामूली कामकाज के साथ धुल सकता है।

आजादी के 75वें साल के कार्यक्रमों से जनता को जोड़ने की सलाह

सांसदों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि आजादी के 75वें साल के कार्यक्रमों का आयोजन सिर्फ सरकार का काम नहीं होना चाहिए। इसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने सभी सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र के हर गांव में इसके कार्यक्रम आयोजित करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर सांसद अपने क्षेत्र के हर विधानसभा के लिए दो कार्यकर्ताओं की समिति का गठन करें, जो कम-से-कम 75 गांवों में 75 घंटे बिताकर लोगों से यह जानने की कोशिश करे कि आजादी के 100वें साल यानी 2047 में वे कैसे भारत की परिकल्पना करते हैं। इसके साथ ही वे गांव वालों से आजादी के 75वें साल के अवसर पर स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुझाव भी जुटाएं। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में स्थानीय खेलों और स्वच्छता अभियान को भी शामिल किया जा सकता है।

किसानों की चिंता है तो सदन चलने दें : तोमर

नई दिल्ली, प्रेट्र : कृषि कानूनों को लेकर संसद नहीं चलने दे रहे विपक्ष पर मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर उन्हें किसानों की चिंता है तो सदन में कामकाज होने दें।



लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसानों से जुड़ी एक बीमा योजना से संबंधित पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की। जिस समय तोमर यह बात कह रहे थे, उस समय भी विपक्षी सदस्य पेगासस जासूसी से जुड़े आरोपों और कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर नारेबाजी जारी रखे थे। तोमर ने कहा, किसानों से जुड़े 15 सवाल हैं। अगर विपक्षी सदस्यों को वास्तव में किसानों की चिंता है तो उन्हें सरकार की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, लगातार व्यवधान सदन की मर्यादा को कम कर रहा है। बता दें कि किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जहां इन्हें उनके हित में बता रही है वहीं किसानों का कहना है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को खत्म कर देंगे और उन्हें कारपोरेट घरानों की दया पर छोड़ दिया जाएगा।

राकेश अस्थाना बने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर

नई दिल्ली, प्रेट्र : गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया है।



राकेश अस्थाना। फाइल फोटो/प्रेट्र

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक अस्थाना तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस के आयुक्त का कार्यभार संभालेंगे। अस्थाना इस समय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक पद पर तैनात हैं।

यह अहम बात है कि अस्थाना को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के रूप में नियुक्ति दिए जाने के साथ ही एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है जब एजीएमयूटी यानी अरुणाचल प्रदेश-गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र कैडर से बाहर के किसी आइपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का प्रमुख बनाया गया है। आम तौर पर इस पद पर इसी कैडर के आइपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाता रहा है।

राकेश अस्थाना भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं। वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के विशेष निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सीबीआइ में अपने कार्यकाल के दौरान वह इस एजेंसी के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा के साथ चर्चित विवाद में शामिल रहे थे।

अनाथ बच्चों की पहचान में और देरी बर्दाश्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पिछले वर्ष मार्च के बाद से अनाथ हुए बच्चों का मामला
- कोर्ट ने राज्य सरकारों से ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए उठाए गए कदमों पर मांगी रिपोर्ट
- कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा जारी रखने का दिया आदेश



सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मार्च के बाद माता-पिता खोकर अनाथ हुए बच्चों की पहचान और देखभाल के प्रति चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे बच्चों की पहचान में और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अनाथ बच्चों की पहचान और देखभाल के बारे में सभी राज्यों से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। यह भी बताने को कहा कि उन्होंने आइसीपीएस योजना के मुताबिक कितने अनाथ बच्चों को प्रति माह 2,000 रुपये की आर्थिक मदद दी है। राज्यों को कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा जारी करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।

ये आदेश न्यायमूर्ति एलएन राव व अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिए। कोर्ट ने कहा, सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं और मदद की घोषणा की हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग के मुताबिक 34 योजनाएं हैं। योजनाओं का लाभ अनाथ बच्चों तक पहुंचना चाहिए। कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे ऐसे बच्चों की पहचान के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी को जरूरी निर्देश जारी करें। कोर्ट ने कहा, जिन बच्चों ने मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या एक संरक्षक खो दिया है उनकी पहचान में और देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि वह इस अवधि के दौरान अनाथ हुए सभी बच्चों को चिह्नित करने की बात कर रहा है, चाहे उनके माता-पिता की कोरोना से मौत हुई हो या फिर किसी और वजह से।

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि एनसीपीआरसी के पोर्टल बाल स्वराज पर राज्यों द्वारा ऐसे बच्चों के दर्ज किए गए ब्योरे और राज्यों के आए जवाब को देखते हुए कोर्ट को दो मुद्दों पर निर्देश देने की जरूरत है। एक तो जो बच्चे संरक्षक के साथ रह रहे हैं, क्या उनके संरक्षक उनका खर्च वहन करने की स्थिति मे हैं या उन्हें किसी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत है। अगर मदद की जरूरत है तो उन्हें तत्काल आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। अग्रवाल ने कहा कि दूसरा मुद्दा ऐसे बच्चों की शिक्षा जारी रखने का है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि वे ऐसे बच्चों की शिक्षा जारी रखना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय बाल आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से कहा गया है कि पोर्टल पर ऐसे बच्चों का ब्योरा अपलोड करने के पांच स्तर दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों ने सिर्फ दो स्तर तक ब्योरा अपलोड किया है।

कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बताएंगे कि उनके यहां कितने अनाथ बच्चों की पहचान की गई है? कितने बच्चों को योजना का लाभ दिया गया? मामले में कोर्ट 26 अगस्त को फिर सुनवाई करेगा।

बंगाल के रवैये पर जताई नाराजगी

राष्ट्रीय बाल आयोग ने यह भी कहा कि कुछ राज्यों जैसे बंगाल और पंजाब ने बहुत कम बच्चों के अनाथ होने की जानकारी पोर्टल पर डाली है। इस पर कोर्ट ने बंगाल के वकील से सवाल किया तो उन्होंने कहा, यह जारी रहने वाली प्रक्रिया है और कोर्ट को इसकी प्रक्रिया समझाने लगे। कोर्ट ने राज्य सरकार के ढीले रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, आप ऐसी दलील कैसे दे सकते हैं। अनाथ बच्चों की देख-रेख की जिम्मेदारी आपकी है। आपको सक्रियता से काम करना चाहिए।

तीसरी लहर का खतरा गहराया, 10 फीसद संक्रमण दर वाले जिले बढ़े

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सरकार ने कहा, पिछले 10 दिनों में ऐसे जिलों की संख्या 47 से बढ़कर 54 हुई
- कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट कम हुई, 22 जिलों में बढ़ने लगे मामले

देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद पहली बार देश में 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या बढ़ी है। राहत की बात यह है कि ऐसे जिले अभी तक मुख्य रूप से केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमित हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, एक तरफ पिछले तीन हफ्ते से कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट थम गई है, वहीं दूसरी तरफ 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या बढ़ने लगी है। फिलहाल इसे कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत नहीं कहा जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी अभी स्थिति पर नजर रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसे तीसरी लहर के खतरे के संकेत के रूप में जरूर देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले 54 जिलों में केरल के 10, मणिपुर के 10, नागालैंड के सात, मिजोरम व मेघालय के छह-छह, अरुणाचल प्रदेश के पांच, राजस्थान के चार, सिक्किम के दो और हरियाणा, दमन व दीव, असम व पुडुचेरी के एक-एक जिले शामिल हैं। 16 जुलाई को इन जिलों की संख्या 47 थी। मणिपुर, केरल, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा में 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या बढ़ी है। वहीं राजस्थान में कम हुई है।

नए मामलों में बढ़ोतरी चिंता का कारण : सिर्फ संक्रमण दर ही नहीं, कई जिलों में नए केस में तेज बढ़ोतरी भी चिंता का सबब बन गया है। देश में 22 जिले ऐसे हैं, जिनमें नए मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनमें केरल के सात, मणिपुर के पांच, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के तीन-तीन, महाराष्ट्र के दो और असम व त्रिपुरा के एक-एक जिले शामिल हैं।



लव अग्रवाल। फाइल/इंटरनेट मीडिया

10 जिले कम हुए तो 15 जिले बढ़े

16 जुलाई को जिन 47 जिलों में 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर थी, उनमें से आठ जिलों में संक्रमण दर 10 फीसद से कम हो गई है। लेकिन, 15 नए जिलों संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा हो गई है।

देश में प्रतिदिन आने वाले नए केस में गिरावट थम गई है। पांच से 11 मई के बीच औसतन पौने चार लाख मामले प्रतिदिन मिल रहे थे, जो जून के अंतिम हफ्ते में गिरकर औसतन 48 हजार प्रतिदिन तक आ गए, लेकिन उसके बाद से मामलों में तेज गिरावट नहीं आ रही है। पिछले तीन हफ्ते से प्रतिदिन औसतन 38 हजार मामले सामने आ रहे हैं।

नीति आयोग के सदस्य और टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डा. वीके पाल ने कहा कि 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या में बढ़ोतरी एक संयोग भी हो सकता है। लेकिन नए केस में लगातार गिरावट वाले जिलों में अचानक बढ़ोतरी चिंता का कारण है।

सुविधा

शिक्षा मंत्रालय ने भारत नेट कार्यक्रम के जरिये स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने पर शुरू किया काम, आनलाइन शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम बनाने पर जोर, देश में वर्तमान में हैं करीब 10 लाख सरकारी स्कूल

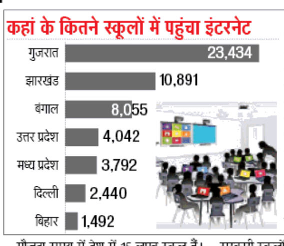
इंटरनेट से जुड़ेंगे सभी सरकारी स्कूल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने सहित सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम में तब्दील करने की मुहिम के बीच केंद्र सरकार ने देश भर के सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से लैस करने का फैसला किया है। अब तक 1.19 लाख सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। बाकी सभी स्कूलों को भी उस गांव तक फाइबर नेटवर्क पहुंचते ही जोड़ दिया जाएगा।

स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने की यह मुहिम इसलिए भी तेज हुई है, क्योंकि इसके जरिये विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों को दूसरे स्कूलों से आनलाइन जोड़ा जा सकेगा। स्कूली छात्रों को इससे फायदा होगा। इसके साथ ही स्मार्ट क्लासरूम के जरिये छात्र देश-दुनिया के बेहतरीन शिक्षकों के वीडियो देख सकेंगे और ऐसे पाठ पढ़ सकेंगे, जिन्हें समझने के लिए उन्हें ट्यूशन या कोचिंग की मदद लेनी पड़ती है, जो ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आसानी से नहीं मिल पाती है।

कहां के कितने स्कूलों में पहुंचा इंटरनेट



1.19 लाख स्कूलों तक पहुंची सुविधा : जो गांव फाइबर कनेक्टिविटी से जुड़ गए हैं, वहां के स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से लैस करने का काम शुरू कर दिया गया है। आगे भी जैसे-जैसे गांवों में यह लाइन पहुंचेगी, वहां के सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों तक को इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुहिम के तहत अब तक 1.19 लाख स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है।

मौजूदा समय में देश में 15 लाख स्कूल हैं। इनमें करीब 10 लाख सरकारी हैं, जो अभी तक इंटरनेट सुविधा से वंचित थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह हाईटेक सुविधाओं से लैस करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में संसद को दी गई जानकारी में बताया कि सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने का तेजी से चल रहा है। भारतनेट कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023 तक सभी गांवों को फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

स्कूली छात्रों को साल में कम से कम एक बार जरूर दिखाएं संग्रहालय पेज>>5

सहकारिता मंत्रालय के गठन पर कैबिनेट की आज लग सकती मुहर

नई दिल्ली : सहकारिता मंत्रालय के गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अलग मंत्रालय बनाने की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। विचार के बाद तैयार कैबिनेट मसौदा वितरित हो चुका है, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में मुहर लग जाने की संभावना है। (पेज-3)

गुलाम कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत

मुजफ्फराबाद : गुलाम कश्मीर (गिलगिट-बाल्टिस्तान) में चुनाव के दौरान सरकारी अराजकता और धांधली के कारण पाकिस्तान की सेना के खिलाफ विद्रोह हो गया है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे लोगों की सुरक्षा बलों के साथ कई स्थानों पर झड़प भी हुई। टायर जलाकर जगह-जगह रास्ता जाम कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि गुलाम कश्मीर में 25 जुलाई को हुए विधान सभा चुनाव हुए थे। (पेज-11)

1 अगस्त से चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसके लिए आनलाइन बुकिंग 31 जुलाई से शुरू हो जाएगी। एक दिन में केवल तीन हजार पर्यटक ही चिड़ियाघर में आ सकेंगे।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 28 जुलाई, 2021

दिल्ली में जुलाई की जोरदार बारिश ने तोड़ा 18 साल का रिकार्ड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक सफदरजंग पर हुई 382.8 मिमी बारिश, 2003 के बाद अभी तक इस माह की सर्वाधिक
- सुबह साढ़े आठ बजे तक महज तीन घंटों में हुई 100 मिमी बारिश, यह भी 24 घंटों के दौरान आठ सालों की सबसे ज्यादा

दिल्ली में मानसून देर से भले ही आया हो, लेकिन अब राजधानी में अच्छी बारिश हो रही है। मंगलवार शाम तक इस माह में अब तक 382.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है जो 2003 के बाद जुलाई में सबसे अधिक है। मंगलवार सुबह भी केवल तीन घंटों में ही 100 मिमी बारिश दर्ज की गई। यह भी आठ साल में जुलाई में 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक बारिश है। इससे पूर्व 2013 में 21 जुलाई को 123.4 मिमी बारिश हुई थी।

गौरतलब है कि निर्धारित समय से 16 दिन देरी से 13 जुलाई को मानसून आने के बावजूद राजधानी में इस महीने अब तक बारिश के 14 दिन दर्ज किए गए हैं। 19 वर्षों में सर्वाधिक विलंबित मानसून अब दिल्ली को भिगो रहा है। मौसम विभाग ने सफदरजंग पर अभी तक 108 फीसद अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है। 27 जुलाई तक सामान्य बारिश है 183.5 मिमी जबकि हो चुकी है 380.9 मिमी बारिश।

आमतौर पर दिल्ली में जुलाई में 210.6 मिमी बारिश दर्ज की जाती है। पिछले साल 236.9 मिमी, 2019 में 199.2 मिमी और 2018 में 286.2 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। 2017 में 170.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, 2016 में 292.5 मिमी और 2015 में 235.2 मिमी हुई।

2013 में दिल्ली में 340.5 मिमी बारिश हुई थी। 2003 में आल टाइम रिकार्ड 632.2 मिमी बारिश का है।

स्काइमेट वेदर के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान) महेश पलावत के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बारिश के दिनों की संख्या में कमी आई है और चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि शहर कम समय में अधिक वर्षा दर्ज कर रहे हैं। पहले 100 मिमी बारिश तीन से चार दिनों में होती थी। अब हमें केवल पांच-छह घंटों में इतनी वर्षा मिल रही है। हालांकि पलावत के मुताबिक बारिश के ऐसे दौर भूजल रिचार्ज करने में मदद नहीं करते बल्कि निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ का कारण बनते हैं। अगर चार से पांच दिन धीमी बारिश होती है तो पानी जमीन में रिसता है। जबकि तेज बारिश की स्थिति में पानी जल्दी बह जाता है।

इस बीच, जलभराव से निपटने के लिए विभागों द्वारा किए गए दावे भी बारिश के पानी में डूब गए। स्थिति ये रही कि इस जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालक घंटों जाम में फंसे रहे। बारिश इतनी जबर्दस्त हुई कि कई जगह दुकानों और घरों के अंदर भी पानी चला गया। डीटीसी बसों में पानी घुस गया। कई जगह अंडरपास में पानी भरने से यातायात को डायवर्ट करना पड़ा।

पानी घुसने के कारण दो घंटे बंद रहा साकेत मेट्रो स्टेशन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश के चलते महरौली बदरपुर रोड पर जगह-जगह जलभराव हो गया। एमबी रोड पर हुए जलभराव के चलते सड़क के किनारे बने मेट्रो स्टेशन में पानी जाने लगा, जिससे साकेत मेट्रो स्टेशन को दो घंटे से अधिक समय के लिए बंद करना पड़ा। डीएमआरसी के अधिकारियों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी का नाला जाम होने के कारण सड़क पर भरा पानी गेट नंबर एक से स्टेशन के अंदर आ गया था। इसके चलते मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था।

मंगलवार दोपहर एमबी रोड पर भरा हुआ पानी अचानक से साकेत मेट्रो स्टेशन के अंदर जाने लगा जिसके चलते मेट्रो प्रशासन ने स्टेशन को बंद कर दिया। डीएमआरसी ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक स्टेशन के पास पीडब्ल्यूडी का नाला है जो कि जाम हो गया था। इससे सड़क का पानी ओवरफ्लो होकर स्टेशन के अंदर जाने लगा। इस कारण दो घंटे से अधिक समय के लिए मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा। स्थिति सामान्य होने के बाद मेट्रो स्टेशन दोबारा खोल दिया गया था।



साकेत मेट्रो स्टेशन के बाहर एमबी रोड पर जमा बारिश के पानी के कारण मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया। फोटो सौजन्य- वीडियो ग्रैब

कम से कम पांच दिनों का हो विधानसभा का मानसून सत्र : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा विधायकों ने विधानसभा का मानसून सत्र कम से कम पांच दिन करने की मांग की है। इसे लेकर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई से शुरू होने वाला सत्र सिर्फ दो दिनों का है। दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसकी अवधि बढ़ाने की जरूरत है। विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद विधायकों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा विधायकों ने कई विषयों पर अल्पकालिक चर्चा कराने का नोटिस दिया है। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट है। स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदूषण की समस्या गंभीर है। परिवहन व्यवस्था पर गंभीर संकट छाया हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष से इन सभी विषयों पर चर्चा का अनुरोध किया गया है।

न्यूज गैलरी

दिल्ली दंगा मामले में उमर की जमानत अर्जी का विरोध

नई दिल्ली : दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करते हुए कहा कि आरोपित की जमानत अर्जी आधारहीन है। अब इस मामले में सात अगस्त को सुनवाई होगी। उमर खालिद को स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। (जासं)

मेट्रो में नियम उल्लंघन के लिए 263 यात्रियों पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली : मेट्रो में बैठने की पूरी क्षमता के साथ परिचालन की सुविधा होने के बाद दो दिनों से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए मेट्रो में पहले के मुकाबले अधिक यात्री सफर कर रहे हैं। इस दौरान मेट्रो में कई यात्री खड़े होकर भी सफर करते देखे जा रहे हैं। इससे मेट्रो ने सख्ती बढ़ा दी गई है। लिहाजा मंगलवार को 263 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया। एक दिन पहले 159 यात्रियों पर जुर्माना लगाया गया था। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अनुसार मंगलवार को रात आठ बजे तक करीब साढ़े आठ लाख यात्रियों ने करीब 16.9 लाख यात्राएं कीं। डीएमआरसी का कहना है कि मेट्रो में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा नियमों का पालन नहीं करने पर 292 यात्रियों को मेट्रो से उतार भी दिया गया। (राब्यू)

कैग से कराई जाए जल वोर्ड के कामकाज की जांच : भाजपा

नई दिल्ली : भाजपा दिल्ली जल बोर्ड के कामकाज को लेकर सवाल खड़े कर रही है। उसका आरोप है कि बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। पैसे किस काम में खर्च किए जा रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया जा रहा है। भाजपा ने इसके कामकाज की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से या किसी अन्य से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को पत्र लिखा है। (राब्यू)

पेड़ों की कटाई रोकने पर विचार करने से एनजीटी का इन्कार

नई दिल्ली : सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) कालोनियों के पुनर्विकास की परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने विचार करने से इन्कार कर दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की वाली पीठ ने कहा कि आवेदक पहले ही इसी विषय पर याचिका दायर कर चुका है और उसी मामले में दूसरी याचिका विचार करने योग्य नहीं है। (जासं)

दिल्ली सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए डाक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों के नाम भेजेगी

एलान ▶ दिल्ली वाले तय करेंगे किसे मिले पद्म पुरस्कार, सरकार ने जारी की मेल आइडी

डिप्टी सीएम सिसोदिया की अध्यक्षता में बनाई गई सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना काल में डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के सराहनीय योगदान को देखते हुए इस बार दिल्ली सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए केवल डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के नाम केंद्र सरकार के पास भेजेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेसवार्ता कर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए जिनके नाम केंद्र को भेजेगी, वह नाम दिल्ली की ही जनता बताएगी। दिल्ली का कोई भी नागरिक <e>padmaawards.delhi@gmail.com पर पूरी जानकारी के साथ किसी भी डाक्टर या स्वास्थ्यकर्मी का नाम 15 अगस्त तक भेज सकता है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में फैसला लेने के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में सर्च एंड स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जो जनता की ओर से आए हुए नामों की स्क्रीनिंग करेगी। इसके बाद दिल्ली सरकार वे नाम 15 सितंबर से पहले केंद्र को भेजेगी। मुख्यमंत्री ने कहा



अरविंद केजरीवाल। एएनआइ

कि दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली ऐसी राज्य सरकार है, जिसने कोरोना काल में लोगों की सेवा करते-करते शहीद हुए स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि दी। अब यह समय सभी डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का सम्मान करने का है।

केजरीवाल ने कहा कि हर वर्ष देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्म पुरस्कार से सम्मानित करता है, जिन लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हो। उन्होंने कहा, 'मैं यहां तीन पुरस्कारों की बात कर रहा हूं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। इन तीनों पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है। सभी राज्य सरकारों को भी अपने-अपने राज्य से नाम देने के लिए लिखती है। कोरोना काल में दी गईं सेवाओं के लिए पूरा देश डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की कर्जदार है। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार का पद्म पुरस्कार डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को दिए जाएं।' मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित करने का यह सही तरीका है। लोग मेल के जरिये अपनी राय व्यक्त करें और नाम सुझाएं।

मृत कोरोना योद्धाओं के स्वजन को मुआवजा देने का वादा पूरा करे दिल्ली सरकार : भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डाक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों को पद्म पुरस्कार दिलवाने की बात करते हैं, लेकिन जनता की सेवा करते हुए जान गंवाने वाले योद्धाओं के साथ वह भेदभाव कर रहे हैं। ये कहना है भाजपा का। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत कोरोना काल में जान गंवाने वाले योद्धाओं व उनके स्वजन को मुआवजा देने की जानकारी मांगी थी। उन्हें बताया गया कि एक अप्रैल, 2020 से इस वर्ष 20 जुलाई तक 170 योद्धाओं की मौत हुई है और इनमें से सिर्फ 17 लोगों के स्वजन को मुआवजा दिया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर केवल वाहवाही लूटने को आतुर रहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले अपने वादे के अनुसार सभी मृतक कोरोना योद्धाओं के स्वजन को एक-एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस के सिपाही अमित राणा के परिवार को भी एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया।

आरटीआइ से मिली जानकारी से भी स्पष्ट है कि सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आरटीआइ के जवाब में सिर्फ 170 कोरोना योद्धाओं की मौत की बात कही गई है, लेकिन हकीकत में यह संख्या तीन सौ से ज्यादा है। सरकार को बिना भेदभाव के सभी मृत कोरोना योद्धाओं के स्वजन की आर्थिक सहायता करनी चाहिए।

रोटेशन में फंस सकते हैं दलबदल करने वाले नेता

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

2022 में होने वाले नगर निगम चुनाव में सियासी भविष्य पर असमंजस

अप्रैल 2022 में होने वाले नगर निगम चुनाव बहुत से नेताओं के सियासी भविष्य पर ग्रहण भी लगा सकते हैं। यह वे नेता हैं, जो पार्षदी पाने के फेर में इन दिनों धड़ल्ले से अपनी पार्टी छोड़ नई पार्टी का दामन थामने में लगे हैं। बेशक ये नेता दूसरी पार्टी में जाने से पहले अपनी टिकट को लेकर पक्का आश्वासन ले रहे हैं, लेकिन अगर सीट का प्रोफाइल ही बदल गया तो आश्वासन किस काम का रह जाएगा। इसके बाद न नेताजी के दावे में मजबूती रह जाएगी और न ही नई पार्टी पर वायदा निभाने का दबाव।

दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार नगर निगम चुनाव से पहले सभी 272 सीटों का रोटेशन करने का प्रविधान है। चुनाव लड़ने में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फार्मूलों के तहत रोटेशन की प्रक्रिया पर काम होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी सीट का प्रोफाइल बदल सकता है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए आरक्षित सीट इसी वर्ग में महिला के लिए आरक्षित हो सकती है, तो सामान्य श्रेणी की कोई सीट को महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

पिछली बार अप्रैल 2017 में हुए निगम चुनावों के लिए सीटों के रोटेशन की अधिसूचना छह फरवरी 2017 को प्रकाशित हुई थी। इस बार भी जनवरी 2022 में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद ही इसकी घोषणा किए जाने की संभावना है कि कौन सी सीट अपने पूर्ववर्ती स्वरूप में रहेगी और किन-किन सीटों का प्रोफाइल बदल जाएगा। इस आशय की घोषणा और अधिसूचना के बाद ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रत्याशी चयन की भूमिका को अंतिम रूप दिया जाएगा।

जानकारों की मानें तो बहुत से नेता दूसरे दलों में इसीलिए जा रहे हैं कि उस पार्टी के टिकट पर पार्षदी सुनिश्चित हो जाएगी। हालांकि, रोटेशन की यह प्रक्रिया उनके अरमानों पर पानी भी फेर सकती है। कारण, जिस पार्टी में वे लंबे समय से हैं, वहां तो रोटेशन के बाद भी उनके किसी परिजन को ही टिकट मिल सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी में इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। पार्टी बदलने की सबसे ज्यादा होड़ कांग्रेसियों में लगी है और अभी तक जो कांग्रेसी पार्टी को अलविदा कहकर गए हैं, उनमें से कई की सीट इस बार रोटेशन में बदलने वाली है।

किस नगर निगम में कितनी सीटें और कितनी आरक्षित

निगम	कुल सीटें	अनु. जाति / जनजाति	महिला	सामान्य
उत्तरी दिल्ली	104	20 (10 महिला 10 पुरुष)	42	42
दक्षिणी दिल्ली	104	15 (आठ महिला सात पुरुष)	45	44
पूर्वी दिल्ली	64	11 (छह महिला पांच पुरुष)	27	26

डीयू, जेएनयू प्रवेश परीक्षा की तारीखें घोषित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मंगलवार रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की। डीयू में सितंबर के अंतिम सप्ताह जबकि जेएनयू में सितंबर के तीसरे हफ्ते में प्रवेश परीक्षाएं होंगी।

डीयू प्रवेश परीक्षा तिथि
- 26 से 30 सितंबर तक व 1 अक्टूबर को।
- 27 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे।

डीयू पाठ्यक्रम	
पाठ्यक्रम	आवेदन की अंतिम तिथि
स्नातकोत्तर	21 अगस्त
एमफिल-पीएचडी	21 अगस्त
स्नातक	2 अगस्त से आवेदन प्रारंभ होंगे। आखिरी तिथि 31 अगस्त

डीयू प्रवेश परीक्षा
- स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दो तरीके से दाखिले होंगे।
- 50 फीसद सीटों पर प्रवेश परीक्षा से दाखिला।
- 50 फीसद सीटों पर डीयू से स्नातक करने वाले छात्रों को मेरिट आधार पर।
- स्नातक के 12 पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होगी प्रवेश परीक्षा

जेएनयू प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम
- आनलाइन पंजीकरण-27 जुलाई से 27 अगस्त (शाम पांच बजे) तक।
- फीस जमा करने की आखिरी तारीख-27 अगस्त (रात 11 बजकर 50 मिनट)
- प्रवेश परीक्षा की तारीख-20, 21, 22, 23 सितंबर।
- परीक्षा समय-180 मिनट(तीन घंटा)
- परीक्षा प्रारूप-कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट

अनलाक की तेज रफ्तार से बढ़ेगा संक्रमण का खतरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- आइसीएमआर ने दी विशेष एहतियात बरतने की सलाह

राजधानी में कोरोना भले ही काबू में है, लेकिन अनलाक की रफ्तार बढ़ने के साथ ही संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में अनलाक के तहत नियमों में छूट देने पर विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। यह सलाह इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) के विज्ञानियों ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को दी है। इसी वजह से मेट्रो में खड़े होकर सफर करने या धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने सहित अन्य मामलों में छूट फिलहाल देने से परहेज किया जा रहा है।

उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई डीडीएमए की वर्चुअल बैठक हुई थी। इसमें आइसीएमआर के विज्ञानी डा. समीरन पांडा ने सुझाव दिया कि यदि सभी सुरक्षात्मक नियमों का पालन किया जाता रहा तो कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की संभावना जरूर है, लेकिन कोई नया स्ट्रेन आता है तभी वह ज्यादा प्रभावित करेगा। अन्यथा दूसरी लहर की तुलना में कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। इससे बचने के लिए सुरक्षात्मक नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है।

डा. समीरन पांडा के अनुसार कोरोना के डेल्टा प्लस स्ट्रेन से सभी राज्य प्रभावित नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लोग इस स्ट्रेन से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है, यह नए स्ट्रेन पर निर्भर करेगा।

नीति आयोग के सदस्य डा. वी के पाल ने इस बैठक के माध्यम से दिल्ली सरकार को चेताया है कि ज्यादा अनलाक करने से कोरोना तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, अभी स्थिति नियंत्रण में है। अगले तीन महीने बेहद संवेदनशील हैं। इसलिए सतर्क रहने के साथ ही निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा। राजधानी में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी होगी व कंटेनमेंट जोन की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करना होगा। इस बीच, राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर कई दिनों के बाद बढ़कर 0.10 फीसद से अधिक हो गई है। एक दिन पहले भी संक्रमण दर 0.07 फीसद थी, जो बढ़कर 0.11 फीसद हो गई। इससे मंगलवार को कोरोना के 71 नए मामले आए।

कैदियों के टीकाकरण पर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट तलब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जेल में बंद कैदियों के टीकाकरण पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने इसके साथ ही सरकार से यह भी जानकारी देने को कहा कि समय-समय पर कैदियों की स्वास्थ्य जांच कैसे की जाती है। मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सभी कैदियों का टीकाकरण कराने की मांग को लेकर दायर दो याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ताकि जेल के अंदर कोरोना संक्रमण न फैले। याचिका दायर करने वाले जमानत या पैरोल पर बाहर थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कैदियों के टीकाकरण की ताजा स्थिति रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। दो में एक याचिका उम्रकैद की सजा काट रही 63 वर्षीय महिला ने दायर की है। उसने मांग की है कि सभी कैदियों, खासतौर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों जो जमानत, पैरोल या फरलो पर बाहर थे, उनके आत्मसमर्पण करने से पहले उनका टीकाकरण कराया जाए।

दोनों याचिकाओं में दावा किया गया है कि 14 जनवरी तक दिल्ली की तीन जेलों में 16,396 कैदी थे, जबकि जेलों की क्षमता 10 हजार के करीब है, ऐसे में वहां शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो सकता है।

सावन में उत्तरी निगमकर्मियों पर राहत की बरसात

निहाल सिंह, नई दिल्ली

- निगम के 57 हजार कर्मचारियों को मिला पूरा बकाया वेतन
- संपत्ति कर से हुई आय से दूर हुआ कर्मियों का वेतन संकट

इस सावन उत्तरी निगमकर्मियों पर भी राहत की बारिश हुई है। चार साल बाद पहला मौका आया है, जब उत्तरी निगम के 57 हजार कर्मचारियों का एक भी माह का वेतन बकाया नहीं है। अन्यथा उनके साथ अधिकारियों का भी पांच माह तक का वेतन बकाया रहता था। इसी तरह निगम ने मई माह तक की पेंशन भी जारी कर दी है।

निगम के मुताबिक संपत्ति कर के रूप में इस वर्ष अब तक करीब 400 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए निगम की उपलब्धि है। निगम ने इस पूरी राशि को वेतन में दे दिया है। वहीं, हाल ही में दिल्ली सरकार से भी 293 करोड़ रुपये का अनुदान मिला, जिससे भी वेतन चुकाने में मदद मिली। उल्लेखनीय है कि 2017 से निगम खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। 2017 में वेतन भुगतान में देरी दो से तीन माह की थी, जो 2018, 2019 व 2020 में पांच माह तक बढ़ गई।

उल्लेखनीय है कि निगम कर्मियों के वेतन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट इसे लेकर निगम अधिकारियों को कई बार कड़ी फटकार लगाते हुए उन्हें निगम की संपत्तियां बेचकर वेतन देने की बात कह चुका है। दिल्ली सरकार को भी अनुदान जारी करने को लेकर समय-समय पर आदेश दिए हैं।

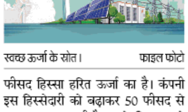
... तो हरित ऊर्जा से रोशन होगी दिल्ली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

- अगले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा, पवन चक्की और जल विद्युत संयंत्रों से 33 सौ मेगावाट बिजली खरीदेगी बीएसईएस
- कार्बन उत्सर्जन में आएगी कमी, पर्यावरण संरक्षण के साथ उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद

बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही हैं। कोयला आधारित संयंत्रों से बिजली खरीदने के बजाय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो संयंत्रों से बिजली खरीदने को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ ही उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसे ध्यान में रखकर बीएसईएस पुराने कोयला आधारित संयंत्रों के साथ किए गए लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते को खत्म करना चाहती है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पुराने संयंत्रों से समझौते खत्म करने के साथ ही अगले तीन वर्षों में कंपनी कुल बिजली में से 52 फीसद हरित ऊर्जा खरीदने की तैयारी में है।

बिजली अधिकारियों के अनुसार, इस समय बीएसईएस के पास लंबी अवधि वाले बिजली खरीद समझौतों में से 23 फीसद हिस्सा हरित ऊर्जा का है। कंपनी इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50 फीसद से ज्यादा करना चाहती है। इसके लिए अगले ढाई से तीन वर्षों में 33 सौ मेगावाट हरित ऊर्जा खरीदने का लक्ष्य है। इसमें से 2291 मेगावाट सौर ऊर्जा, पवन चक्की व कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्रों से मिलेगी। वहीं, लगभग एक हजार मेगावाट बिजली जल विद्युत संयंत्रों से मिलेगी। कुछ दिनों पहले कंपनी ने सोलर एनर्जी कारपोरेशन आफ इंडिया (सेकी) के साथ समझौता किया है, जिससे उसे लगभग ढाई रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 510 मेगावाट अक्षय ऊर्जा मिलेगी।



स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत। फाइल फोटो

हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी और पर्यावरण बेहतर बनेगा। बिजली अधिकारियों के मुताबिक बीएसईएस को कुल 33 सौ मेगावाट हरित ऊर्जा मिलने से कार्बन उत्सर्जन में 70 लाख टन की कमी आने की संभावना है। उनका कहना है पुराने कोयला संयंत्रों से छह रुपये प्रति यूनिट या इससे भी ज्यादा महंगी पड़ती है। हरित ऊर्जा लगभग ढाई से तीन रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिलेगी जिससे दिल्ली के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

हाई कोर्ट ने खारिज की आइएमए अध्यक्ष की चुनौती याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- निचली अदालत के आदेश और टिप्पणियों को खारिज करने की थी मांग

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के अध्यक्ष जेए जयलाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने किसी भी धर्म का प्रचार करने के लिए आइएमए का उपयोग नहीं करने संबंधी निचली अदालत की टिप्पणी को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने कहा कि निचली अदालत के आदेश में ऐसा कोई भी तथ्य गलत नहीं है, जिससे याचिकाकर्ता प्रभावित होता हो। निचली अदालत ने जयलाल से कहा था कि एक जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति से स्तरहीन टिप्पणियों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही निचली अदालत ने जयलाल को नसीहत दी थी कि वे आइएमए जैसी संस्था को किसी धर्म विशेष के प्रचार के प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं करें। निचली अदालत ने यह आदेश रोहित झा की तरफ से दी गई शिकायत की सुनवाई के आधार पर दिया था। रोहित ने आरोप लगाया था कि आइएमए अध्यक्ष कोरोना के उपचार में आयुर्वेद की अपेक्षा एलोपैथी को बेहतर साबित करने की आड़ में ईसाई धर्म प्रचार कर रहे हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ अपमानजनक अभियान चला रहे हैं।

निचली अदालत में जयलाल ने माफी मांग ली थी, लेकिन बाद में यह कहते हुए चुनौती याचिका दायर की थी कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और न ही उन्होंने माफी मांगी है, ऐसे में निचली अदालत के आदेश और टिप्पणियों को खारिज किया जाए।

9,712 पद खाली हैं सशस्त्र बलों में अधिकारियों के। इसी प्रकार सैनिक, एयरमेन व सेलर के 1.09 लाख पदों पर भर्तियां बाकी हैं। यह जानकारी राज्यसभा में रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने दी।

सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी बढ़ी

पेगासस जासूसी कांड ▸ भारी हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चली

सात विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को भेजा पत्र, पेगासस व किसानों के मुद्दे पर की बहस कराने की मांग

- विपक्ष के हंगामे के चलते नौ बार बाधित हुई लोकसभा की कार्यवाही, 10वीं बार उसे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया
- सात विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, पेगासस और किसानों के मुद्दे पर सरकार को बहस कराने का निर्देश देने का आग्रह
- राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने पर विपक्षी दलों ने किया हंगामा, आसन के सामने आकर नारेबाजी की

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली


पेगासस जासूसी कांड और कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। एएनआइ

संसद में पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और विपक्ष का घमासान अब तनातनी की ओर बढ़ गया है। मानसून सत्र के छठे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष के भारी हंगामे के कारण कामकाज नहीं हुआ। भारी शोर-शराबे और नारेबाजी के चलते लोकसभा की कार्यवाही 10 बार स्थगित हुई। दोनों सदनों में गतिरोध के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने हंगामे पर विपक्षी दलों को फटकार लगाई।

लोकसभा में सुबह कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने किसी तरह करीब आधे घंटे तक प्रश्नकाल की कार्यवाही चलाई, इसे भी दो बार स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पीकर के आसन के सामने पोस्टर-बैनर लिए हंगामा कर रहे कांग्रेस, टीएमसी, द्रमुक, सपा, बसपा, माकपा सरीखे दलों के सदस्यों पर निशाना साधते हुए उन पर मंत्रियों को सदन में जवाब देने से रोकने का आरोप लगाया।

स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को हंगामा करने पर नसीहत देते हुए कहा कि उनका व्यवहार पूरा देश देख रहा है और यह तरीका उचित नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष पर राजनीतिक मकसद से सदन को ठप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर वह चर्चा चाहता है तो प्रश्नकाल चलने देना चाहिए क्योंकि किसानों से जुड़े कई सवाल हैं। लेकिन विपक्षी सदस्य किसानों व जासूसी के मुद्दे पर आक्रामक रवैया छोड़ने को तैयार नहीं हुए जिस पर सदन 12 बजे के बाद तीसरी बार स्थगित हुआ। दोपहर 12.30 बजे और दो बजे भी यही कहानी दोहरायी गई। इसके बाद तो हर आधे-आधे घंटे के अंतराल पर कुल मिलाकर पूरे दिन लोकसभा की कार्यवाही नौ बार हंगामे की वजह से स्थगित हुई और शाम 4.30 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

दो कांग्रेस सदस्यों ने दिया धरना : सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद किसानों के समर्थन में पंजाब से कांग्रेस के दो सांसदों रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह औजाला लोकसभा चैंबर में ही धरने पर बैठक गए। करीब चार घंटे बाद लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों के अनुरोध पर दोनों ने धरना खत्म किया।

विधायी कामकाज कराने के खिलाफ विपक्ष की रणनीति : विपक्ष के आक्रामक तेवरों और हंगामे के बावजूद सरकार के जरूरी विधायी कामकाज को शोर-शराबे में ही करा लेने की रणनीति को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सुप्रिया सुले, टीआर बालू, कनीमोरी सरीखे सात विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। इसमें राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को पत्र भेजने का फैसला किया गया।

सभापति ने विपक्ष दलों को लगाई फटकार : राज्यसभा में भी सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही विपक्ष ने पेगासस जासूसी कांड व किसानों के आंदोलन पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस का हवाला देते हुए चर्चा की मांग की। सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। सभापति ने हंगामा कर रहे विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग पूरे सत्र को नहीं चलने देना चाहते। हंगामा करने वाले सदस्य देश का अहित कर रहे हैं। बार-बार व्यवधान के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी आखिरकार पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष का सरकार पर हमला : सभापति की तीखी टिप्पणियों के बाद नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के आनंद शर्मा, टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय, सपा के रामगोपाल यादव, माकपा के विनय विस्वम, द्रमुक के त्रिची शिवा समेत दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी सरकार और आसन पर आक्रामक जवाबी हमला बोला।

पीएम से पेगासस पर सर्वदलीय बुलाने की मांग : खड़गे ने कहा कि पेगासस पर दुनिया के कई देशों में जांच हो रही है तो हमारे यहां क्यों नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को इस मामले में सभी दलों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए। खड़गे ने नायडू की टिप्पणियों को गैरवाजिब ठहराया।

...नरेश गोयल, अजय सिंह के भी थे नाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेगासस के संभावित लक्ष्यों में जेट एयरवेज के पूर्व अध्यक्ष नरेश गोयल, स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह और एस्सार ग्रुप के प्रशांत रूइया के नाम शामिल थे। एक न्यूज वेबसाइट की तरफ से जारी नई सूची से यह जानकारी सामने आई है। लीक सूची के मुताबिक गेल इंडिया के पूर्व प्रमुख बीसी त्रिपाठी भी संभावित निगरानी वाले लक्ष्यों में शामिल थे। इस सूची में रोटोमैक पेंस के विक्रम कोठारी, उनके बेटे राहुल और एयरसेल के पूर्व प्रवर्तक सी शिवशंकरन भी शामिल हैं।

वेबसाइट की रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी निजी कंपनियों में काम करने वाले कम से कम तीन अधिकारियों के नाम भी सूची में शामिल थे। संभावित निगरानी लक्ष्यों में अदाणी समूह के मध्यम स्तर के अधिकारी, एस्सार समूह के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति और स्पाइसजेट के साथ पूर्व में रह चुके एक व्यक्ति शामिल थे।

वेबसाइट के मुताबिक लंबे समय तक रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े रहे वी बालसुब्रमण्यम और रिलायंस एडीए ग्रुप के एन सेतुरमन संभावित जासूसी लक्ष्यों में शामिल थे। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के एक पूर्व प्रमुख और गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक निगम के एक पूर्व कार्यकारी निदेशक के नंबर भी सूची में दिखे हैं। लीक सूची में भारत के म्युचुअल फंड उद्योग से जुड़े कम से कम पांच कारपोरेट अधिकारियों के नंबर भी शामिल हैं, जिनमें फ्रैंकलिन टेम्पलटन, डीएसपी ब्लैकराक और मोतीलाल ओसवाल जैसी कंपनियों के पेशेवर शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : वरिष्ठ पत्रकार एन राम व शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पेगासस के जरिये सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं व पत्रकारों की जासूसी किए जाने संबंधी खबरों की शीर्ष अदालत के किसी वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जाए। याचिका पर कुछ दिन में सुनवाई हो सकती है। याचिका में इस बात की जांच करने का अनुरोध किया गया है कि क्या पेगासस स्पाइवेयर के जरिये फोन को हैक कर एजेंसियों ने भारत में स्वतंत्र भाषण और असहमति को अभिव्यक्त करने से रोकने का प्रयास किया। याचिका में केंद्र को यह बताने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि क्या सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने पेगासस स्पाइवेयर के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है और क्या उन्होंने इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी करने के लिए किया है।

संसद प्रश्नोत्तर

सीएए नियम तैयार करने के लिए नौ जनवरी तक का समय लिया

▸ केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा की समिति ने समय बढ़ाने का आग्रह किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियम तैयार करने के लिए नौ जनवरी तक का समय मांगा है। इस अधिनियम को संसद ने 2019 में ही पारित कर दिया था। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी दी। वह कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई के सवालों का जवाब दे रहे थे। कांग्रेस सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार सीएए नियम तैयार और अधिसूचित करने के साथ ही इस दिशा में कदम उठाने की समयसीमा भूल गई है। राय ने कहा, 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 12-12-2019 को अधिसूचित किया जा चुका है व 10 जनवरी, 2020 से लागू हो गया है। अधीनस्थ कानून पर लोकसभा व राज्यसभा की समिति ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नियम तैयार करने के लिए नौ जनवरी, 2022 तक समय बढ़ाने का आग्रह किया है।'

यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज नाम जाहिर करना जनहित में नहीं : गृह राज्यमंत्री ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं उनके नाम जाहिर करना व्यापक जनहित में नहीं होगा और इससे मामले पर प्रभाव पड़ सकता है। एक लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत नौ मामले दर्ज किए गए और 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

पांच वर्षों में अर्धसैनिक बलों के 355 जवानों की ड्यूटी के दौरान जान गई : राय ने कहा कि पिछले पांच साल में ड्यूटी के दौरान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स के 355 जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि 2016-2020 के दौरान ड्यूटी करते हुए जिन 355 जवानों ने जान गंवाई उनमें सबसे अधिक 209 जवान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के थे। बीएसएफ के 78, आइटीबीपी के 16, सशस्त्र सीमा बल के आठ, सीआइएसएफ के सात और असम राइफल्स के 37 जवान शामिल हैं।

कोरोना के कारण जनगणना संबंधी जमीनी गतिविधियां स्थगित : एक लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना 2021 संबंधी जमीनी गतिविधियां स्थगित हैं। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रविधानों के तहत दो चरणों में जनगणना 2021 की जानी थी। अप्रैल-सितंबर 2020 में आवास सूचीबद्ध करना और आवासीय जनगणना की जानी थी और आबादी की गणना का काम नौ से 28 फरवरी, 2021 के दौरान किया जाना था।

2013 में हुई थी राष्ट्रीय एकता परिषद की पिछली बैठक : एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राय ने कहा कि राष्ट्रीय एकता परिषद (एनआइसी) की पिछली बैठक 2013 में हुई थी। एनआइसी का लक्ष्य विविधता में एकता, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, बराबरी, न्याय-सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक और सभी समुदायों के बीच भाईचारा हासिल करना है।

म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र ने परामर्श जारी किया : म्यांमार से भारत में होने वाली घुसपैठ रोकने पर एक सवाल के लिखित उत्तर में गृह राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड की राज्य सरकारों को 10 मार्च को जारी परामर्श में म्यांमार से घुसपैठ रोकने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है। लोकसभा में एसआर पार्थिबन और रवनीत सिंह ने इस संबंध में सवाल किया था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विज्ञापन पर खर्च में आई कमी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों पर सरकार की ओर से किया जाने वाला खर्च कम हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2020-2021 में प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर सरकार की व्यय राशि 197.49 करोड़ रुपये थी। इससे पहले 2019-2020 में प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों पर 295.05 करोड़ रुपये और 2018-2019 में 429.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 2018-2019 में इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों पर सरकार ने 514.29 करोड़ रुपये खर्च किए। वर्ष 2019-2020 में सरकार की ओर से इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया में विज्ञापनों पर 316.99 करोड़ रुपये और 2020-2021 में 167.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

'फर्जी कोविड जांच मामले में राज्यों से मांगा गया ब्योरा'

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वास्थ्य मंत्रालय ने फर्जी कोविड जांच मामले में राज्यों से ब्योरा मांगा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में रास को बताया कि उत्तराखंड ने फर्जी कोविड जांच के कुछ प्रकरण की सूचना दी थी। मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ निजी कंपनियां फर्जी कोविड जांच में लिप्त पाई गई हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। मंत्रालय से उन राज्यों का विस्तृत ब्योरा मांगा गया था, जहां पर इस प्रकार के मामले हुए हैं।

पवार के अनुसार, उत्तराखंड ने बताया है कि इस मामले में संलिप्त कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मंत्रालय ने कहा कि सभी संलिप्त प्रयोगशालाओं की जांच की जा रही है। उन्हें आगे कोविड जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है। उनका भुगतान भी फिलहाल रोक दिया गया है।

केंद्र ने माना, अपने संगठनों में बच्चों की भर्ती कर रहे नक्सली

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में स्वीकार किया कि नक्सली अपने संगठनों में बच्चों की भर्ती कर रहे हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में दैनिक गतिविधियों के अलावा सैन्य प्रशिक्षण में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सली बच्चों को अपने संगठनों में शामिल कर खाना बनाने, दैनिक उपयोग की सामग्री ले जाने व सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में जानकारी एकत्र करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। इसलिए राज्य सरकारें ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करती हैं। समाचार एजेंसी प्रेट्र के अनुसार, राय ने लोकसभा को बताया कि 2018 में वामपंथी उग्रवाद की 833 घटनाएं हुई थीं। यह 2019 में घटकर 670 और पिछले साल 665 रह गईं।

प्रधानमंत्री से ममता ने मांगी बंगाल के लिए और वैक्सीन


बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ कहा, राज्य को आबादी के अनुपात में कम संख्या में मिले हैं टीके

▸ बंगाल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का भी किया अनुरोध

राजनीतिक कड़वाहट को किनारे रखते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में जीत के करीब तीन महीने बाद पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दीदी ने कोरोना की चुनौतियों के साथ सूबे को आबादी के अनुपात में टीका मुहैया कराने का पीएम से अनुरोध किया। साथ ही बंगाल का नाम बदलने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने पेगासस विवाद पर भले ही चर्चा नहीं की, लेकिन पीएम से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में इस प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग का समर्थन किया।

बंगाल चुनाव के बाद मोदी से हुई पहली मुलाकात पर ममता ने कहा कि इस बैठक में उन्होंने सूबे के विकास और परियोजनाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही कोरोना संकट से लड़ने पर भी बातचीत की गई। उन्होंने पीएम से कहा कि बंगाल को आबादी के अनुपात में कोरोना की वैक्सीन कम संख्या में मिली है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। बंगाल का नाम बदलने के लंबित प्रस्ताव पर ममता ने कहा कि हमने पीएम से इस पर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया। पीएम की इस पर प्रतिक्रिया क्या रही? यह पूछे जाने पर दीदी ने बताया, पीएम ने कहा कि हम देखेंगे।

ममता विस चुनाव के कुछ ही दिनों बाद बंगाल में चक्रवात का जायजा लेने गए पीएम से संक्षिप्त रूप से रूबरू हुई थीं। तब सियासी तल्खी के चलते अपना ज्ञापन सौंपकर पीएम की बैठक से चली गई थीं। हालांकि मंगलवार को मोदी से मुलाकात और उनसे हुई बातचीत को लेकर दीदी ने वैसी कुछ तल्खी नहीं दिखाई। ममता ने कहा कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से गुरुवार को मुलाकात का समय मिला है। लेकिन कोरोना का दोनों टीका लगवाने के बावजूद राष्ट्रपति भवन ने मिलने से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के लिए कहा है। उन्होंने कहा, इसमें मुझे कुछ समस्या है और इस वजह से वे राष्ट्रपति से मौजूदा दौरे में मिलने नहीं जा पाएंगी।

भारत–अमेरिका रिश्तों को नई दिशा देगी जयशंकर–ब्लिंकन वार्ता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ पहली भारत यात्रा पर मंगलवार देर शाम नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री

▸ बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से होगी वार्ता


नई दिल्ली में मंगलवार को हवाई अड्डे पर विमान से उतरते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। प्रेट्र

अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ उसके रिश्तों में कोई बड़े बदलाव की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 2024 तक द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा कैसी होगी, इसे तय करने में बुधवार (28 जुलाई) को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच की बैठक अहम होगी। बतौर विदेश मंत्री ब्लिंकन पहली भारत यात्रा पर मंगलवार देर शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनके भारत में कदम रखने के साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय रिश्तों पर एक बयान जारी किया जिसमें भारत को एक मजबूत रणनीतिक साझीदार बताया गया है।

ब्लिंकन की पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात होने वाली है। वह पीएम मोदी को राष्ट्रपति जो बाइडन का संदेश देंगे जो खास तौर पर क्वाड देशों (भारत, अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया) के प्रमुखों की बैठक से संबंधित होगा। इन नेताओं के बीच सितंबर, 2021 में होनेवाली बैठक को लेकर दोनों देशों के बीच संपर्क जारी है। भारत व अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी क्वाड से जुड़े मुद्दे काफी अहम रहने वाले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को पूरी तरह से मुक्त व सभी के लिए समान अवसर वाला बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। भारत को एक बड़ी वैश्विक शक्ति बताते हुए कहा गया कि कोविड-19 से जुड़े मामले व महामारी से निपटने को लेकर सहयोग का मुद्दा भी बातचीत में काफी महत्वपूर्ण होगा।

मोदी-बाइडन के बीच बैठक को लेकर तैयार होगी जमीन : सूत्रों का कहना है कि दोनों देशों के बीच लगातार उच्चस्तरीय व कई स्तरों पर संपर्क का सिलसिला जारी रहेगा। ब्लिंकन की यात्रा के बाद अमेरिकी सेना के स्पेशल आपरेशंस कमांड के कमांडर जनरल रिचर्ड डी क्लार्क भारत आ रहे हैं। इसके बाद अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिकी सेना प्रमुख जेम्स मैककोनविले भारत आएंगे। इन तीनों यात्राओं से दोनों देशों के बीच होने वाली आगामी टू प्लस टू (रक्षा व विदेश मंत्रियों की) वार्ता की जमीन तैयार होगी। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडन के बीच की पहली आमने-सामने मुलाकात को लेकर अभी कोई तिथि तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्ष जल्द से जल्द इसे होते देखना चाहते हैं। सनद रहे कि देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी समूह-20 बैठक में हिस्सा लेने ब्रिटेन नहीं जा सके जिससे उनकी बाइडन से मुलाकात नहीं हो सकी थी।

बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा : जयशंकर और ब्लिंकन के बीच बैठक में क्षेत्रीय मुद्दे भी उठेंगे। दोनों पक्षों की तरफ से बताया गया कि अफगानिस्तान की स्थिति एक बड़ा मुद्दा होगा। साथ ही चीन व भारत के बीच सैन्य तनाव का मुद्दा भी उठने की संभावना है। अमेरिकी पक्ष रक्षा मुद्दों को लेकर ज्यादा जोर दे रहा है। इस बात का प्रमाण उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान है। अमेरिका ने हाल के वर्षों में भारत को 20 अरब डालर की सैन्य सामग्रियों की बिक्री को हरी झंडी दिखाई है। दोनों देशों के बीच कई रक्षा उपकरणों को साथ मिलकर विकसित करने और उनका निर्माण करने पर भी बात हो रही है। इसके अलावा इस बैठक में भारत की तरफ से वैक्सीन निर्माण में जरूरी अमेरिकी कच्चे माल का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ मिलकर दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने की रणनीति पर भी बात होगी।

सहकार से समृद्धि

प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचे से लैस होगा नया मंत्रालय, नए मंत्रालय को मिल सकते हैं चार से पांच संयुक्त सचिव, सहकारी आंदोलन को मिलेगा बल, बढ़ेंगे रोजगार के मौके

सहकारिता मंत्रालय के गठन की तैयारियां पूरी

सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

सहकारिता मंत्रालय के गठन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अलग मंत्रालय बनाने की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अंतिम दौर में है। गंभीर विचार-विमर्श के बाद तैयार कैबिनेट मसौदा वितरित हो चुका है, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को होने वाली बैठक में मुहर लग जाने की संभावना है। सहकारी क्षेत्र में प्राइमरी सोसायटी से लेकर मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए प्रस्तावित नवगठित मंत्रालय में चार से पांच संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है।

नवगठित मंत्रालय में तीन अहम सेक्शन बनेंगे, जिनकी जिम्मेदारी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी जा सकती है। अब तक सहकारिता विभाग कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक तौर पर उपेक्षित तरीके से काम करता था। इसके लिए कोई संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तक नियुक्त नहीं होता था, लेकिन सरकार ने इस विभाग की अहमियत को भांपते हुए नया सहकारिता मंत्रालय बनाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के फैसले की घोषणा संसद में की जा सकती है।

सूत्रों के मुताबिक सहकारिता मंत्रालय के कैबिनेट नोट पर अन्य सभी मंत्रालयों की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं। इसे बुधवार को कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। नया मंत्रालय बन जाने के बाद सहकारिता क्षेत्र को प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध हो जाएगा, जिससे सहकारी आंदोलन को बल मिलेगा।

इससे समाज के निचले स्तर तक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार व अनियमितता को दुरुस्त किया जा सकेगा। सहकारी आंदोलन के सहारे गांव, गरीब, किसान, बुनकर, मछुआरों और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया जा सकेगा।

नए सहकारिता मंत्रालय का गठन कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय की तर्ज पर किया जाएगा। देश में फिलहाल आठ लाख सहकारी संस्थाओं के लगभग 40 करोड़ सदस्य होने का दावा किया जाता है, जिसमें समाज के निचले तबके और जरूरतमंद लोगों की संख्या ज्यादा है। नए मंत्रालय के दायरे में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सेंट्रल रजिस्ट्रार, सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण के साथ प्रमोशन आफ कोआपरेशन जैसे विषय प्रमुख होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 हजार से अधिक सहकारी बैंकों की शाखाएं काम कर रही हैं, लेकिन इन बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें अपने दायरे में ले लिया है।

देश के लाखों महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी करोड़ों महिलाओं को सहकारिता मंत्रालय के गठन का लाभ मिलेगा। बुनकर, मछुआरे, डेयरी क्षेत्र, हाउसिंग, लेबर, हेल्थ व बीमा क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं आगे बढ़कर काम कर पाएंगी। युवाओं के शिक्षण व प्रशिक्षण की सख्त जरूरत है, जो अब पूरी होगी, जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

स्वदेश दर्शन योजना में शामिल है रामायण सर्किट : रेड्डी

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन योजना की थीम आधारित सर्किट में शुमार है। इसके अलावा मंत्रालय ने बौद्ध, तीर्थंकर, कृष्ण व अध्यात्म सर्किट के तहत परियोजनाओं का आवंटन किया है।

रेड्डी ने लिखित जवाब में कहा, 'पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित सर्किटों में शुमार रामायण सर्किट के लिए दो परियोजनाओं का आवंटन किया गया है।' उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान का राष्ट्रीय मिशन (प्रसाद) योजना के तहत राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को चिह्नित पर्यटन व धरोहर स्थलों के एकीकृत विकास के लिए वित्तीय मदद भी मुहैया करा रहा है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी



मैं मौसम विभाग से हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मेरी बातों पर यकीन न करें!

40 करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से उत्तराखंड सरकार को। ऊर्जा के तीनों निगमों में एक दिन की हड़ताल ने सरकार और उपभोक्ताओं को हलकान किया।

ममता को उम्मीद, विपक्षी एकता समय पर लेगी स्वरूप

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कांग्रेस नेताओं कमल नाथ, आनंद शर्मा और सिंघवी से मिलकर दीदी ने शुरू किया संवाद का सिलसिला
- सोनिया गांधी से आज चाय पर चर्चा करेंगी ममता, पवार से भी होगी मुलाकात

बंगाल में लगातार तीसरी धमाकेदार जीत के बाद विपक्षी गोलबंदी को गति देने पहली बार दिल्ली आईं ममता बनर्जी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कमल नाथ और आनंद शर्मा के साथ मुलाकात कर विपक्षी खेमे के नेताओं के साथ संवाद का सिलसिला शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ विपक्ष को साथ लाने की पहल शुरू कर रहीं ममता ने कहा है कि समय आने पर विपक्षी एकता अपने आप ठोस स्वरूप ले लेगी। इस पहल के तहत ममता बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चाय पर चर्चा करने के अलावा राकांपा नेता शरद पवार समेत विपक्ष के कुछ अन्य प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर भाजपा के खिलाफ गोलबंदी की संभावना तलाशेंगी।

विपक्षी नेताओं से मुलाकातों का दौर शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग का मुखर समर्थन कर इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ आने का संदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट



बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ से मुलाकात की। प्रेट्र

की निगरानी में सबसे पहले जांच की मांग करने वाली कांग्रेस के लिए ममता का यह रुख राहत देने वाला है। वैसे दीदी ने विपक्षी नेताओं से मेल-मुलाकातों का सिलसिला कांग्रेस के दिग्गज कमल नाथ से मिलकर शुरू किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ममता से मिलने उनके आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच लगभग एक घंटे चर्चा हुई। मुलाकात के बाद कमल नाथ ने कहा कि वे ममता को जीत की बधाई देने गए थे। विपक्षी राजनीति के भावी स्वरूप पर चर्चा के संदर्भ में कमल नाथ ने कहा कि इस बारे में उनकी बातचीत नहीं हुई और हमारी पार्टी का नेतृत्व इस बारे में चर्चा करेगा।

ममता ने इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा से लगभग एक घंटे की बातचीत की। दीदी ने शर्मा और कमल नाथ से मुलाकातों पर कहा कि इनसे दोस्ताना ताल्लुक रहा है। आनंद शर्मा ने भी इस मुलाकात के बारे में कहा कि ममता बनर्जी से उनकी पुरानी मित्रता रही है और जब वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब वे उनकी महामंत्री थीं। साथ ही कैबिनेट में भी दोनों सहयोगी रहे हैं। भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के उनके प्रयासों के संदर्भ में शर्मा ने कहा कि यह समय की मांग है। बंगाल में संवैधानिक व लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिस तरह से भाजपा और केंद्र सरकार ने चुनाव में प्रहार किया उसे देखते हुए ममता की जीत से देश को नई दिशा मिली है। दीदी ने इसके बाद शाम को कांग्रेस के नेता वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से मुलाकात की।

कांग्रेस अध्यक्ष से बुधवार को होने वाली अपनी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें चाय पर आमंत्रित किया है। सोनिया गांधी से 10 जनपथ पर होने वाली यह मुलाकात विपक्षी सियासत को 2024 में नई दिशा देने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ममता ने इसका संकेत देते हुए कहा कि सोनिया से चाय के दौरान उनकी अहम चर्चा भी होगी। दीदी राकांपा प्रमुख शरद पवार से भी बुधवार को मिलेंगी। पांच दिनों के राजधानी प्रवास पर आईं ममता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई दूसरे विपक्षी नेताओं से भी इस दौरान मुलाकात कर विपक्षी गोलबंदी की अपनी पहल का आधार मजबूत करने की कोशिश करेंगी।

तीसरे मोर्चे के लिए चौटाला ने संभाली कमान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला ने विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं को जोड़कर थर्ड फ्रंट (तीसरा मोर्चा) गठित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए चौटाला विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने विभिन्न राज्यों के दौरे पर निकलेंगे। चौटाला की कोशिश है कि तीसरे मोर्चे के गठन का एलान पूर्व उपप्रधानमंत्री स्व. देवीलाल के जन्म दिवस पर 25 सितंबर को होने वाली राज्य स्तरीय रैली में कर दिया जाए। माना जा रहा है कि चौटाला यह रैली जींद, सिरसा, हिसार अथवा गुरुग्राम में कहीं कर सकते हैं।

जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में सजा पूरी कर लौटे चौटाला ने भाजपा के विरुद्ध तीसरे मोर्चे के गठन की जरूरत बताते हुए जनता दल (यू) महासचिव केसी त्यागी से करीब दो घंटे तक गुरुग्राम में मंत्रणा की। केसी त्यागी इनेलो प्रमुख का हालचाल पूछने आए थे। वहीं पर त्यागी



एक अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चौटाला साथ करेंगे लंच

ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चौटाला की फोन पर बात कराई। अब नीतीश कुमार एक अगस्त को चौटाला के साथ दिल्ली में उनके आवास पर लंच करने आ रहे हैं। उस दिन भी तीसरे मोर्चे के प्रारूप पर ठोस मंत्रणा संभव है।

चौटाला तीसरे मोर्चे के गठन की मंशा से ही अपने पुराने मित्र प्रकाश सिंह बादल, शरद पवार, ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव समेत करीब एक दर्जन बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से चौटाला अपने पारिवारिक रिश्ते बताते हैं। मुलायम सिंह यादव से भी उनकी अच्छी बनती है। मुलायम के बेटे अखिलेश यादव और प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल से चौटाला के बेटे अभय के अच्छे संबंध हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात भी चौटाला के एजेंडे में शामिल है।

चौटाला अपने पिता स्व. देवीलाल की जयंती पर हरियाणा में बड़ी राजनीतिक रैली कर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने वाले हैं। कई बार ऐसे मौके आए, जब इनेलो को संघर्ष के दौर का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार पार्टी फिर से मजबूती के साथ खड़ी दिखाई दी। चौटाला की रणनीति भाजपा विरोधी सभी दलों को ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस कार्यक्रम के मंच पर लाकर उनकी मौजूदगी में थर्ड फ्रंट का एलान कराने की है। पहले भी ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाली रैलियों में उनके पुराने साथी शामिल होते रहे हैं। कांग्रेस इस फ्रंट का हिस्सा होगी या नहीं? इस सवाल पर चौटाला कहते हैं कि हर उस राजनीतिक दल के लिए इस फ्रंट में दरवाजे खुले हैं, जो भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं।

कमल नाथ को उनके घर में घेरेगी भाजपा, नकुल नाथ की भी बढ़ेगी मुश्किल

नईदुनिया राज्य ब्यूरो, भोपाल : मध्य प्रदेश में भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की राजनीतिक घेराबंदी शुरू कर दी है। यह घेराबंदी खासतौर पर उनके गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में सिंधिया छिंदवाड़ा आएंगे। भाजपा की घेराबंदी से कमल नाथ के पुत्र और सांसद नकुल नाथ की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस रणनीति के पीछे 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव की भाजपा की तैयारी को मजबूत स्वरूप देना है।

प्रदेश कांग्रेस और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर बदलाव की चर्चा के बीच भाजपा ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। छिंदवाड़ा में सिंधिया कमल नाथ की नीतियों को लेकर हमलावर रहेंगे।

सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की ओर से क्षेत्रों का अघोषित बंटवारा है। छिंदवाड़ा में कमल नाथ और नकुल नाथ तो गुना और राघौगढ़ क्षेत्र में राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह और उनके बेटे राजवर्धन सिंह के कार्यों में पार्टी हस्तक्षेप नहीं करती है।

कांग्रेस में रहते हुए सिंधिया लंबे समय तक छिंदवाड़ा नहीं गए थे। अब पार्टी संगठन की ओर से सिंधिया के ऐसे कार्यक्रम तय किए गए हैं कि वह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे को भी प्रभावित करें।

कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे बासवराज बोम्मई

केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में चुने गए पार्टी विधायक दल के नेता

निवर्तमान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने रखा नाम का प्रस्ताव, बुधवार को लेंगे शपथ

बेंगलुरु, आइएएनएसः बासवराज सोमप्पा बोम्मई कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। एक निजी होटल में आयोजित विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। वह उत्तरी कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं और लिंगायत समुदाय के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। वह बुधवार को 30वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उनके नाम का प्रस्ताव निवर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने किया। बोम्मई येदियुरप्पा की सरकार में गृह, कानून और संसदीय मामलों के विभाग का कामकाज संभाल चुके हैं। वह जल संसाधन और सहकारिता विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल नेता एसआर बोम्मई के पुत्र बासवराज का जन्म 28 जनवरी, 1960 को हुआ था। वह मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ ही पेशे से किसान और उद्यमी भी हैं। उन्होंने



बेंगलुरु में मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (बाएं से तीसरे) की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक में बासवराज सोमप्पा बोम्मई (बाएं से दूसरे) को नेता चुना गया। इस मौके पर निवर्तमान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (बाएं) भी मौजूद रहे। प्रेट्र

अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की थी। वह धारवाड़ से 1998 और 2004 में विधायक चुने गए। फरवरी 2008 में भाजपा में शामिल हुए। जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने तो वे हावेरी जिले के शिगांव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए।

प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं की अच्छी जानकारी होने के साथ ही उन्होंने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है। इसके लिए उनकी काफी सराहना भी की जाती है। इतना ही नहीं उन्हें शिगांव में भारत की पहली 100 फीसद पाइप सिंचाई परियोजना को लागू करने का श्रेय भी दिया जाता है। बोम्मई को येदियुरप्पा का करीबी जरूर माना जाता है, लेकिन जब निवर्तमान मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ी थी तो वह उनके साथ नहीं गए थे। हालांकि जब वह पार्टी में वापस आए तो उन्होंने येदियुरप्पा का एक बार फिर विश्वास हासिल कर लिया। पार्टी और सरकार का विभिन्न मंचों पर बचाव करने के चलते बोम्मई येदियुरप्पा के पसंदीदा व्यक्ति रहे हैं। बोम्मई को कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने बधाई दी है।

सिद्धू ने उठाए पांच मुद्दे, कैप्टन बोले– यह पहले ही एजेंडे में

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की हुई पहली बैठक

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मंगलवार को सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यलय में पहली बैठक हुई। सिद्धू चारों कार्यकारी अध्यक्षों को साथ लेकर कैप्टन से मिले और मुख्यमंत्री को पांच मुद्दों पर आधारित एक ज्ञापन सौंपा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सारे मुद्दे पहले से ही सरकार के एजेंडे में हैं और इन पर काम किया जा रहा है।

बैठक के बाद सिद्धू ने ज्ञापन की प्रति अपने ट्विटर एकाउंट पर भी शेयर की। यह वही मुद्दे हैं जिनका जिक्र सिद्धू ने अपने ताजपोशी समारोह में किया था। सिद्धू ने बेअदबी और कोटकपूरा व बहबलकलां गोलीकांड मामलों के दोषियों को सजा दिलाने, बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई करने की मांग की। तीनों कृषि कानूनों में संशोधन के बजाय एसवाइएल नहर के मुद्दे की तरह इन्हें खारिज करने की मांग भी की ताकि पंजाब पर इसका कोई असर न हो। सिद्धू ने कहा कि इसके लिए सभी विधायक तैयार हैं। इसके अलावा 2017 के चुनाव घोषणापत्र में किए गए बिजली खरीद समझौते रद करने के वादे को पूरा करने की अपील भी की। सिद्धू ने कहा कि धरने दे रहे शिक्षकों, डाक्टरों, सफाई कर्मचारियों, लाइनमैन आदि विभिन्न कर्मचारी संगठनों को बातचीत के बुलाया जाए ताकि विचार चर्चा से उनकी मांगों को हल किया जा सके। ज्ञापन में सिद्धू समेत चारों कार्यकारी अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक को सौहार्दपूर्ण बताया। उन्होंने सिद्धू और चारों कार्यकारी अध्यक्षों को बताया कि उन्होंने जिन मुद्दों पर चिंता जताई है वह पहले ही सरकार के ध्यान में हैं। पार्टी के साथ तालमेल करके इन पर काम किया जा रहा है। घोषणापत्र के अधिकतर वादे पूरे किए जा चुके हैं और शेष मामले भी जल्द हल हो जाएंगे। सरकार सभी चुनावी वादे पूरे करने के लिए वचनबद्ध है।

कैप्टन ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, कार्यकारी अध्यक्षों कुलजीत नागरा, संगत सिंह गिलजियां, पवन गोयल और सुखविंदर डैनी से कहा कि आपकी जीत मेरी जीत है और हमारी जीत पार्टी की जीत है। हमें राज्य और लोगों के हितों को देखते हुए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। पार्टी नेता और वर्कर सरकार के लोक हितैषी फैसलों व सरकार के कामों को जमीनी स्तर पर लेकर जाएं। कैप्टन ने सरकार और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को निरंतर मिलते रहने की पेशकश भी की। खास बात यह रही कि कैप्टन अमूमन अपने फार्म हाउस या सरकारी आवास पर बैठकें करते हैं, मगर सिद्धू व कार्यकारी अध्यक्षों के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक की।

सिंहदेव नाराज, संकट में विधायक बृहस्पति

नईदुनिया, रायपुर : पंजाब और राजस्थान के बाद अब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान तेज हो गया है। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह के आरोप के बाद मंगलवार को विधानसभा में मंत्री टीएस सिंहदेव शासन की तरफ से स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए सदन से बाहर चले गए। इससे विपक्ष को सरकार पर हमले तेज करने का मौका मिल गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है। एक मंत्री को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। इस बीच, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मंत्रियों के आग्रह पर सिंहदेव एक बार फिर विधानसभा पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। सिंहदेव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अब इस मामले में जो भी कहना होगा, मुख्यमंत्री ही कहेंगे।

विस परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय से करीब दो घंटे की चर्चा के बाद बाहर निकले सिंहदेव से जब सवाल किया गया कि क्या विवाद सुलझ गया, उन्होंने कहा कि यह भविष्य के गर्भ में है। सदन में वापसी के सवाल पर कहा कि बैठक में मैंने अपनी बात कह दी है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। आगे जैसी परिस्थिति बनेगी, देखा जाएगा। देर शाम सीएम निवास पर सभी मंत्रियों का एक बार फिर जमावड़ा हुआ। कांग्रेस के सूत्रों की मानें तो आलाकमान ने साफ कर दिया है कि विधायक बृहस्पति से पूरे मामले पर जवाब मांगा जाए। इसकी जिम्मेदारी पुनिया को सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक, बृहस्पति का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनका निलंबन भी किया जा सकता है।

सांसद मंडल ने गुपचुप मुकुल से की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- मुकुल से मिलने के बाद वहां से निकलते हुए उत्तरीय से अपना ढक लिया मुंह
- बंगाल की पूर्व बर्द्धमान सीट से सांसद के तृणमूल में लौटने की अटकलें तेज

बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल ने सोमवार रात गुपचुप मुकुल राय से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद उनके तृणमूल में लौटने की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। मुकुल भी कुछ समय पहले ही भाजपा छोड़कर तृणमूल में लौटे हैं।

जानकारी के मुताबिक, सुनील मंडल सोमवार रात करीब आठ बजे मुकुल राय के 181, साउथ एवेन्यू स्थित आवास पर पहुंचे। वे वहां 15 मिनट तक रुके। वहां से निकलते वक्त सुनील मंडल ने गले में डाले हुए पटके से अपना मुंह ढक लिया था। वहां मौजूद मीडियाकर्मियों ने जब उनसे बात करनी चाही तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए।

गौरतलब है कि बंगाल की पूर्व बर्द्धमान सीट से सांसद सुनील मंडल मुकुल के घनिष्ठ बताए जाते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा के खिलाफ मुंह खोलते हुए कहा था कि भगवा पार्टी उनपर विश्वास नहीं करती।

बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर सुनील मंडल ने कहा था कि दिल्ली से विमान में उड़कर बंगाल आकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की भी जमकर आलोचना करते हुए कहा था कि सुवेंदु ने उनसे जो वादे किए थे, उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया। गौरतलब है कि सुनील मंडल ने सुवेंदु अधिकारी के साथ ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा का झंडा थामा था। बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से ही वे पार्टी से दूरी बनाकर चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वह तृणमूल में वापसी की कोशिश में हैं और इस बाबत तृणमूल के आला नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। दिल्ली में मुकुल से मुलाकात को भी इसी का हिस्सा बताया जा रहा है।

पीएसी की बैठक का बहिष्कार करेगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : भाजपा ने मुकुल राय की अध्यक्षता में होने वाली बंगाल विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। मुकुल हाल में भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे हैं। उन्हें पीएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी अध्यक्षता में पीएसी की पहली बैठक 30 जुलाई को होने वाली है। भाजपा पीएसी के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को अवैध करार देते हुए इसका कड़ा विरोध कर रही है। गौरतलब है कि जिस दिन यह बैठक होने वाली है, उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंद्योपाध्याय के कक्ष में मुकुल के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत भाजपा की तरफ से की गई शिकायत पर सुनवाई होने वाली है। नंदीग्राम से भाजपा विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुकुल राय की पीएसी के चेयरमैन पद पर नियुक्ति अवैध तरीके से की गई है।

दिल्ली में होटल के सीसीटीवी फुटेज मे दिखे विधायक

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले की जांच कर रहे रांची पुलिस के विशेष जांच दल (एसआइटी) को दिल्ली में बड़ी सफलता हाथ लगी है। रांची के कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी के जांच के सिलसिले में खलारी के डीएसपी अनिमेष नैथानी के नेतृत्व में दिल्ली गई एसआइटी को द्वारका स्थित होटल विवांता से 15 मिनट का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। इसमें झारखंड के वे तीनों विधायक दिखे हैं, जिनका जिक्र गिरफ्तार आरोपितों के बयान में हुआ है। सूत्रों के अनुसार, ये विधायक कांग्रेस के इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला व निर्दलीय विधायक अमित यादव हैं। ये तीनों सफाई दे चुके हैं कि वे दिल्ली तो गए थे, लेकिन अपने निजी काम से।

एसआइटी साक्ष्यों के साथ रांची लौटेगी। समीक्षा के बाद फुटेज में नजर आ रहे तीनों विधायकों का पक्ष लिया जाएगा। गिरफ्तार आरोपितों के बयान के बाद भी अभी तक इन तीनों विधायकों का नाम प्राथमिकी में नहीं है। फुटेज में तीनों विधायक इनोवा से होटल विवांता पहुंचते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के भाजपा नेता जय कुमार बेलखेड़े उर्फ बालकुंडे, महाराष्ट्र के भाजपा नेता चंद्रशेखर राव बावनकुले व चरण सिंह के अलावा गिरफ्तार तीनों आरोपित अभिषेक दुबे, अमित सिंह व निवारण महतो भी दिखे हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है। हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले में दो दिन पहले जेल भेजे जाने से पूर्व अमित सिंह, निवारण प्रसाद व अभिषेक दुबे ने दिल्ली का पता दिया था। अभिषेक ने बताया था कि 15 जुलाई को वह इंडिगो की फ्लाइट से अमित सिंह, निवारण प्रसाद महतो व तीनों स्थानीय विधायकों के साथ दिल्ली गया था। सबका टिकट महाराष्ट्र के जय कुमार बेलखेड़े उर्फ बालकुंडे ने बुक कराया था। दिल्ली में झारखंड के तीनों विधायक कहां और किससे मिले, इसकी भी जानकारी पुलिस को है। अब एसआइटी के अधिकारी सभी संबंधित जगहों से साक्ष्य जुटा रहे हैं।

विधायक ने कहा, 50 करोड़ में भी नहीं बिकेगा अकेला

जासं, चौपारण (हजारीबाग) : चर्चा में आए बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने पूरे प्रकरण को एक साजिश बताया है। विधायक ने कहा कि हम सेक्युलर विचारधारा के हैं। हमारा और भाजपा का कोई गठजोड़ हो ही नहीं सकता। चाहे पेशगी की रकम एक करोड़ हो या 50 करोड़, अकेला यादव कभी बिक नहीं सकता। उन्होंने दिल्ली जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि जामताड़ा विधायक डा इरफान अंसारी के पिता की तबीयत खराब थी। वह दिल्ली में भर्ती थे। उन्हें देखने विधायक अंसारी के साथ दिल्ली गए थे। दिल्ली में किसी भाजपा नेता या विधायक से हमने मुलाकात नहीं की।

हाई कोर्ट पहुंचा झारखंड सरकार गिराने की साजिश का मामला

राज्य ब्यूरो, रांची : हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश का मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच गया है। पंकज कुमार यादव ने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल कराई है। इस प्रकरण की जांच सीबीआइ, आयकर व ईडी से कराने की मांग की गई है। राजीव कुमार ने बताया कि कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के कॉल डिटेल की जांच कराने की भी मांग की गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि विधायकों की खरीद-फरोख्त की जानकारी उन्हें कहां से मिली है। अनूप सिंह ने विदेश जाकर किन-किन लोगों से मुलाकात की है। 2005 से ही राज्य में विधायकों की खरीद-फरोख्त का खेल चल रहा है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतदाता विधायक का चुनाव करते हैं, लेकिन विधायक अपने फायदे और पद के लालच में बिक जाते हैं, जो मतदाता के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। याचिका में पिछले पांच माह में दिल्ली जाने वाले सभी विधायकों की जांच करने की मांग की गई है। इससे यह पता चल पाए कि दिल्ली जाने वाले विधायक किन-किन लोगों से मिले हैं। इसके साथ ही इनके खातों की जांच कराई जाए कि इस दौरान कहां-कहां ट्रांजेक्शन किया गया है।

बंगाल सरकार ने हिंसा के आरोपों को किया खारिज

राज्य ब्यूरो कोलकाता : बंगाल सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट के समक्ष 95 पृष्ठ का हलफनामा प्रस्तुत किया। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों का बिंदु-दर-बिंदु खंडन किया गया है।

हलफनामे में कहा है कि रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। यह भी कहा कि विस चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा की घटना नहीं हुई है। हिंसा से जुड़े आरोपों में सच्चाई नहीं है। विद्वेष की भावना से राज्य सरकार के खिलाफ रिपोर्ट पेश की गई है। मामले की सुनवाई बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल सहित पांच जजों की बेंच के सामने होगी। बता दें कि चुनाव के बाद हिंसा पर विभिन्न याचिकाओं पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार सहित सभी पक्षों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट पर 26 जुलाई तक हलफनामा जमा देने का निर्देश दिया था।

उप्र में खोया जनाधार पाने को कांग्रेस का सोशल इंजीनियरिंग पर जोर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- संगठन पुनर्गठन के जरिये सामाजिक संतुलन साधने की जुगत

उत्तर प्रदेश में अपना खोया जनाधार वापस पाने की जिद्दोजहद में जुटी कांग्रेस समाज के सभी वर्गों और समुदायों को साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रही है। संगठन पुनर्गठन से शुरू हुई इस मुहिम को पार्टी फील्ड में भी विस्तार देने में जुटी है। पंचायत चुनाव में बेशक पार्टी को इसका लाभ न मिला हो, लेकिन इस दिशा में उसकी कोशिशें जारी हैं।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उप्र की कमान संभालने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का पुनर्गठन करते हुए कमेटी के आकार पर कैंची चलाने के साथ उसमें सोशल इंजीनियरिंग को खास तवज्जो दी थी। इसी का नतीजा था कि 115 सदस्यीय पीसीसी में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 34 फीसद, मुस्लिमों की 17 फीसद, अन्य पिछड़ा वर्ग की 34 फीसद, अनुसूचित जाति की 12 फीसद और सिख समुदाय की एक फीसद है। जिलाध्यक्षों के चयन में भी सामाजिक संतुलन को साधने की कोशिश की गई। पार्टी के 75 जिलाध्यक्षों में सामान्य वर्ग की हिस्सेदारी 47 फीसद, मुसलमानों की 16 फीसद, अन्य पिछड़ा वर्ग की 25 फीसद और अनुसूचित जाति की 11 फीसद है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिलाध्यक्षों के चयन में पार्टी भले ही अन्य पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व न दे सकी हो, लेकिन उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसने ओबीसी वर्ग की उपेक्षा के आरोपों से खुद को बरी करने की कोशिश जरूर की है।

उप्र के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि 8,135 न्याय पंचायत समितियों और 840 ब्लाक समितियों के गठन में भी सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। 11 सदस्यीय ग्राम पंचायत समितियों के गठन में भी सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाएगा। संगठन पुनर्गठन में सभी वर्गों को समाहित कर उन्हें सियासी संदेश देने के साथ कांग्रेस पिछड़ों और अनुसूचित जाति जातियों के बीच विशेष रूप से पैठ बनाने में लगी है। प्रयागराज में निषादों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए पार्टी ने मार्च में प्रयागराज से बलिया तक नदी अधिकार यात्रा निकालकर पूर्वांचल में गंगा किनारे के जिलों में ठीक-ठाक उपस्थिति रखने वाले इस समुदाय का झंडाबरदार बनने की भूमिका निभाई है। वहीं आजमगढ़ में दलित पंचायत का आयोजन कर उसने अनुसूचित जातियों के बीच यह साबित करने का प्रयास किया कि जोर जुल्म के खिलाफ वह शोषितों-वंचितों के साथ है।

मिशन यूपी में जुटेंगे भाजपा सांसद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उप्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दोहराने का लक्ष्य साधकर भाजपा मजबूत मोर्चाबंदी करने में जुटी है। संगठन के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपकर सांसदों को मिशन-यूपी में लगाया जा रहा है। इसके लिए बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में सभी छह क्षेत्रों की बैठकें होनी हैं। इन बैठकों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां भाजपा ने तेज कर दी हैं। रणनीति को लेकर लखनऊ और दिल्ली में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। पूरा जोर इसी पर है कि जनता के बीच सेवा कार्यों को बढ़ाने के साथ ही योगी सरकार का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना है और योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी करना है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम तय कर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया गया है। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई है। चूंकि अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इसलिए सभी सांसद दिल्ली में ही मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित राज्यसभा सदस्य भी बैठकों में बुलाए गए हैं। बुधवार को ब्रज, पश्चिम और कानपुर, जबकि गुरुवार को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल मंगलवार को लखनऊ से रवाना हो गए। प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह पहले से वहां मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी भी दिल्ली जाएंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकों में रहेंगे।

संघ की भाजपा के साथ समन्वय बैठक आज

राज्य ब्यूरो, देहरादून : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिवसीय समन्वय बैठक बुधवार से देहरादून में शुरू होने जा रही है। पहले दिन संघ और भाजपा के मध्य होने वाली बैठक को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें भाजपा संगठन और उत्तराखंड सरकार के कामकाज के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी मंथन हो सकता है। अगले दो दिन यानी 29 व 30 जुलाई को प्रदेश में सेवा कार्यों में जुटे संघ से जुड़े 35 संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ उनके कामकाज पर मंथन होगा। समन्वय बैठकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार और डा. कृष्ण गोपाल मौजूद रहेंगे। भाजपा के साथ होने वाली समन्वय बैठक में पार्टी की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और चारों प्रांतीय महामंत्री उपस्थिति रहेंगे।

220 मृत किसानों के आश्रितों को पंजाब सरकार देगी नौकरी। ये वे किसान हैं, जिनकी मृत्यु कृषि कानून विरोध आंदोलन के दौरान हुई है। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा 550 किसानों के जान गंवाने की बात कह रहा है।

स्थायी समाधान के लिए पूर्ण सीमांकन की जरूरत

असम–मिजोरम सीमा विवाद ▸ भाजपा नेता किकान ने गृह मंत्री के हस्तक्षेप के बाद जल्द समाधान की उम्मीद जताई

कांग्रेस ने जमीनी हालात जानने के लिए सात सदस्यीय कमेटी गठित करने का किया है एलान

नई दिल्ली, प्रेट्र : असम-मिजोरम सीमा विवाद के बाद नगालैंड से भाजपा विधायक और पार्टी के मिजोरम प्रभारी महोनलुमो किकान ने पूर्ण सीमांकन की वकालत की है। उन्होंने कहा कि विवाद के स्थायी समाधान के लिए यह जरूरी है। किकान ने गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद जल्द समाधान की उम्मीद भी जताई है।

एक ओर असम में भाजपा सत्ता में है, तो दूसरी ओर मिजोरम में भाजपा के नेतृत्व वाले पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन (नेडा) के गठबंधन साझेदार मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) की सरकार है। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि सहयोगी होने के नाते दोनों दलों को मामले को सुलझाने में मदद करनी चाहिए। हालांकि झड़प के बाद स्थानीय स्तर पर भावनाएं प्रबल हुई हैं। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों का उपयोग कैसे हालात को शांत करने और दोनों राज्यों को एक टिकाऊ समाधान की ओर बढ़ाने के लिए करती है।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने हालात की समीक्षा के लिए सात सदस्यीय समिति गठित करने की बात कही है। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नोटिफिकेशन में कहा, 'तत्काल समिति गठित की जाएगी, जिसके सदस्य असम-मिजोरम सीमा विवाद की जमीनी स्थिति जानने के लिए कछार और अन्य क्षेत्रों में जाएंगे। समिति पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।' समिति में असम कांग्रेस प्रमुख भूपेन बोरा, देबब्रत सैकिया, गौरव गोगोई, प्रद्युत बोरदोलोई, सुष्मिता देब, रोकिबुल हुसैन और कामलाख्या डे पुरकायस्थ शामिल होंगे।

कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई ने इस मामले में लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने मामले में जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि विवाद के दौरान एलएमजी (लाइट मशीनगन) से हमले की बातें सामने आ रही हैं। यह जांच होनी चाहिए कि लोगों के पास एलएमजी कैसे पहुंची।

गृह मंत्री ने देश को फिर निराश किया : राहुल

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम–मिजोरम सीमा विवाद पर दुख जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, 'गृह मंत्री ने लोगों के जीवन में घृणा और अविश्वास का बीज बोकर एक बार फिर देश को निराश किया है। भारत अब भयावह नतीजों से दो–चार हो रहा है।'

झारखंड में डेढ़ किमी तक घुस आया ओडिशा

मुजतबा हैदर रिजवी, रांची


पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा अंचल स्थित कोइमा गांव, जहां सीमा विवाद को लेकर होती रही है झड़प। जागरण

असम और मिजोरम की तरह ही झारखंड और ओडिशा के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है। ओडिशा झारखंड में डेढ़ किलोमीटर अंदर तक घुस आया है और आठ गांवों पर कब्जा जमा चुका है। झारखंड के सीमावर्ती गांव की जमीन पर कब्जा कर लेने से लोग भूमिहीन हो गए हैं। दोनों ओर से कई बार लाठियां भी चल चुकी हैं। झारखंड सरकार ने कई बार ओडिशा से समस्या पर वार्ता की। लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल सका।

इन आठ गांवों पर जमाया है कब्जा : ओडिशा ने पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा अंचल के महुलडंगरी और गुड़ाबांदा अंचल के सात गांव सोना पेटपाल, छेरघाटी, काशीपाल, कुड़िया, मोहन पाल, भुरसन व कोइमा गांव पर कब्जा जमाया है।

2018 में माहुलडांगरी पर ओडिशा ने किया था कब्जा : ओडिशा के मयूरभंज जिले के सिरसा और नेदा गांव के लोगों ने नवबंर, 2018 में बहरागोड़ा अंचल के महुलडांगरी के 500 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाया। जब अंचल के लोग टोकरी बनाने के लिए कांसा काटने गए तो ओडिशा की ओर से पथराव कर हो गए। दोनों ओर तनातनी हो गई। झाड़पोखरिया थाना की पुलिस ने लाठी चार्ज कर बहरागोड़ा के लोगों को खदेड़ दिया था। अब ओडिशा के कब्जे में आए गांव की लगभग ढाई हजार एकड़ जमीन है। इसी तरह वर्ष 2018 में कोईमा-रातुला सड़क पर भी कब्जा कर लिया। यह सड़क पहले पूर्वी सिंहभूम जिले में थी। इस सड़क के ऊपर मयूरभंज जिला प्रशासन ने नई सड़क बना दी और इस कब्जा कर लिया।

कोइरा नाला के रास्ता बदलने से ओडिशा ने उठाया फायदा : स्वर्णरेखा नदी में गिरने वाले कोइरा नाला को दोनों राज्यों का सीमा माना गया है। नाले के कटाव और दिशा बदलने से भौगोलिक स्थिति में हुए परिवर्तन का ओडिशा ने फायदा उठाया। झारखंड की तरफ जितना यह नाला घुसा। ओडिशा यहां की जमीन पर कब्जा जमाता चला गया।

1983 में झारखंड ने सात गांवों पर दोबारा कर लिया था कब्जा

10 दिसंबर, 1983 को सिंहभूम के डीसी पुलिस का लाव लश्कर लेकर सीमा पर पहुंचे और सात गांवों पर कब्जा जमाने के लिए खूंटागड़ी करवाई। बाद में ओडिशा के अधिकारियों ने सभी खूंटे उखाड़ दिए और खेतों में काम कर रहे किसानों को वहां से मार कर भगा दिया। पिछले कई दशकों से बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन समस्या नहीं सुलझी।

तेजस एक्सप्रेस से करिए शिमला की सैर वाया नई दिल्ली

निशांत यादव, लखनऊ : देश की कारपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस जल्द ही पर्यटकों को भी सेवाएं देगी। तेजस एक्सप्रेस से दिल्ली के रास्ते हिमाचल प्रदेश की सैर कराने की तैयारी है। इस ट्रेन से सप्ताहांत पर पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश भ्रमण कराने का प्रस्ताव भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय ने तैयार किया, जिसे मंगलवार को नई दिल्ली स्थित आइआरसीटीसी मुख्यालय ने स्वीकृति भी दे दी। अब इसके पैकेज की दर और इसके दिन तय करने के आदेश दिए गए हैं।

आइआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस का लखनऊ से नई दिल्ली के बीच संचालन सप्ताह में चार दिन करेगा। लखनऊ से बड़ी संख्या में पर्यटक विमान से चंडीगढ़ और वहां से सड़क मार्ग से शिमला जाते हैं। ऐसे में कई बार फ्लाइट का महंगा किराया, होटल मिलने में दिक्कत और टैक्सी का खर्च अलग से सहना पड़ता है। आइआरसीटीसी विमानों की तर्ज पर ट्रेन होस्टेस वाली तेजस एक्सप्रेस से पर्यटकों को लुभाने की तैयारी कर रहा है। पर्यटकों के लिए यह पैकेज पांच दिन का होगा। तेजस से नई दिल्ली पहुंचने पर वहां एक्जक्यूटिव लाउंज में लंच के बाद सड़क मार्ग से चंडीगढ़ ले जाया जाएगा। चंडीगढ़ में रात्रि विश्राम के बाद पर्यटक सुबह शिमला रवाना होंगे। पर्यटकों को तीन सितारा होटल में ठहरने और खानपान की सुविधा आइआरसीटीसी मुहैया कराएगा।

न्यूज गैलरी


स्वर्ण आभूषणों से बनी कलाकृति... : पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की छठी पुण्यतिथि पर मंगलवार को देशभर में उन्हें याद किया गया। इस मौके पर केरल के त्रिशूर में एक कलाकार ने स्वर्ण आभूषणों से उनकी एक मनमोहक कलाकृति बनाई। मिसाइल मैन के रूप में मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रेट्र

दरबार मूव के कर्मियों को एक और माह की मोहलत

जम्मू : जम्मू–कश्मीर सरकार ने दरबार मूव से जुड़े रहे कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी आवास खाली करने के लिए एक महीने की मोहलत दी है। पहले उन्हें 20 जुलाई तक आवास खाली करने थे। अब आवास खाली करने के लिए कर्मचारियों को तीन दिन की छुट्टी भी मिलेगी। (राब्यू)

मप्र में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या छह हुई

इंदौर: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले पिपलियामंडी थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या छह हो गई है। मंगलवार को दो लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मंदसौर के जिला आबकारी अधिकारी को हटा दिया है। (नईदुनिया)

बदरीनाथ धाम पर टिप्पणी करने वाले पर मुकदमा

देहरादून : हिंदुओं की आस्था के केंद्र बदरीनाथ धाम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रायपुर थाना पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपित का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह बदरीनाथ धाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। (राब्यू)

अभेद्य होगी वाराणसी के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार के साथ अत्याधुनिक प्राइमरी रडार स्थापित किए जाएंगे। नया रडार भवन एक साल में बना लेने की योजना है। प्राइमरी रडार की मदद से आसमान में सभी प्रकार के विमान, हेलीकाप्टर और ड्रोन पर दूर से ही सटीक नजर रखी जा सकेगी। (जासं)

उप्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में गहरा सकता है बिजली संकट

जागरण संवाददाता, चतरा

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और पंजाब में बिजली संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। इन राज्यों के पावर प्लांटों में कोयले का स्टाक लगभग खत्म हो चुका है। एक-दो दिन के भीतर कोयले की आपूर्ति नहीं होने से वहां बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। सीसीएल की आम्रपाली परियोजना से उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के प्लांटों को कोयले की आपूर्ति होती रही है। परियोजना में पिछले आठ दिन से कोयले की ढुलाई और खनन का काम ठप है। इससे प्रतिदिन पांच करोड़ का नुकसान हो रहा है।

आम्रपाली परियोजना से शिवपुर रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई का ठेका अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी नकास के जिम्मे था। नकास का ठेका 20 जुलाई को समाप्त हो गया और अगले तीन वर्ष के लिए आरकेटीसी नामक दूसरी एजेंसी को काम दे दिया गया है।

बताया जा रहा है कि एजेंसी बदलने से ही विवाद उत्पन्न हुआ है। झमेला परिवहन वाली सड़क को लेकर है। आम्रपाली से शिवपुर साइडिंग तक सड़क का कुछ भाग रैयती जमीन पर है। जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो सीसीएल ने संबंधित रैयतों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया था। उसका मानना था कि यह जमीन परियोजना क्षेत्र से बाहर है। बाद में शिवपुर साइडिंग का निर्माण हुआ तो वह जमीन कोयला ढुलाई के मार्ग में आ गई। इसके बाद सीसीएल प्रबंधन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब उस जमीन से होकर कोयला ढोने पर रैयतों ने रोक लगा दी है। वह सीसीएल से उस जमीन का अधिग्रहण, उसके एवज में मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। सीसीएल प्रबंधन के अनुसार, अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड आंदोलन को हवा देकर अपना हित साधना चाहती है। चाल है। दोनों कंपनियों की लड़ाई में नुकसान सीसीएल एवं राज्य सरकार को हो रहा है।

जनरल रावत बोले– घुसपैठ नाकाम बनाने को रहें सतर्क

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ सटे अग्रिम इलाकों का दौरा कर, सेना की आपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान एलओसी पर जंगबंदी के बाद की स्थिति पर भी संबंधित सैन्य कमांडरों के साथ विचार-विमर्श करते हुए घुसपैठरोधी तंत्र को मजबूत बनाने और आतंकियों की घुसपैठ के साथ नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी को पूरी तरह नाकाम बनाने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किए।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सीडीएस रावत ने सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय संग उत्तरी कश्मीर में गुरेज सेक्टर की अग्रिम चौकियों का दौरा करने के अलावा बारामुला स्थित सेना की डैग्गर डिविजन का भी दौरा किया। उन्होंने यकीन दिलाया दुश्मन से निपटने के लिए संसाधानों की कमी को आड़े नहीं आने दी जाएगी।

श्रीनगर में गैंगवार, युवक को गोलियों से भूना

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

दम तोड़ रहे आतंकवाद के बीच कश्मीर में मंगलवार को गैंगवार की सनसनीखेज घटना सामने आई है। 16 गुज्जर छत्ताबल गैंग के सदस्य शेख मिरान अली को कथित तौर पर उसके विरोधी गैंग के सदस्य ने सरेआम गोलियों से भून डाला। उसे आठ गोलियां मारीं। श्रीनगर में यह अपनी तरह की पहली वारदात है। पहले इस घटना को आतंकी हमला माना जा रहा था, लेकिन पुलिस ने कुछ ही समय बाद स्पष्ट कर दिया कि यह हत्या गैंगवार का नतीजा है। अलबत्ता, देर शाम को आतंकी संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने शेख मिरान की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उसे पुलिस का सहयोगी करार दिया है।

श्रीनगर के डाउन-टाउन के बुलबुल लंकर, नवाकदल में सुबह करीब 11:30 बजे फिल्मी अंदाज में हुई इस हत्या के बाद से स्थानीय लोग सकते में हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शेख मिरान अली अपनी गाड़ी में सवार होने जा रहा था, तभी अचानक एक युवक आया और उसने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज से हड़कंप मच गया। शेख मिरान को आठ गोलियां मारी गईं। इनमें से अधिकांश उसके सिर पर लगीं। एक गोली उसकी गाड़ी के अगले शीशे पर भी लगी है। उसे जमीन पर गिरते देख हमलावर फरार हो गया।

गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने शेख मिरान को एसएमएचएस अस्पताल में पहुंचाया, जहां वह कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। वारदात के कुछ ही मिनट बाद पुलिस ने इस वारदात को गैंगवार बताते हुए कहा कि शेख मिरान 16 गुज्जर छत्ताबल गैंग का सदस्य था। उसकी विरोधी गैंग के सदस्यों के साथ लड़ाई हुई। इसमें चली गोली में वह मारा गया है। फिलहाल, मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। श्रीनगर के एक नामी स्कूल से पढ़ाई करने वाला 25 वर्षीय शेख मिरान अली कश्मीर के नामी बाडी बिल्डरों में गिना जाता था। वह दो जिम भी चला रहा था। वह इंटरनेट मीडिया, विशेषकर इंस्टाग्राम पर अक्सर सक्रिय रहता था।

डाउन-टाउन में ये तीन गैंग सक्रिय : स्थानीय सूत्रों ने बताया कि डाउन-टाउन में कथित तौर पर तीन गैंग बीते कुछ महीनों में सक्रिय हुए हैं। एक गैंग का नाम 16 गुज्जर, छत्ताबल है, दूसरा गैंग इत्तेहाद डाउन-टाउन है। तीसरा लश्कर-ए- नौहट्टा है। तीनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बीते दिनों शेख मिरान अपने गैंग के करीब 60-70 लड़कों के साथ विभिन्न वाहनों में पहलगाम गया था। उसने वहां कथित तौर पर हुड़दंग मचाया था। इसकी कुछ तस्वीरें भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थीं।

स्थानीय लोगों में चिंता

स्थानीय लोगों ने पुलिस की गैंगवार की थ्यौरी पर चिंता जताते हुए कहा कि वारदात के चंद मिनट बाद ही पुलिस को पता चल जाता है कि यह गैंगवार है। यह गैंग रातोंरात नहीं बने हैं। इनके पास हथियार भी हैं। आखिर, पुलिस ने इन गैंग को शहर में क्यों पनपने दिया। यह युवक आम लोगों को अक्सर तंग करते हैं, लेकिन पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की।

स्कूली छात्रों को साल में एक बार जरूर दिखाएं संग्रहालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विज्ञान से जोड़ने के लिए पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने कई अहम सुझाव दिए हैं। इनमें सबसे अहम सिफारिश यह है कि स्कूली छात्रों को साल में कम से कम एक बार संग्रहालयों का भ्रमण जरूर कराया जाए। समिति ने इसके लिए पर्यटन मंत्रालय से कहा है कि वह स्कूलों को इसके लिए राजी करे। समिति ने इसके साथ ही एक और अहम सुझाव दिया है, जिसमें सभी राज्यों में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) के क्षेत्रीय केंद्र खोलने को कहा गया है। मौजूदा समय में इसका केंद्र सिर्फ कोलकाता में है।

पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी संसद की इस स्थायी समिति का मानना है कि इन पहलों से नई पीढ़ी को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जा सकता है। इससे उनके मन में इनके प्रति सम्मान जगेगा। साथ ही इनके संरक्षण की मुहिम को भी मदद मिलेगी। नई पीढ़ी इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए आगे आएगी। समिति ने इसके साथ ही स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर संग्रहालय विज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम को शामिल करने का सुझाव दिया है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध करने को भी कहा है। समिति का कहना है कि संग्रहालय जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं, उसकी मंशा पूरी होनी चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में छात्रों को विज्ञान से भी जोड़ने की पहल की है। इसके तहत सभी राज्यों में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एनसीएसएम) के क्षेत्रीय केंद्र खोलने का सुझाव दिया है। इससे स्कूली बच्चों में विज्ञान के साथ संग्रहालय से जुड़ाव में भी मदद मिलेगी। इससे उनमें वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। समिति ने देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) स्थलों पर एक साइट संग्रहालय विकसित करने की भी सिफारिश की है। इसका उद्देश्य यह है कि वहां कोई घूमने जाए तो उसे उससे जुड़ी चीजें एक साथ मौजूद संग्रहालय में ही देखने को मिल जाएं।

नानकमत्ता गुरुद्वारा परिसर में नृत्य कार्यक्रम को लेकर सिख संगत में रोष, बवाल

जागरण टीम, ऊधमसिंह नगर

श्री गुरुद्वारा नानकमत्ता परिसर में 24 जुलाई को सीएम के आगमन पर हुए नृत्य कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने पर सिख संगत भड़क गई। प्रबंधन द्वारा दो सेवादारों को सोमवार को ही बर्खास्त करने के बावजूद मामला तूल पकड़ गया। इस मामले को लेकर मंगलवार को गुरुद्वारा के दीवान हाल में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश से शामिल होने आ रहे सिख संगत को पुलिस ने खटीमा-पीलीभीत बार्डर पर कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के लिए रोक लिया। इस पर संगत की पुलिस से भी नोकझोंक हो गई। इधर, बैठक में सिख संगत ने नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों से इस्तीफा मांगते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही श्री अकाल तख्त अमृतसर साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर रिपोर्ट मांगी है। कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने तनाव बढ़ने पर नानकमत्ता में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।

सीएम बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी 23 व 24 जुलाई को गृह जनपद ऊधमसिंह नगर में थे। 24 को सीएम नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुद्वारा गेट पर उनके स्वागत में बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया था। इसके बाद सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और धार्मिक डेरा कार सेवा में उनको चांदी का मुकुट पहनाया गया। जब मामले ने तूल पकड़ा तो प्रबंधन कमेटी ने दो सेवादारों को सोमवार को ही बर्खास्त कर दिया था। इधर, परिसर में नृत्य कार्यक्रम व मुकुट पहनाए जाने का वीडियो वायरल होने पर सिख संगत ने मंगलवार को बैठक बुला ली। इसमें शामिल होने के लिए भारतीय सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवीर सिंह विर्क बरेली, लखनऊ, पीलीभीत सहित आसपास के जिलों की संगत के साथ नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुंचे।

वहीं, दूसरी ओर मझोला में 17 मील चौकी बार्डर पर पुलिस ने संगत के लोगों को रोक लिया और आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने को कहा। इसे लेकर पुलिस व संगत बीच विवाद हो गया। अधिकांश लोग पुलिस की बात को अनसुना करते हुए नानकमत्ता पहुंच गए। भारतीय सिख संगठन के अध्यक्ष जसवीर सिंह विर्क का कहना है कि सीएम के स्वागत में गुरुद्वारा के गेट पर बालिकाओं का नृत्य, चांदी का मुकुट पहनाना और गुरुवाणी के संचालन में व्यवधान मर्यादा के खिलाफ है।

> शरारती तत्वों की ओर से बच्चों को परिसर में लाया गया था। सेवादारों ने उन्हें तत्काल परिसर से बाहर कर दिया। मुख्यमंत्री को मुकुट प्रबंधक कमेटी की ओर से नहीं बल्कि विधायक प्रेम सिंह राणा की ओर से भेंट किया गया था। गुरुवाणी में व्यवधान का आरोप गलत है। अकाल तख्त अमृतसर साहिब की कमेटी भी जांच कर रही है। उसका निर्णय हमें मान्य होगा।
>
> – सरदार सेवा सिंह, प्रबंधक श्री गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब

> यह नानकमत्ता साहिब का आंतरिक मामला है। जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश से भी संगत आई थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी तैनात की गई है।
>
> – दलीप सिंह कुंवर, एसएसपी, ऊधमसिंह नगर

हिंसा कभी भी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं रही : राष्ट्रपति


श्रीनगर में मंगलवार को कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षा समारोह में छात्रा को उपाधि देते राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द। सौजन्य : सूचना विभाग

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▸ कहा, मुझे विश्वास है कि यहां के युवा कश्मीर को बेहतर बनाने के मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने मंगलवार को कहा कि हिंसा कभी भी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं रही। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस शांतिपूर्ण परंपरा को तोड़ा गया। हिंसा एक वायरस की तरह है, जो शरीर पर हमला करता है। लोकतंत्र में सभी मतभेदों का समाधान करने और नागरिकों की प्रतिभा को बाहर लाने की क्षमता है। राष्ट्रपति ने कहा कि जैसे-जैसे कश्मीर शांति और खुशहाली के एक नए दौर की तरफ अग्रसर हो रहा है, वैसे ही यहां नई रोमांचकारी और सुखद संभावनाएं नजर आने लगी हैं। पूरा भारतवर्ष आप लोगों को गर्व और प्रशंसा की भावना के साथ देख रहा है। कश्मीर की खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक नई शुरुआत और दृढ़ प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि यहां के युवा कश्मीर को बेहतर बनाने के इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे।

शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कनवेंशन सेंटर श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षा समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मैं कश्मीर की युवा पीढ़ी से उनकी समृद्ध विरासत से सीखने का आग्रह करता हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीरी युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि पिछले आठ साल के दौरान एक हजार पीएचडी पास हुए हैं। पढ़ाई में आपका विश्वास प्रोत्साहित करने वाला है।

कश्मीर के सहयोग बिना इतिहास लिखना संभव नहीं : राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कश्मीर विश्वविद्यालय के दो सेंटर आफ एक्सीलेंस और लैब कश्मीर की मदद करेंगे और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए विश्व को रास्ता दिखाएंगे।

राष्ट्रपति ने कश्मीरी भाषा में जताई खुशी

कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने अपने भाषण की शुरुआत कश्मीरी भाषा से की। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, 'मैय स्पज, खुशी तौहि मिलिथ'। यानी मैं आपसे मिल कर खुशी महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति के कश्मीरी बोलने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।

> मैं कश्मीर को इस धरती पर स्वर्ग के रूप में ही देखना चाहता हूं। मैं अपने इस सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह जम्मू–कश्मीर की युवा पीढ़ी पर विश्वास रखता हूं। मुझे यकीन है कि वह मेरे इस सपने को जल्द सच करेगी।
>
> –राम नाथ कोविन्द, राष्ट्रपति

मौसम का हाल

श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 24 .6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, 1988 में रहा था 25 .6, जम्मू में हल्की बारिश से मौसम सुहाना, आज भी बारिश के आसार

कश्मीर में रही 33 साल की सबसे गर्म रात

जागरण टीम, जम्मू

मानसून के मौसम में भी कश्मीर में तपिश कम नहीं हुई है। दिन तो दूर रात की गर्मी भी बेहाल कर रही है। श्रीनगर में सोमवार-मंगलवार की रात पिछले 33 साल सबसे गर्म रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर चढ़कर 24.6 पर पहुंच गया। इसके पहले 21 जुलाई, 1988 को श्रीनगर में रात का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को कश्मीर में अधिकांश इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं, जम्मू में मंगलवार तड़के हल्की बारिश होने से मौसम सुहाना रहा। हालांकि, दोपहर को धूप निकल आई।

बीते कई दिनों से कश्मीर भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान लगातार सामान्य से कई डिग्री ऊपर बना हुआ है। रातें तक तपने लगी हैं। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचे से लोग पूरी रात बेचैन रहे। उमस ने अलग से परेशान किया। यहां का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री ऊपर 34.6 सेल्सियस रहा। श्रीनगर के अलावा भी अन्य इलाकों में न्यूनतम तापमान के सामान्य से काफी ऊपर रहा। श्रीनगर समेत अधिकांश स्थानों पर दिन भर चटक धूप रही। मौसम विभाग श्रीनगर के उपनिदेशक डा. मुख्तार अहमद ने बताया कि बुधवार को मौसम बदलने के आसार हैं।

नदी–नालों से दूर रहने की सलाह

शेर–ए–कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डा. महेंद्र सिंह ने बुधवार को जम्मू में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इस पूरे सप्ताह बारिश होती रहेगी। बारिश को देखते हुए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने लोगों को नदियों, नालों, दरिया और अन्य जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।

राज्यपाल गए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर, पवार ने दी नसीहत

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कोंकण के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर क्या गए, शरद पवार सहित महाविकास अघाड़ी के अन्य नेता उन्हें नसीहत देने लग गए हैं। पवार ने कहा है कि ऐसी परिस्थिति में ज्यादा लोगों को समस्याग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं करना चाहिए। इससे राहत कार्य में बाधा आती है।

मंगलवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हम जैसे नेताओं को ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए। बता दें कि 22 जुलाई से हो रही बरसात के कारण कोंकण एवं पश्चिम महाराष्ट्र के आठ जिलों में बाढ़ एवं भूस्खलन से अब तक 207 लोग मारे जा चुके हैं। इस बरसात से 1,028 गांव एवं करीब दो लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित जिलों के प्रभारी मंत्री इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस एवं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भी भूस्खलन से बुरी तरह ध्वस्त हो चुके रायगढ़ के तालिये गांव का दौरा कर चुके हैं। मंगलवार को राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी भी भाजपा विधायक आशीष शेलार के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे पर गए। माना जा रहा है कि राज्यपाल के दौरे को ही निशाना बनाते हुए शरद पवार ने नेताओं को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में न जाने की नसीहत दी है।

आसान नहीं है हर्ड इम्युनिटी की पहेली



कोरोना महामारी के प्रसार के साथ ही एक और शब्द जो लगातार चर्चा में रहा है, वह है हर्ड इम्युनिटी। हाल में चौथे देशव्यापी सीरो सर्वे के बाद से इसकी चर्चा ने फिर जोर पकड़ा है। सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिर कितनी आबादी को टीका लग जाने के बाद हर्ड इम्युनिटी आ जाएगी। यह सवाल इसलिए भी उठता है, क्योंकि अलग-अलग मौके पर शोधकर्ताओं ने इसका अलग-अलग आंकड़ा दिया है। आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी आफ न्यू साउथ वेल्स के जेम्स वुड और यूनिवर्सिटी आफ सिडनी की जूली लीस्क ने इस संबंध में कई सवालों के जवाब दिए हैं।

... इसलिए मुश्किल है सटीक थ्रेसहोल्ड बता पाना

कोरोना महामारी के डेढ़ साल बीतने के बाद भी विज्ञानी ऐसा थ्रेसहोल्ड नहीं बता पा रहे हैं, जिस पर निश्चित तौर पर हर्ड इम्युनिटी आ जाएगी। यह अनिश्चितता कई बार लोगों में संदेह पैदा कर देती है। थ्रेसहोल्ड नहीं बता पाने के दो अहम कारणों पर नजर डालते हैं :

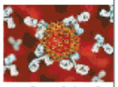
1 रूप बदलता वायरस और टीकों के प्रभाव में अंतर

कोरोना महामारी का कारण बनने वाला सार्स-कोव-2 वायरस बहुत तेजी से अपने अंदर बदलाव करता है। इसके वैरिएंट की संक्रामकता भी अलग-अलग पाई गई है। ऐसे में प्रभावी थ्रेसहोल्ड बदलता जाता है। इसी तरह, अलग-अलग वैरिएंट पर टीकों का असर भी बदलता है। फाइजर के टीके की दो डोज को अल्फा वैरिएंट पर 86 से 95 फीसद कारगर पाया गया है, जबकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 70 से 85 फीसद तक प्रभावी रही है। वैरिएंट की संक्रामकता जितनी ज्यादा होगी और वैक्सीन का असर जितना कम होगा, महामारी पर नियंत्रण के लिए उतनी ज्यादा आबादी को टीका लगाना होगा।



2 समय के साथ हल्की पड़ जाती है एंटीबाडी

कोई सटीक थ्रेसहोल्ड निर्धारित नहीं हो पाने का एक कारण यह भी है कि लोगों में बनी एंटीबाडी समय के साथ हल्की पड़ती जाती है। इंफ्लूएंजा की वैक्सीन के मामले में हम इसीलिए किसी हर्ड इम्युनिटी की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि उस टीके से मिली सुरक्षा बहुत कम समय तक की होती है। इस साल के टीके से बनी इम्युनिटी अगले साल फ्लू के समय काफी हद तक निष्प्रभावी हो जाती है और उस समय के नए वैरिएंट से संक्रमण नहीं रोक पाती है। कोरोना के मामले में भी ऐसी आशंका है। इसलिए टीके की बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा, आबादी का घनत्व भी हर्ड इम्युनिटी पर असर डालता है।



संक्रमण की चेन तोड़ती है हर्ड इम्युनिटी



जब कम से कम इतनी आबादी में एंटीबाडी बन जाए, जिससे संक्रमण की चेन टूट सके, उसे हर्ड इम्युनिटी कहते हैं और आबादी के इस प्रतिशत को थ्रेसहोल्ड कहा जाता है। टीके के जरिये सरकारों का लक्ष्य सबसे पहले इसी थ्रेसहोल्ड तक पहुंचना है। अलग-अलग बीमारी के लिए थ्रेसहोल्ड अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, खसरा के मामले में 92 से 94 फीसद लोगों में एंटीबाडी बनने पर हर्ड इम्युनिटी आती है। कोरोना के मामले में इसे 85 फीसद या इससे ज्यादा माना जा रहा है।

धीरे-धीरे सामान्य होगा जीवन

हम समझ सकते हैं कि हर्ड इम्युनिटी का सटीक थ्रेसहोल्ड बताना क्यों संभव नहीं है। हालांकि जैसे-जैसे टीकाकरण बढ़ेगा, जीवन सामान्य होता जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामले आएंगे, लेकिन कुछ जगहों पर सिमटे रहेंगे। कांटैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग जैसे कदमों का पालन करते रहना होगा।

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

दूसरी लहर में चार महीने बाद चार लाख से कम सक्रिय मामले

हालात ▸ करीब साढ़े चार महीने बाद 30 हजार से कम नए मामले मिले

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में चार महीने बाद सक्रिय मामले चार लाख से नीचे आए हैं। करीब साढ़े चार महीने बाद पहली बार एक दिन में 30 हजार से कम नए मामले भी पाए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 132 दिन बाद 29,689 नए केस मिले हैं और 124 दिन बाद सक्रिय मामले 3,98,100 रह गए हैं। एक दिन में सक्रिय मामलों में 13,089 की कमी हुई है।

अब तक वैक्सीन की 44 करोड़ 19 लाख डोज लगाई गईं : मंत्रालय ने बताया कि मंगलवार को सुबह सात बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की 44.19 करोड़ डोज लगाई गई हैं। इसमें पिछले 24 घंटे के दौरान लगाई गईं 65.86 लाख डोज भी शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक अभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2.28 करोड़ डोज बची हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 45.73 करोड़ डोज मुहैया कराई जा चुकी हैं और 24.11 लाख डोज जल्द ही उन्हें उपलब्ध करा दी जाएंगी।



उप्र के प्रयागराज स्थित एक वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लेते लोग। प्रेट्र

कोरोना से मौत पर कार्यबल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय कार्यबल का गठन करे। यह कार्यबल पता लगाएगा कि इस साल अप्रैल से जून तक भारत में हुई मौतों के लिए कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन किस हद तक जिम्मेदार था। शीर्ष अदालत में यह याचिका मुंबई निवासी शोधकर्ता और अभिनव भारत कांग्रेस के ट्रस्टी पंकज फडनीस ने दाखिल की है। इसमें मांग की गई है कि यह बताया जाए कि डेल्टा वैरिएंट की उत्पत्ति कहां हुई थी? याचिका में कहा गया है कि एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आखिरी तीन महीनों में 39 लाख भारतीयों की मौत हुई।

मसूरी में बिना कोरोना रिपोर्ट प्रवेश पर प्रतिबंध बढ़ा

जासं, देहरादून : कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पर्यटक स्थलों पर वीकेंड पर जुट रही भीड़ के नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधों को यथावत रखा है। चार अगस्त की सुबह छह बजे तक लागू कोरोना कर्फ्यू में वीकेंड पर मसूरी में अन्य वाहनों के साथ दोपहिया से प्रवेश पर भी रोक जारी रहेगी।

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	29,689
कुल सक्रिय मामले	3,98,100
24 घंटे में टीकाकरण	65.86 लाख
कुल टीकाकरण	44.19 करोड़

सुबह आठ बजे तक की स्थिति

नए मामले	29,689
कुल मामले	3,14,40,951
सक्रिय मामले	3,98,100
मौतें (24 घंटे में)	415
कुल मौतें	4,21,382
ठीक होने की दर	97.39 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	1.73 फीसद

कोरोना से 93 फीसद सुरक्षा देती है कोविशील्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया (एसआइआइ) की वैक्सीन कोविशील्ड कोरोना महामारी से 93 फीसद सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी लहर के दौरान सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (एएफएमसी) द्वारा किए गए एक अध्ययन का संदर्भ देते हुए मंगलवार को केंद्र ने इस बात की जानकारी दी। यह वैक्सीन मृत्युदर को भी 98 फीसद तक कम करती है।

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डा. वीके पाल ने इस अध्ययन के नतीजे मीडिया के सामने पेश किए। यह अध्ययन 15 लाख डाक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स पर किया गया। उन्होंने कहा, 'कोविशील्ड वैक्सीन से 93 प्रतिशत सुरक्षा देखी गई (जिन लोगों को कोविशील्ड टीका लगाया गया) और यह दूसरी लहर के दौरान था जो डेल्टा वायरस की वजह से फैली थी। मृत्युदर में भी 98 प्रतिशत की कमी देखी गई।' कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकों की उपयोगिता पर जोर देते हुए पाल ने कहा कि टीका लगवाने से संक्रमण कम होता है लेकिन यह पूर्ण गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा, 'कोई टीका यह गारंटी नहीं देता कि संक्रमण नहीं होगा लेकिन गंभीर बीमारी रोकी जाती है और लगभग खत्म हो जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया सजग रहें, सतर्क रहें और हमारे टीकों पर भरोसा रखने के साथ ही आने वाले हफ्तों और महीनों को लेकर सावधान रहें।' समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक अपोलो अस्पताल समूह की तरफ से किए गए एक अध्ययन में पाया गया है किकोरोना वैक्सीन संक्रमण से 97 फीसद सुरक्षा प्रदान करती हैं।

हेपेटाइटिस के मरीजों को खतरा, जल्द लगाएं टीका

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना के संक्रमण से हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी जैसी घातक बीमारी को खत्म करने का अभियान प्रभावित हुआ है। इस बीच लोगों को इन घातक बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। डाक्टर कहते हैं कि हेपेटाइटिस व लिवर की अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए कोरोना ज्यादा घातक है। अध्ययन में भी यह बात साबित हो चुकी है। इसलिए हेपेटाइटिस व लिवर की अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को जल्द टीका लगवा लेना चाहिए।

एम्स के गैस्ट्रोलाजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. शालीमार ने कहा कि कोरोना से संक्रमित लिवर सिरोसिस व हेपेटाइटिस के मरीजों पर अध्ययन किया गया है। जिसमें यह पाया कि लिवर की इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को कोरोना का संक्रमण होने पर मृत्यु दर अधिक होती है। लिवर सिरोसिस का एक बड़ा कारण हेपेटाइटिस बी व हेपेटाइटिस सी का संक्रमण है। देश में करीब तीन से चार फीसद लोगों को हेपेटाइटिस बी व करीब एक फीसद लोगों को हेपेटाइटिस सी है। समस्या है कि इन बीमारियों से पीड़ित ज्यादातर लोगों को अपनी बीमारी के बारे में मालूम नहीं होता। पीएसआरआइ अस्पताल के गैस्ट्रोलाजी विभाग के चेयरमैन डा. दिनेश कुमार सिंघल ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि लिवर के मरीजों के लिए कोरोना ज्यादा जानलेवा बन गया है।

हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण भी बढ़ाने की दरकार

हेपेटाइटिस बी की रोकथाम के लिए टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस बी का टीका राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का भी हिस्सा है। पांचवें परिवार स्वास्थ्य सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 85 फीसद बच्चों को यह टीका लग पाता है। करीब 15 फीसद बच्चे हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण से महरूम रह जाते हैं।

कुंभ में राजस्थान से अपलोड हुआ था कोरोना टेस्टिंग का फर्जी डाटा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

कुंभ में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े का राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया है। मैक्स कारपोरेट सर्विसेज के पार्टनर शरत पंत और मल्लिका पंत के कहने पर फर्जीवाड़ा करने वाले आशीष वशिष्ठ ने राजस्थान से फर्जी डाटा अपलोड कराया था। एसआइटी ने राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी राकी से इस बारे में पूछताछ की है। राकी ने बताया कि ढाई रुपये प्रति एंट्री की दर से उसे भुगतान मिला था।

कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एसआइटी की पड़ताल में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहली गिरफ्तारी के बाद एसआइटी ने भिवानी की डेल्फिया लैब संचालक आशीष वशिष्ठ को तीन दिन की रिमांड पर लिया था। उसकी निशानदेही पर हरियाणा से लैपटाप व रजिस्टर भी बरामद किया था। पूछताछ में आशीष वशिष्ठ ने बताया कि उसने राजस्थान के हनुमानगढ़ निवासी राम मोहन नवानी उर्फ राकी की मदद से कोरोना टेस्टिंग की फर्जी एंट्री आइसीएमआर पोर्टल पर डाली थी। इस पर एसआइटी ने राकी को पूछताछ के लिए हरिद्वार बुलाया था। पूछताछ में राकी ने एसआइटी को बताया कि फर्जी एंट्री डालने के लिए आइडी पासवर्ड आशीष ने उसे उपलब्ध कराए थे। उसने कई युवकों की मदद लेकर पोर्टल पर एंट्री कराई।

जायडस कैडिला ने डीसीजीआइ को अतिरिक्त डाटा सौंपा

नई दिल्ली, एएनआइ : अहमदाबाद की दवा कंपनी जायडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन जायकोव-डी की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से संबंधित अतिरिक्त डाटा भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआइ) को सौंप दिया है। सूत्रों ने बताया कि डीसीजीआइ ने कंपनी से अतिरिक्त डाटा की मांग की थी। कंपनी की तरफ से मुहैया कराए गए डाटा की विषय विशेषज्ञ समिति की अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी। अगर डाटा को संतोषजनक पाया जाता है तब डीसीजीआइ द्वारा अगस्त में जायडस कैडिला की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय फलक

'पोर्न एप' से कुंद्रा ने पांच माह में कमाए 1.17 करोड़

दोहरा झटका

मुंबई, प्रेट्र : मुंबई पुलिस ने मंगलवार को राज कुंद्रा की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए एक अदालत को बताया कि कारोबारी ने पोर्नोग्राफिक (अश्लील) फिल्मों के निर्माण व एप के जरिये वितरण से पिछले साल अगस्त से दिसंबर के बीच कम से कम 1.17 करोड़ रुपये की कमाई की। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हालांकि कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूसरी तरफ, बांबे हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल राहत देने से इन्कार करते हुए पहले अभियोजन पक्ष को सुनने का निर्णय लिया।

मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल रिमांड याचिका में पुलिस ने कहा, 'रयान थोर्पे व अन्य आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि पोर्न फिल्मों को दिखाने वाले हाटशाट एप की अगस्त से दिसंबर 2020 के बीच की कमाई 1,17,64,886 रुपये (1,58,057 डालर) थी। यह कमाई गूगल व एपल एप स्टोर के जरिये की गई। दोनों कंपनियों से जानकारियां मांगी गई हैं।' हालांकि, कोर्ट ने कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद वकील अबद पोंडा व सुभाष जाधव ने यह कहते हुए कि अब जांच खत्म हो चुकी है कुंद्रा की जमानत अर्जी दाखिल की।

▸ हाई कोर्ट ने कारोबारी को तत्काल राहत देने से किया इन्कार

शिल्पा शेट्टी को क्लीनचिट नहीं : पुलिस

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने कहा है कि पोर्न फिल्म मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को अभी क्लीनचिट नहीं दी गई है। मामले में संलिप्त सभी लोगों के खातों से लेनदेन की जांच के लिए फोरेंसिक आडिटर नियुक्त किए गए हैं। शर्लिन चोपड़ा को बतौर गवाह बयान देने के लिए बुलाया गया है। इस बीच न्यूफिक्स एप के मालिक अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर ने अपने बैंक खाते से प्रतिबंध हटाने के लिए मुंबई पुलिस को लिखा है, जिसमें उसके छह करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जब्त है।



अश्लील फिल्मों के निर्माण के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा (बाएं) को अपने साथ ले जाती मुंबई पुलिस की अपराध शाखा की टीम। एएफपी

उधर, हाई कोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी ने कुंद्रा की तरफ से गिरफ्तारी को दी गई चुनौती के संदर्भ में पुलिस को 29 जुलाई तक शपथ-पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।

कुंद्रा को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने फरवरी में अश्लील फिल्मों के मामले में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट में कुंद्रा के वकीलों ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तारी में प्रक्रिया का पालन नहीं किया। लोक अभियोजक अरुणा कामत ने कहा कि कुंद्रा को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस जारी किया गया था। एएनआइ के अनुसार, कुंद्रा के सहयोगी रयान को भी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

रो पड़ीं शिल्पा, कुंद्रा से हुई थी बहस : पुलिस सूत्रों ने बताया कि अपराध शाखा ने जब अश्लील फिल्मों के मामले में छापेमारी की तब शिल्पा शेट्टी व उनके पति राज कुंद्रा के बीच काफी बहस हुई थी और वह रो पड़ी थीं। शिल्पा ने कहा था कि उन्हें पति की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि शिल्पा ने कुंद्रा से पूछा था कि ऐसा क्यों किया और इसकी क्या जरूरत थी। शिल्पा पुलिस टीम के सामने ही बिफर पड़ी थीं।

दो महिलाओं को अश्लील फिल्म में काम करने को किया मजबूर

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में दो महिलाओं की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनका दावा है कि उन्हें 'अश्लील फिल्म में काम करने के लिए मजबूर किया गया' और बाद में उनमें से एक का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यहां यह जानकारी दी। उनमें से कुछ कारोबारी राज कुंद्रा और उनकी कंपनी से जुड़े बताए जाते हैं।

छग में मतांतरित पत्नियों और पास्टरों के खिलाफ शिकायत

मतांतरण

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में मतांतरण से आहत लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। मंगलवार को जगदलपुर में जहां एक दलित मतांतरित पत्नी से बेटी वापस लेने के लिए एसपी दरबार पहुंचा और शिकायत कर पास्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं, भिलाई में एक पत्नी ने पति और बेटे पर मतांतरण करने का दबाव बनाया तो पति ने थाने पहुंचकर पत्नी, बड़े बेटे, पास्टर और उसकी पत्नी के खिलाफ शिकायत की है। दोनों मामलों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों की मदद की है।

छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कोतवाली थाना के सामने पंचर बनाने की दुकान चलाने वाले युवक ओबी नाग की पत्नी का पांच साल पहले मतांतरण करा दिया गया था। शहर के एक पास्टर के बहकावे में आकर उसकी पत्नी बेटी को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई थी। इस समय वह किराये के मकान में रह रही है। हाल ही में मतांतरण का मामला गर्माने के बाद उसने बजरंग दल के जिला संयोजक अविनाश सिंह गौतम से अपनी बेटी को वापस पाने के लिए एसपी बस्तर के दरबार में गुहार लगाई है। एसपी जितेंद्र सिंह मीणा को दी शिकायत में उसने कहा कि सनसिटी निवासी एक पास्टर उसकी पत्नी के संपर्क में आया था। पास्टर उसे चर्च जाने और बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करने लगा।



जगदलपुर। पत्नी के मतांतरण से परेशान पति ओबी नाग। नईदुनिया

पास्टर क्रास और हिंदू-देवी देवताओं की मूर्तियों को पानी में डालकर यह साबित करने की कोशिश करता कि उसका मत श्रेष्ठ है। दरअसल क्रास तो लकड़ी का होता, इसलिए पानी के ऊपर आ जाता, जबकि धातु की बनी मूर्तियां डूब जाती थीं। इसी तरह लोहे के क्रास और मोम या लकड़ी की मूर्तियों को आग लगाकर दिखाता कि हिंदू देवताओं में शक्ति ही नहीं है। इसके अलावा बच्चे की मुफ्त शिक्षा और उपचार का प्रलोभन भी देता रहा। वह उसकी पत्नी को चंगाई और प्रार्थना सभाओं में भी ले जाता था। उसने जब अपनी पत्नी को अपना मत ही मानने की सलाह दी तो वह नौ वर्षीय बेटी को लेकर घर से चली गई। वह अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता है। यह भी चाहता है कि उसकी पुत्री का लालन-पालन हिंदू रीति-रिवाज से ही हो। अवयस्क पुत्री को वापस दिलाने और पास्टर के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है।

पिस्टल के बल पर युवक का मतांतरण कराया

जागरण संवाददाता, सहारनपुर : नौकरी की तलाश में उत्तराखंड से राजस्थान गए युवक का पिस्टल के बल पर मतांतरण करा दिया गया। वह भागकर पहले मुजफ्फरनगर, फिर सहारनपुर पहुंचा। उसने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर एसपी सिटी को शिकायत दी। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। नैनीताल तल्लीताल निवासी नितिन पंत ने बताया कि 2010 में वह नौकरी की तलाश में राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी गया था। यहां पर जब उसे नौकरी नहीं मिली तभी उसे मुस्लिम समाज के युवक मिले। आरोप है कि ये युवक उसे राजस्थान के मेवात के गांव पंचगावा में ले गए। यहां पर कुछ मौलवियों ने उसे पिस्टल दिखाकर जबरन मतांतरण कराया। इसके बाद उसे एक बंद कमरे में कई दिन तक भूखा रखा गया।

'मजबूरी में सड़कों पर भीख मांगते हैं लोग, रोक नहीं लगा सकते'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मानवीय समस्या है और कल्याणकारी राज्यों को इसका हल निकालना चाहिए

▸ भिखारियों और बेघरों के टीकाकरण और पुनर्वास की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा आदेश नहीं दे सकते। शिक्षा और रोजगार के अभाव में बच्चों समेत बड़े लोग सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हैं। यह सामाजिक आर्थिक मुद्दा है इसका हल मांगे गए आदेश से नहीं हो सकता। यह मानवीय समस्या है जिसे कल्याणकारी राज्यों को संविधान के भाग तीन (मौलिक अधिकार) और भाग चार (राज्य के नीति निदेशक तत्व) में दिए गए तरीकों से हल करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने बेघरों और भिखारियों को कोरोना टीका लगाए जाने और चिकित्सीय सुविधाएं देने की मांग पर केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने एक जनहित याचिका (पीआइएल) पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि याचिका में ऐसे लोगों के टीकाकरण और कोरोना के दौरान चिकित्सीय सुविधाओं का मुद्दा उठाया गया है जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

अदालत केंद्र और दिल्ली सरकार से यह जानना चाहती है कि इस मानवीय चिंता के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने मामले को 10 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए सालिसिटर जनरल से मामले की सुनवाई में कोर्ट की मदद करने का अनुरोध किया है।

पीआइएल में मांग की गई है कि कोरोना महामारी को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल और सड़क पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे लोगों का पुनर्वास कर मूलभूत सुविधाएं, आश्रय और चिकित्सीय सुविधाएं देना सुनिश्चित किया जाए साथ ही सभी को कोरोना टीका लगाया जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर हल निकालना चाहिए।

सिद्धू की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की आय के गलत आकलन के मामले में दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। सिद्धू ने इनकम टैक्स कमिश्नर के समक्ष इस मामले में दायर रिवीजन याचिका को रद करने के आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस अजय तिवारी एवं जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर 11 अगस्त तक जवाब तलब किया है। सिद्धू ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 2016-17 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी आय नौ करोड़ 66 लाख रुपये बताई थी और इसे 19 अक्टूबर, 2016 को जमा करवा दिया था। आयकर विभाग ने 13 मार्च, 2019 को सूचित किया कि उनकी आय 13 करोड़ 19 लाख रुपये है। इस तरह उनकी आय में तीन करोड़ 53 लाख रुपये और जोड़ दिए।

रेलवे एक हफ्ते में बताए कहां हैं नियमित 115 कर्मी : हाई कोर्ट

जासं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1996 में नियमित किए गए 115 दैनिक कर्मियों के बारे में उत्तर मध्य रेलवे से एक हफ्ते में जानकारी मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि वह कौन हैं और फिलहाल कहां है।

अपील का चार माह में करें निपटारा : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह चार माह में उन अपीलों पर फैसला करे जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों ने दायर की हैं।

भंवरी देवी हत्याकांड मामले के सहआरोपित को जमानत

जासं, जोधपुर : राजनीति में भूचाल लाने देने वाले भंवरी देवी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सह आरोपी परसराम विश्नोई को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

शशि थरूर के आवेदन पर सुनवाई से अदालत का इन्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : सुनंदा पुष्कर मौत मामले में आरोपित कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला 18 अगस्त तक टाल दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने थरूर की तरफ से कागजात पेश करने की मांग को लेकर दायर आवेदन को ठुकरा दिया। गीतांजलि गोयल ने कहा कि इसके आगे वे किसी भी नए आवेदन पर सुनवाई नहीं करेंगी। हालांकि, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को पेश करने के संबंध में अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव द्वारा की गई मांग को स्वीकार करते हुए अदालत ने लिखित बयान पेश करने को कहा।

सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भारतीय दंड सहिंता की धारा 306, 498ए और 302(हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 12 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 28 जुलाई, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

सरकारी खजाने में बढ़ रहा सोने का आरक्षित भंडार

नई दिल्ली: सरकारी खजाने में सोने का आरक्षित भंडार पिछले चार वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। सरकार विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरक्षित स्वर्ण निधि रखती है ताकि जरूरत पर इसका इस्तेमाल कर नकदी और विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जा सके। वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में सरकारी खजाने में 3,388 करोड़ डॉलर के स्वर्ण मौजूद थे। वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में आरबीआइ के पास 3,057 करोड़ डॉलर मूल्य का सोना आरक्षित था। (जाब्यू)

फार्मा क्षेत्र में पीएलआइ से छह वर्षों में 1.96 लाख करोड़ रुपये की निर्यात संभावनाएं हैं। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक लाख रोजगार की संभावनाएं हैं।

मनसुख मांडविया
रसायन व उर्वरक मंत्री



सेंसेक्स	52,578.76	▼ 273.51
निफ्टी	15,746.45	▼ 78
सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 46,505	▼ ₹123
चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹65,710	▼ ₹206
डॉलर	₹74.47	▲ ₹0.05
क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 74.79	

इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स घटाए सरकार : ह्युंडई

जाब्यू, नई दिल्ली : भारत में परिचालन शुरू करने के करीब पहुंची अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी आटो कंपनी ह्युंडई ने भी सरकार से आग्रह किया है कि वह इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क घटाए। उन्होंने कहा, इससे इन वाहनों के बाजार को गति देने में मदद मिलेगी। कंपनी ने इस कदम को पर्यावरण-अनुकूल इन वाहनों के प्रसार के लिए भी जरूरी बताया है।

ह्युंडई मोटर इंडिया के एमडी व सीईओ एसएस किम का कहना है कि आयात शुल्क घटाने के साथ ही अगर देश भर में ईवी की चार्जिंग की सुविधा बड़े पैमाने पर लगाया जाए तो देश में इन वाहनों के विकास व विस्तार को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से तैयार करने में समय लगेगा। पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ह्युंडई ने भविष्य में लांच किए जाने वाले अपने दो इलेक्ट्रिक कारों का प्रदर्शन भी किया।

विलफुल डिफाल्टर्स की संख्या बढ़कर 2,494 हुई : वित्त मंत्री

सीतारमण ने राज्यसभा में दी जानकारी, बैंकों ने फंसे हुए और बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से तीन लाख करोड़ वसूले

नई दिल्ली, प्रेट्र: जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या 2,208 से बढ़कर 2,494 हो गई है। कर्ज नहीं चुकाने वालों का यह आंकड़ा इस वर्ष 31 मार्च तक का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि आरबीआइ के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने फंसे हुए और बट्टे खाते में डाले गए कर्जों में से 3,12,987 करोड़ रुपये की वसूली की है। वहीं, विलफुल डिफाल्टर्स यानी जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों की संख्या जहां 31 मार्च 2019 को 2,017 थी जो 31 मार्च, 2020 को 2,208 और इस वर्ष 31 मार्च को 2,494 हो गई। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकारी बैंकों का फंसा कर्ज (एनपीए) 31 मार्च, 2019 को 5,73,202 करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च, 2020 को घटकर 4,92,632 करोड़ रुपये और इस वर्ष



निर्मला सीतारमण • फाइल फोटो

31 मार्च को 4,02,015 करोड़ रुपये रह गया है। उन्होंने कहा कि बैंक जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकारी बैंकों ने पिछले वर्ष के 1,75,876 करोड़ रुपये के मुकाबले 2020-21 के दौरान 1,31,894 करोड़ रुपये बट्टा खाते में डाले हैं। हालांकि दिए जा रहे कर्ज के मुकाबले एनपीए में लगातार गिरावट आ रही है। सरकारी बैंकों का एनपीए 31 मार्च, 2015 को 11.97 फीसद था जो इस वर्ष 31 मार्च को 9.11 फीसद रह गया।

49,000 करोड़ का कोई लेनदार नहीं

बैंकों और बीमा कंपनियों के पास लगभग 49,000 करोड़ रुपये उन खातों में पड़े हैं जिसका कोई लेनदार नहीं है। वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि पिछले वर्ष 31 दिसंबर तक बैंकों के पास यह रकम 24,356 करोड़ रुपये और बीमा कंपनियों के पास 24,586 करोड़ रुपये थी।

अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है बढ़ा हुआ कर संग्रह

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बढ़ा हुआ कर संग्रह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। इस अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 2.46 लाख करोड़ रहा है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 1.17 लाख करोड़ था। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी और गैर-जीएसटी) संग्रह 3.11 लाख करोड़ रुपये रहा है।

दो लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर आपदा की मार : तोमर

विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के चलते इस वर्ष अब तक दो लाख हेक्टेअर से ज्यादा कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचा है। जबकि पिछले वर्ष 66.55 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को नुकसान पहुंचा था। एक प्रश्न के जवाब में मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सबसे अधिक नुकसान गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उप्र, कर्नाटक, ओडिशा और गोवा में हुआ है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, किसानों के लिए शुरू की गई स्वैच्छिक पेंशन योजना (किसान मान-धन योजना) से अब तक 21.40 लाख से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। सितंबर 2019 में जब इसे लांच किया गया था तब इससे 13,29,353 किसान जुड़े थे।

ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन 22.17 घंटे विद्युत आपूर्ति

मई में ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन 22.17 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 23.36 घंटे था। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल, 2019 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में विदेशी निवेश गिरा

वित्त वर्ष 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) 2,926 करोड़ रहा है। यह 2019-20 के मुकाबले 57% कम है। यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंगलवार को लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 100 फीसद एफडीआइ की अनुमति है।

एथनाल बेचकर चीनी मिलों ने कमाए 15,000 करोड़ रुपये

चीनी मिलों ने तेल कंपनियों को एथनाल बेचकर वर्ष 2020-21 में लगभग 15,000 करोड़ रुपये कमाए है। यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को लोकसभा में दी।

फ्रांस की अदालत ने दिया भारत सरकार की संपत्तियां जब्त करने का आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने मंगलवार को संसद में स्वीकार किया कि केयर्न एनर्जी की याचिका पर फ्रांस की एक अदालत ने पेरिस स्थित भारतीय संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। रेट्रो टैक्स मुद्दे पर भारत सरकार से मुकदमा जीतने के बाद कंपनी सरकार से 1.72 अरब डालर (12,600 करोड़ रुपये से अधिक) की वूसली पर अड़ी हुई है। इसके लिए उसने दुनियाभर की कई अदालतों में मुकदमा दायर कर रखा है। वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को रास में कहा, सरकार ने केयर्न एनर्जी के पक्ष में दिए गए फैसले के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अपील की है। हालांकि यह नहीं बताया कि फ्रांस की अदालत ने किन संपत्तियों को फ्रीज का आदेश दिया है।

आनलाइन कर्ज देने वाले नहीं वसूल सकते ज्यादा ब्याज

दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआइ को तुरंत ठोस कदम उठाने का दिया निर्देश, केंद्र को आरबीआइ संग बैठक कर रिपोर्ट देने को कहा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: आनलाइन कर्ज देकर लोगों से भारी ब्याज वसूलने वाली मोबाइल एप आधारित कंपनियों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने बैंकिंग नियामक आरबीआइ को इस संबंध में जल्द सख्त कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को आरबीआइ के साथ मिलकर ब्याज दर निर्धारित करने और 27 अगस्त को अगली सुनवाई के दिन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने यह भी कहा कि अगर सरकार और आरबीआइ इस मसले से निपटने में देर करते हैं तो अदालत विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से इससे निपटेगी। सुनवाई के दौरान एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा और स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि इस मामले पर जल्द विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे रिपोर्ट देनी है। उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए समय देने की मांग की। वहीं, आरबीआइ ने कहा कि वह इस तरह के प्लेटफार्म को रेगुलेट नहीं करता है और इसका अधिकार केंद्र के पास है।

याचिकाकर्ता तेलंगाना निवासी धरणीधर कनीमोरी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आरबीआइ के पास इस तरह के कर्ज देने वाले एप पर शिकंजा कसने के अधिकार हैं। उन्होंने अदालत को बताया, जिस कमेटी की रिपोर्ट की बात आरबीआइ ने की है, उसे अप्रैल में रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। उन्होंने कहा है, ऐसे करीब तीन सौ प्लेटफार्म व एप हैं, जो लोगों को 1,500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का कर्ज देते हैं।

कच्चे माल के निर्यात में बढ़ोतरी, घरेलू उत्पादन हो रहा प्रभावित

राजीव कुमार • नई दिल्ली

कच्चे माल के निर्यात में भारी बढ़ोतरी से तैयार माल (फिनिश्ड गुड्स) के उत्पादन पर विपरीत असर की आशंका बढ़ रही है। खासकर एमएसएमई के उत्पादन और निर्यात में कमी आ सकती है। देश के निर्यात में एमएसएमई का योगदान 30 फीसद से अधिक है। कच्चे माल के निर्यात में भारी तेजी एवं घरेलू स्तर पर भी मांग बढ़ने से इनका दाम लगातार बढ़ रहा है, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ने से छोटे उद्यमियों के तैयार माल महंगे होते जा रहे हैं जिससे उनकी घरेलू और विदेशी दोनों ही बिक्री प्रभावित होगी। इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर कार्यक्रम पर असर पड़ेगा।

कारोबारियों के मुताबिक पिछले सात-आठ माह में सभी प्रकार के कच्चे माल की कीमतों में 50-70



लागत बढ़ने से छोटे उद्यमियों के तैयार माल हो रहे हैं महंगे • फाइल फोटो

फीसद तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। इनमें मुख्य रूप से स्टील, लौह अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, प्लास्टिक, रबर, काटन जैसे कच्चे माल शामिल हैं। स्टील के दाम में तो पिछले एक साल में लगभग 100 फीसद का इजाफा है। हाई रोल्ड कायल (एचआरसी) स्टील की कीमत पिछले साल जून में 35,900 रुपये प्रति टन थी जो अब 69,000 रुपये प्रति टन को पार कर गई है।

पिछले पांच-छह माह में इन सभी वस्तुओं के निर्यात में भारी बढ़ोतरी हुई है जिससे इन वस्तुओं के घरेलू दाम को मजबूती मिल रही है।

इंटिग्रेटेड एसोसिएशन आफ माइक्रो स्माल मीडियम इंटरप्राइजेज आफ इंडिया (आइएमएसएमईऑफइंडिया) के चेयरमैन राजीव चावला के अनुसार कच्चे माल के लगातार बढ़ रहे दाम से एमएसएमई निर्यातकों को आर्डर छोड़ने पड़ रहे हैं या उन्हें काम बीच में बंद करना पड़ रहा है। निर्यात आर्डर तीन महीने पहले लिए जाते हैं और हर पंद्रह दिनों पर कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं।

वहीं, गारमेंट निर्यातक ललित ठुकराल का कहना है कि काटन, यार्न जैसे कच्चे माल के निर्यात में जिस गति से बढ़ोतरी हो रही है,उस गति से गारमेंट के निर्यात में इजाफा नहीं है। जबकि आत्मनिर्भर भारत का अभियान तभी सफल होगा जब काटन और यार्न से अधिक गारमेंट निर्यात में बढ़ोतरी होगी।'

किर्लोस्कर परिवार में विरासत पर विवाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित किर्लोस्कर परिवार में 130 वर्षों की विरासत को लेकर विवाद हो गया है। संजय किर्लोस्कर के नेतृत्व वाली किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड (केबीएल) ने मंगलवार को उनके भाइयों अतुल व राहुल किर्लोस्कर के तहत आने वाली चार कंपनियों पर उसकी 130 साल की विरासत छीनने तथा जनता को गुमराह करने के प्रयासों का आरोप लगाया है। हालांकि, अतुल व राहुल किर्लोस्कर भाइयों द्वारा नियंत्रित कंपनियों ने संजय किर्लोस्कर की कंपनी के सभी आरोपों को नकारा है।

पारिवारिक संपत्ति विवाद गहराने के बीच केबीएल ने पूंजी बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखा है। इस पत्र में दावा किया गया है कि किर्लोस्कर आयल इंजंस (केओईएल), किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (केआइएल), किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड (केपीसीएल) तथा किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लि. (केएफआइएल) ने केबीएल की विरासत को छीनने या दबाने का प्रयास किया है। पत्र यह भी कहा गया है कि इन कंपनियों ने केबीएल की विरासत को अपनी विरासत के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। इस बारे में केआइएल के प्रवक्ता ने कहा कि केबीएल द्वारा सेबी को लिखे पत्र में कई प्रकार की तथ्यात्मक गलतियां हैं।

उल्लेखनीय है कि 16 जुलाई को अतुल व राहुल किर्लोस्कर के नेतृत्व वाली पांच कंपनियों ने अपने संबंधित कारोबारों में नयापन लाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इन कंपनियों के लिए नई ब्रांड पहचान तथा रंगों की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही नया किर्लोस्कर लोगो भी अपनाया गया था। इस घोषणा के समय कहा गया था कि ये रंग 130 बरस पुराने नाम की विरासत को दर्शाते हैं। केबीएल ने इसी पर आपत्ति जताते हुए सेबी को कहा है कि केओईएल की स्थापना वर्ष 2009 में, केआइएल की 1978 में, केपीसीएल की 1974 में और केएफआइएल की 1991 में हुई है। ऐसे में कंपनियां 130 वर्षों की विरासत का दावा नहीं कर सकती हैं।

मध्यस्थता सर्वोत्तम उपाय : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, आइएएनएस : किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के सीएमडी संजय किर्लोस्कर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मध्यस्थता इस पारिवारिक विवाद का सर्वोत्तम उपाय है। किर्लोस्कर ने बांबे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें किर्लोस्कर परिवार को संपत्ति विवाद मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किर्लोस्कर एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार है। अगर वह चाहे तो अदालत मध्यस्थता के लिए एक जज की नियुक्ति कर सकती है या परिवारिक दोस्तों-रिश्तेदारों की मदद ली जा सकती है। मुकदमा जारी रहा तो यह वर्षों तक खिंच सकता है, जो कारोबारी परिवार के लिए अच्छी बात नहीं होगी।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

प्रेमी के नाम नहीं की जमीन तो बेटी ने पिता को मरवा दिया

सम्भल: प्रेमी को 10 बीघा जमीन नहीं देने और उसके साथ शादी कराने से इन्कार करने पर एक बेटी ने अपने ही पिता को मरवा दिया। हत्या के बाद से फरार चल रही बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश किया है। इस हत्याकांड में शामिल एक तीसरा आरोपित अभी भी फरार है। मामले में मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। (जासं)

पूर्वी अफ्रीका में समुद्री सुरक्षा अभ्यास में आइएनएस तलवार

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना का पोत तलवार समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा व कानून प्रवर्तन क्षमता में सुधार लाना है। (आइएएनएस)

चंबा में भूकंप के हल्के झटकों से सहमे लोग

चंबा : चंबा में मंगलवार को सुबह 5.56 बजे भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.6 मापी गई है। डीसी राणा ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। (संस)

रोहिंग्या किशोरियों की तस्करी में तीन गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

रोहिंग्या महिलाओं व बच्चों की तस्करी त्रिपुरा सीमा से भी की जा रही है। उप्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने मानव तस्करी में लिप्त ऐसे ही एक गिरोह के सरगना समेत तीन आरोपितों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दो रोहिंग्या किशोरी समेत तीन लोगों को मुक्त कराया गया है। पकड़े गए तीनों आरोपितों में एक बांग्लादेश व दो म्यांमार के निवासी हैं। यह गिरोह भी ठेके पर बांग्लादेशी व म्यांमार के निवासियों को यहां लाकर फर्जी दस्तावेजों के जरिये पहचान बदलकर फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने वाले सिंडीकेट का हिस्सा है। दोनों रोहिंग्या किशोरियों को लखनऊ स्थित आशा ज्योति केंद्र भेजा गया है।

एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार के अनुसार बांग्लादेश निवासी मुहम्मद नूर उर्फ नूरुल इस्लाम तथा म्यांमार के निवासी रहमतउल्ला व शबीउर्रहमान उर्फ शबीउल्लाह को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध एटीएस के लखनऊ थाने में एफआइआर दर्ज की गई है। नूर त्रिपुरा में रहकर मानव तस्करी कर रहा था। एटीएस ने बीते दिनों रोहिंग्या महिलाओं को फर्जी दस्तावेजों के जरिये बने पासपोर्ट की मदद से मलेशिया भेजने वाले गिरोह को पकड़ा था। गिरोह



एटीएस द्वारा गिरफ्तार आरोपित रहमतउल्ला। सौ. एटीएस



एटीएस द्वारा गिरफ्तार आरोपित शबीउल्ला। सौ. एटीएस



एटीएस द्वारा गिरफ्तार आरोपित मुहम्मद नूर। सौ. एटीएस

सोना तस्करी में भी लिप्त था। उनसे मिली जानकारियों के आधार पर की जा रही छानबीन के दौरान नूर के बारे में सुराग मिले थे। गोपनीय सूचना मिली थी कि नूर कुछ रोहिंग्या को लेकर ब्रह्मपुत्र मेल से दिल्ली जा रहा है। इस पर एटीएस ने गाजियाबाद में नूर व दो किशोरियों समेत पांच संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।

एटीएस ने जब सभी से पूछताछ की तो सामने आया कि दोनों किशोरियां म्यांमार की निवासी हैं, जिन्हें शादी कराने का प्रलोभन देकर लाया गया था। नूर किशोरियों को एनसीआर क्षेत्र में बेचने के लिए ले जा रहा था, जबकि म्यांमार निवासी एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने का वादा कर लाया गया था। नूर के एक और साथी का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। आइजी एटीएस जीके गोस्वामी ने बताया कि आरोपितों को पकड़ने के लिए 30 से ज्यादा अधिकारियों की टीम लगाई गई थी, जिसने करीब 36 घंटे के आपरेशन के बाद कामयाबी हासिल की। आरोपितों के कब्जे से मोबाइल, आधार कार्ड, बांग्लादेशी नागरिकता का पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज मिले हैं।

नोएडा-गाजियाबाद में बसाए जा रहे घुसपैठिये : आइजी एटीएस का कहना है कि बांग्लादेश व म्यांमार के नागरिकों की अवैध घुसपैठ कराकर फर्जी दस्तावेजों के जरिये उन्हें बसाया जा रहा है। नौकरी दिलाने के बाद उनसे मोटा कमीशन वसूला जाता है। जून माह में अलीगढ़ से ऐसे ही गिरोह के सक्रिय सदस्यों को पकड़ा गया था। नूर त्रिपुरा सीमा से रोहिंग्या को लाकर नोएडा व गाजियाबाद के अलावा दिल्ली में शरण दिलाता था। अब तक दो हजार से अधिक रोहिंग्याओं को बसाने की बात सामने आ चुकी है।

पाक ने तीन अधिकारियों को वापस बुलाया

जासूसी कांड

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने के मामले का पर्दाफाश होने से नाराज पाकिस्तान सरकार ने दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से तीन अधिकारियों को वापस इस्लामाबाद बुला लिया है। उच्चायोग के अधिकारियों की मिलीभगत से अत्यंत गोपनीय तरीके से चल रहे जासूसी के इस खेल का पर्दाफाश होने से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। इससे नाराज पाकिस्तान सरकार ने इन तीनों अधिकारियों को अयोग्य बताकर वापस बुलाए जाने की जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस व आइबी को मिली है। हालांकि, जासूसी मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी इसे लेकर कुछ भी बोलने से इन्कार किया है।

पुलिस, आइबी व मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी उच्चायोग के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने में जुटे हुए हैं। अब तक इस मामले में दिल्ली पुलिस आगरा कैंट में तैनात सेना के लांसनायक परमजीत सिंह समेत पोखरण में सेना को रसद व मीट आपूर्ति करने वाले बीकानेर निवासी ठेकेदार हबीब-उर-रहमान व उच्चायोग में वीजा बनवाने वालों के लिए बिचौलिये का काम करने वाले मोहसिन को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली निवासी मोहसिन का कबाड़ी का बड़ा काम है। उसे पुलिस आइएसआइ व उच्चायोग के बीच की कड़ी मान रही है। सूत्र बताते हैं कि मोहसिन आइएसआइ के सीधे संपर्क में था। पाकिस्तान के लिए वीजा लेने जाने वाले हर शख्स से उच्चायोग में संपर्क कर मोहसिन उसे टटोलने का काम करता था। यदि कोई काम का लगता था तो उसे लालच देकर जासूसी के लिए कहता था।

बीकानेर व सीकर के लोगों के खाते में मोहसिन ने भेजे लाखों रुपये : पाकिस्तान से हवाला व अन्य तरीके से मोहसिन के पास ही पैसे आते थे। हबीब-उर-रहमान के कहने पर वह लोगों के बैंक खातों में पैसे भेजने का काम करता था। मोहसिन के बैंक खातों की जांच से पता चला है कि उसने राजस्थान के बीकानेर व सीकर में कई लोगों के खातों में नियमित तौर पर लाखों रुपये भेजे थे। पुलिस उक्त सभी खातों की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि वे सभी हबीब-उर-रहमान के संपर्क के लोग हो सकते हैं, जो जासूसी में लिप्त रहे हों। अगर ऐसा हुआ तो उक्त दोनों जगहों से कई अन्य लोगों की जल्द गिरफ्तारी संभव है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपित सेना से जुड़े दस्तावेज आइएसआइ व आतंकियों के हैंडलरों को वाट्सएप व इंस्टाग्राम के जरिये मुहैया कराते थे।

एटीएस टीम ने 26 लोगों को उठाया, आठ को ले गई साथ शिकंजा

जागरण संवाददाता, कानपुर : रिमांड के आखिरी तीन दिनों में अलकायदा आतंकी मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन से ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने को आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम ने ताकत झोंक दी है। मंगलवार को शहर से बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों आतंकियों के सामने 26 लोगों की शिनाख्त परेड कराई गई, जिसमें आठ संदिग्ध मिले। वहीं, छह अन्य की भी तलाश हो रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच से मदद मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार सुबह से ही महानगर के विभिन्न स्थानों में छापेमारी कर 26 लोगों को एटीएस ने उठाया। बाबूपुरवा, मछरिया, नौबस्ता, चमनगंज, बेकनगंज, आवास विकास और हीरामन का पुरवा आदि क्षेत्रों के रहने वाले हैं।

खेल जागरण

पाजिटिव क्रुणाल सीरीज से बाहर, दूसरा टी-20 स्थगित

- भारत-श्रीलंका के बीच अब आज खेला जाएगा यह मुकाबला
- पृथ्वी व सूर्यकुमार के इंग्लैंड में पहला टेस्ट खेलने की संभावना नहीं

कोलंबो, प्रेट्र : भारतीय आलराउंडर क्रुणाल पांड्या के कोविड-19 के लिए हुए परीक्षण में पाजिटिव आने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में मंगलवार को होने वाला दूसरा टी-20 मैच एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अब यह मैच बुधवार को खेला जाएगा। साथ ही क्रुणाल भी सात दिन के लिए क्वारंटाइन हो गए हैं, जिसके चलते वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। हालांकि, क्वारंटाइन में रह रहे उनके करीबी संपर्क में आए आठों लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट निगेटिव आए हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर उन्हें मैदान पर नहीं उतारा जाएगा। चूंकि, करीबी संपर्क में आए लोगों में ज्यादातर खिलाड़ी हैं, इसलिए भारत को एक कमजोर टीम को मैदान में उतारना पड़ सकता है।

श्रीलंका के स्वास्थ्य प्रोटोकाल के तहत क्रुणाल भारतीय टीम के बाकी सदस्यों के साथ 30 जुलाई को भारत नहीं लौट सकेंगे। उन्हें अनिवार्य क्वारंटाइन पूरा करने के बाद निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का इंतजार करना होगा।

हालांकि, भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की यह सीरीज होगी, क्योंकि



क्रुणाल पांड्या। एएनआइ

कुछ और मामले आने पर भी भारत के पास निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ इतने खिलाड़ी हैं कि टीम उतारी जा सकती है। तीसरा और आखिरी टी-20 मैच गुरुवार को होगा।

क्रुणाल मंगलवार सुबह पाजिटिव पाए गए, जिन्हें क्वारंटाइन पर रखा गया है। भारत के बाकी खिलाड़ियों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट का इंतजार है।

बीसीसीआइ सचिव जय शाह ने कहा, 'मंगलवार की सुबह मैच से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें क्रुणाल की रिपोर्ट पाजिटिव आई है। मेडिकल टीमों ने आठ लोगों की पहचान की है, जो उनके करीबी संपर्क में थे।'

भारत 20 सदस्यी टीम और चार स्टैंडबाई नेट गेंदबाजों के साथ श्रीलंका दौरे पर गया है। मैच यहां आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है और अब लगातार दो दिन मैच खेले जाएंगे।

भारत ने पहला टी-20 मैच 38 रन से जीता था। हालांकि, यह समझ से परे है कि पिछले एक महीने से कड़े बायो-बबल (कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित माहौल) में रह रहे क्रुणाल पाजिटिव कैसे हो गए।

क्रुणाल के पाजिटिव आने की वजह से पृथ्वी शा और सूर्यकुमार यादव की इंग्लैंड रवानगी पर भी असर पड़ सकता है। ये दोनों फिलहाल श्रीलंका में हैं और दूसरा टी-20 मैच खेलने के बाद इनके इंग्लैंड रवाना होने की संभावना था। अब ऐसे में इनके रवाना होने में भी विलंब होगा, जिसके चलते इनके इंग्लैंड के खिलाफ चार अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट में खेलने की संभावना नहीं है।

विनेश टोक्यो के लिए उड़ान लेने से चूकीं, आज पहुंचेंगी

ओलिंपिक डायरी

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीदों में से एक पहलवान विनेश फोगाट मंगलवार को फ्रैंकफर्ट से टोक्यो के लिए अपनी उड़ान नहीं ले पाई क्योंकि उनके यूरोपीय संघ (ईयू) के वीजा की अवधि एक दिन पहले ही खत्म हो गई थी।

खेलों से पहले हंगरी में अपने कोच वालर अकोस के साथ प्रशिक्षण ले रही विनेश को मंगलवार रात टोक्यो पहुंचना था, लेकिन उन्हें विमान में चढ़ने से पहले फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। भारतीय ओलिंपिक संघ के सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और वह बुधवार को टोक्यो पहुंच जाएंगी। सूत्र ने कहा, उनका वीजा 90 दिनों के लिए मान्य था लेकिन, बुडापेस्ट से फ्रैंकफर्ट पहुंचने पर पता चला कि वह 91 दिनों के लिए यूरोपीय संघ (के क्षेत्र) में थी।

तीरंदाजों के पास खुद को साबित करने का आखिरी मौका : भारतीय तीरंदाज टोक्यो ओलिंपिक की टीम स्पर्धाओं से बाहर होने की निराशा को दूर कर बुधवार को यहां होने वाली व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं की कठिन चुनौतियों का सामना करेंगे। भारत को सबसे ज्यादा उम्मीदें दुनिया की नंबर एक महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी से होगी, जो लगातार तीसरी बार ओलिंपिक में चुनौती पेश कर रही हैं जबकि प्रवीण जाधव के प्रदर्शन पर भी नजरें होंगी।

विजयी अभियान जारी रखना चाहेंगी पीवी सिंधू : बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू जब बुधवार को महिला सिंगल्स में ग्रुप-जे के मैच में हांगकांग की चेउंग मगानी यी के खिलाफ खेलने उतरेंगी तो विजयी अभियान जारी रखने की कोशिश करेंगी।

पूजा रानी की नजर जीत पर : भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी बुधवार को अंतिम-16 के मैच में उतरकर अपने ओलिंपिक अभियान का आगाज जीत के साथ करना चाहेंगी।

जब मां को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाई मीराबाई चानू

इंफाल, प्रेट्र : ओलिंपिक की तैयारी के लिए पिछले पांच वर्षों में ज्यादातर वह उनसे दूर रहीं, लेकिन टोक्यो में अपना सपना पूरा होने के बाद गले में रजत पदक लेकर भारोत्तोलक मीराबाई चानू जब मणिपुर लौटीं तो अपनी मां को देखकर आंसुओं पर काबू नहीं रख सकीं। मणिपुर ने अपनी बिटिया के स्वागत में मानो पलक पावड़े बिछा दिए। बीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। मीराबाई की झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ मीडियाकर्मी भी मौजूद थे। उनके बाहर निकलते ही अफरातफरी मच गई। रियो (2016) ओलिंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मीराबाई को पिछले पांच वर्षों में सिर्फ पांच बार ही अपने घर पहुंच पाई थीं। मीराबाई यहां पहुंचने पर अपनी मां सेखोम ओंगबी तोम्बी लीमा और पिता सेखोम कृति मेइतेई से गले मिलीं, जिसके बाद उनकी आंखें नम हो गईं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 28 जुलाई, 2021

दैनिक जागरण
प्रार्थना हृदय की पुकार है

ठहरी हुई संसद

संसद के निचले सदन में विपक्ष की नारेबाजी से आजिज आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे सख्त शब्दों में अपनी नाखुशी जाहिर की, कुछ वैसे ही राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने अपनी नाराजगी प्रकट की। जहां लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों से नारेबाजी की प्रतियोगिता से बाज आने को कहा, वहीं राज्यसभा के सभापति ने संसद सदस्यों को आत्मनिरीक्षण करने और सदन का समय बर्बाद न करने की हिदायत दी। इसमें संदेह है कि इस नाराजगी का कहीं कोई असर विपक्षी दलों के नेताओं पर पड़ेगा। इसके आसार इसलिए नहीं, क्योंकि विपक्षी दलों ने पहले से ही यह तय कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, संसद को नहीं चलने देना है। विपक्ष न केवल एकजुटता के अभाव से ग्रस्त दिख रहा है, बल्कि इससे भी कि किन मसलों को प्राथमिकता देनी है और किस तरह? भले ही वह कुछ मुद्दों को तूल देता हुआ दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसे इन मुद्दों पर बहस में दिलचस्पी है। यदि ऐसा कुछ होता तो उसकी ओर से ऐसा माहौल उत्पन्न नहीं किया जाता कि संसद चलने ही न पाए। समझना कठिन है कि विपक्ष संसद की कार्यवाही बाधित कर क्या हासिल करना चाहता है? यदि वह यह समझ रहा है कि संसद न चलने से जनता के बीच कोई अच्छा संदेश जाएगा तो यह संभव नहीं, क्योंकि जनमानस तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कोई सार्थक बहस चाहता है।

इस पर आश्चर्य नहीं कि विपक्ष के हंगामा मचाने वाले रवैये का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को उसकी पोल खोलने को कहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को खासतौर पर निशाने पर लिया। उनकी मानें तो कांग्रेस खुद भी संसद नहीं चलने दे रही और अन्य विपक्षी दलों को भी इसके लिए उकसा रही है। वास्तव में यह देखना दयनीय है कि जब कांग्रेस को विपक्ष का नेतृत्व करते हुए उसे दिशा देनी चाहिए, तब वह खुद दिशाहीन दिख रही है। आखिर यह उसकी दिशाहीनता नहीं तो और क्या है कि उसने जैसे कृषि कानून बनाने का वादा अपने घोषणापत्र में किया था, वैसे ही कानून बन जाने पर उनका विरोध कर रही है? बेहतर हो कि वह 2019 में जारी किए गए अपने घोषणापत्र को फिर से पढ़े या फिर यह स्पष्ट करे कि उसके यू टर्न लेने की वजह क्या है? यदि उसका मकसद किसानों को गुमराह करना नहीं है तो फिर उसे अपना यह घोषणापत्र वापस लेना चाहिए। उसके रवैये से यही पता चलता है कि विरोध के लिए विरोध वाली राजनीति किस तरह सिर चढ़कर बोल रही है। इस राजनीति से किसी का भला होने वाला नहीं-आम जनता का तो बिल्कुल नहीं!

मुफ्त वाइफाइ

स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों, नगर निगमों और नगरीय निकायों समेत कुल 217 स्थलों पर मुफ्त वाइफाइ सुविधा देने की तैयारी स्वागत योग्य है। इसके लिए मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को सार्वजनिक स्थल चिन्हित करने को कहा जा चुका है। यह स्थान कोई बस अड्डा या रेलवे स्टेशन के समीप हो सकता है, तहसील या कचहरी का कैंपस हो सकता है अथवा भीड़भाड़ वाला कोई ब्लाक मुख्यालय भी। बड़े बाजार को भी ले सकते हैं, बशर्ते लाभ ज्यादा लोगों को मिलने की गारंटी हो। योजना के मुताबिक बड़े शहरों में दो और कस्बों में एक स्थान पर इंटरनेट सेवा दी जाएगी। करार उन्हीं कंपनियों से करने को कहा गया है, जिनकी स्पीड अच्छी हो। आज के दौर में इंटरनेट की जरूरत बहुत बढ़ चुकी है। आनलाइन सेवाएं भी तेजी से पांव पसार रही हैं। इनकी उपयोगिता कोरोना महामारी के दौर में समझ आई, जब बाजार बंद हुए और लोगों का मिलना-जुलना थमा। फिर बड़ी कंपनियां घर से काम (वर्क फ्राम होम) लेने लगीं और रूटीन बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग से निपटाई जाने लगीं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी संकल्प पत्र में मुफ्त वाइफाइ सुविधा का वादा किया था। सत्ता मिलने पर योगी सरकार ने लखनऊ सहित कई शहरों के प्रमुख स्थलों पर यह सेवा शुरू भी कर दी थी। अब उसी का विस्तार हो रहा है। यद्यपि बड़े शहरों में इंटरनेट मिलना आसान है, लेकिन छोटे शहरों और कस्बों में चुनौतियां अब भी कम नहीं। स्पीड नहीं मिली तो इंटरनेट का होना, न होने जैसा है। अब मुफ्त वाइफाइ से इनके समेत उन लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो इंटरनेट सेवा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। खासकर गांव से कस्बों में आकर पढ़ाई कर रहे बच्चे इसका बखूबी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि स्कूल बंद होने के बाद ग्रामीण इलाकों में आनलाइन पढ़ाई की सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। सरकार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी मुफ्त वाइफाइ सुविधा देनी चाहिए, ताकि वहां के बच्चे भी बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकें।

सरकार को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी मुफ्त वाइफाइ सुविधा देनी चाहिए, ताकि वहां के बच्चे भी बदलते समय के साथ आगे बढ़ सकें

साझा चिंता और तात्कालिक चुनौती



श्रीराम चौलिया

चीन की काट भारत-अमेरिका रिश्तों से जुड़ा एक दीर्घकालीन मुद्दा है, पर अभी अफगानिस्तान पर ध्यान दिया जाना कहीं ज्यादा जरूरी है



एंटनी ब्लिंकन (बाएं) और एस. जयशंकर पर आई एक बड़ी समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी। फाइल

आज से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा शुरू हो रहा है। बतौर विदेश मंत्री वह पहली बार भारत आए हैं। यूं तो इस दौरे का मकसद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और वैश्विक समस्याओं के समाधान में परस्पर सहयोग को बढ़ाना है, परंतु एक और तात्कालिक महत्वपूर्ण मसला है। यह अफगानिस्तान से जुड़ा है, जहां से अमेरिकी फौजों की वापसी को देखते हुए हालात तेजी से बदल गए हैं। इस पर ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बीच गहन मंथन होने की उम्मीद है। बीते कुछ वर्षों से भारत-अमेरिका के बीच लगातार मजबूत हुई दोस्ती की डोर ने उनसे अपेक्षाएं बढ़ाई हैं। इससे दोनों देशों की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। आज अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तेजी से बदल रही है। अमेरिकी वर्चस्व घटा है। उसके वैश्विक नेतृत्व पर अनिश्चितता बढ़ी है। चीन ने जिस तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई है उससे अमेरिका केंद्रित एकध्रुवीय व्यवस्था अस्त होने के कगार पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अब हम उस द्विध्रुवीय विश्व में प्रवेश कर रहे हैं, जहां अमेरिका और चीन बराबर की टक्कर वाली महाशक्तियां होंगी। वहीं अन्य देशों को मध्यम या उससे कम स्तर की शक्तियों के रूप में ही संतुष्ट होना पड़ेगा। नार्वे के राजनीतिशास्त्री आयस्टीन ट्यून्सजो के अनुसार चीन और अमेरिका के बीच शक्ति में अंतर दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है। उधर चीन से पिछड़े देशों और उसके बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। ट्यून्सजो मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य की तुलना शीतयुद्ध के आरंभिक काल से करते हैं। यह वह दौर था जब सोवियत संघ और अमेरिका शिखर पर जबकि अन्य देश वैश्विक ढांचे के अनुक्रम में उनसे काफी निचले पायदान पर थे।

यदि भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों की बात करें तो वह बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने की हिमायत करती है। इससे आशय है कि हम भी दुनिया की अग्रणी शक्ति बनें। साथ ही अन्य देशों की आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक शक्ति में बढ़ोतरी हो। इसके पीछे यही मंतव्य है कि इससे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और लोकतांत्रिक बने और शक्ति का संकेंद्रण महज एक या दो महारथियों के पास न होकर उसका सही संतुलन बना रहे। चीन का रवैया हमारे इस दृष्टिकोण के ठीक उलट है। वह चाहता है कि एशिया में उसके समान कोई और शक्ति न उभरे। वह अपने धन-बल की शक्ति से अमेरिका को पछाड़कर एक नई विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है, जो उसके मूल्यों से ही संचालित हो। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के 'राष्ट्रीय पुनर्जागरण' की मंशा ही चीन केंद्रित साम्राज्य की स्थापना है। इसमें चीन के अंतरराष्ट्रीय स्वामित्व का लक्ष्य है। इससे निःसंदेह अमेरिका को क्षति पहुंचेगी, लेकिन भारत के लिए स्थिति असहनीय हो जाएगी। चीन पड़ोस में सबसे पहले भारत पर नियंत्रण की कुचेष्टा करेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद भारत में ही चीन के लिए चुनौती बनने का माद्दा है। फिलहाल चीन के तेवर इतने तीखे हो गए हैं कि उसे रोक पाना अकेले अमेरिका के बूते की बात नहीं रह गई है। भारत जैसे मित्रों को साधकर ही अमेरिका चीन पर दबाव बना सकता है। बाइडन प्रशासन इसी को ध्यान में रखकर पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के उलट बहुपक्षीय और व्यापक दृष्टिकोण वाले क्षेत्रीय राजनयिक दांव चल रहा है।

जिस समय ब्लिंकन भारत में होंगे उसी दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री लायड आस्टिन सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस का दौरा करेंगे। 'हिंद-प्रशांत की साझा दृष्टि' पर विचार-विमर्श ब्लिंकन की प्राथमिकता में होगा। वहीं लायड वियतनाम, फिलीपींस, जापान और ताइवान जैसे उन देशों को आश्वस्त करने पर ध्यान देंगे, जो चीन की दबंगई से परेशान हैं। चीन इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत से आक्रामकता दिखा रहा है। इतना ही नहीं म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल जैसे छोटे देशों को कर्ज जाल में फंसाकर बेल्ट एंड रोड परियोजना को साकार कर रहा है। चीन की इसी आक्रामकता को जवाब देने के लिए अमेरिका-भारत, जापान और आस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है। भारत ने भी हाल में यूरोपीय संघ के साथ 'व्यापक साझेदारी' की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। बाइडन प्रशासन भी यूरोपीय देशों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। स्पष्ट है कि क्वाड देश अपने संसाधनों को समन्वित कर एकीकृत रूप से काम करें और साथ में यूरोप को भी जोड़ लें तो चीनी दबदबे की हवा निकालना आसान हो जाएगा। वास्तव में चीन जैसी कठिन चुनौती का जवाब एक बहुपक्षीय वैश्विक गठबंधन द्वारा ही दिया जा सकता है।

चीनी चुनौती की काट भारत-अमेरिका रिश्तों का एक दीर्घकालीन मुद्दा है, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान पर ध्यान दिया जाना कहीं अधिक आवश्यक है। अमेरिकी फौजों की वापसी से पहले कई अफगान इलाकों पर तालिबानी कब्जे ने चिंता बढ़ाई है। भारतीय हितों के लिहाज से जरूरी है कि अफगानिस्तान पुनः आतंक और अराजकता का गढ़ न बनने पाए। हिंद-प्रशांत क्षेत्र की तरह यहां भी भारत-अमेरिकी हित जुड़े हुए हैं। दोनों को अफगान धरती से निकलते जिहादी विष की काट तलाशनी ही होगी। अमेरिका यह भी ध्यान रखे कि उसकी फौजों की वापसी के बाद उसके लिए अपने पश्चिम एशियाई सैन्य ठिकानों से अफगानिस्तान को समय पर मदद उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा। इधर भारत भले ही तालिबान के साथ वार्ता की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन उस पर पाकिस्तानी छाप के चलते वह तालिबान को लेकर आश्वस्त नहीं रह सकता। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना को यदि अन्य देशों से कुछ मदद मिले तो अफगानिस्तान में आसन्न खतरे से निपटा जा सकता है।

एक वक्त था जब भारत भू-राजनीति के अखाड़े में संकोच और अनिर्णय का शिकार हुआ करता था। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद यह झिझक टूटी है। अब भारतीय हितों की पूर्ति के लिए साहसिक फैसले लेने से परहेज नहीं किया जाता। अमेरिका भी भारत के इन बदलते तेवरों पर गौर कर निर्णायक कदम उठाए। इसमें अमेरिका जितना रचनात्मक होगा उतना ही उसे लाभ होगा। अमेरिका यह न भूले कि चीन और अफगानिस्तान दोनों मोर्चे कठिन हैं, जिन्हें भारत के साथ से ही साधा जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भारत और अमेरिका की जोड़ी अहम हो गई है।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर एवं डीन हैं)

response@jagran.com

खुद को कमजोर साबित करता विपक्ष



राजीव सचान

विपक्ष को दीनहीन बता उसकी कमजोरी ही छिपाई जा रही है। विपक्ष कमजोर नहीं, बल्कि बिखरा हुआ और दिशाहीन है



संसद में हंगामे पर अब नहीं होती हैरानी। फाइल

संसद का मानसून सत्र चलने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि विपक्ष पेगासस जासूसी मामले की जांच कराने और तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आक्रामक मुद्रा में है। इसी मुद्रा के चलते वह न तो लोकसभा चलने दे रहा है और न ही राज्यसभा। ये दोनों ही मसले ऐसे नहीं जिन पर संसद में बहस नहीं हो सकती। बहस के दौरान विपक्ष अपने तर्कों से सत्तापक्ष को निरुत्तर कर सकता है-ठीक वैसे ही जैसे राज्यसभा में कोरोना पर बहस के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने अपने भावुक और प्रभावी संबोधन से किया। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकारों की नाकामी और आम आदमी की बेबसी को जिस तरह बयान किया, उसने सभी को प्रभावित किया। आखिर संसद में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर ऐसे ही भाषण क्यों नहीं हो सकते, जो सरकार के साथ आम आदमी को सोचने के लिए बाध्य करें? यह वह सवाल है, जो विपक्ष को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि वही है, जो संसद को चलने नहीं दे रहा है। मनोज झा के संबोधन ने यह रेखांकित किया कि विपक्ष तार्किक हो तो उसका संख्याबल मायने नहीं रहता।

एक अर्से से और खासकर 2014 के बाद से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष कमजोर है और इसी कारण वह प्रभावी नहीं साबित हो पा रहा है। यह एक मिथ्या धारणा है। यदि किसी एक दल या गठबंधन की सरकार बहुमत हासिल कर ले तो इसका यह मतलब नहीं होता कि विपक्ष कमजोर हो गया है। 2014 और 2019 में मोदी के नेतृत्व में राजग ने बहुमत अवश्य हासिल किया, लेकिन वैसा नहीं जैसा राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1984 के चुनाव में हासिल किया था। उन्होंने चार सौ से अधिक सीटें हासिल की थीं। तब विपक्ष के दिग्गज नेता तक चुनाव हार गए थे और उसका संख्याबल भी सिमट गया था। आज यह स्थिति नहीं है।

विपक्ष का संख्याबल कमजोर नहीं कहा जा सकता-न लोकसभा में और न ही राज्यसभा में। सच तो यह है कि मोदी सरकार राज्यसभा में अभी भी बहुमत से दूर है। आखिर इस स्थिति में विपक्ष को कमजोर बताने का क्या मतलब? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मिथ्या धारणा का बंधक बनकर रह गया है कि वह कमजोर है। विडंबना यह है कि इस धारणा को बनाने का काम खुद विपक्ष ने यह कहकर किया है कि मोदी सरकार बहुमत के बल पर मनमानी कर रही है। जिसे विपक्ष सत्तापक्ष की मनमानी बताता है, वह दरअसल सरकार का संसदीय कौशल है। इसी कौशल के कारण राज्यसभा से ऐसे भी अनेक विधेयक पारित हो गए, जिन पर विपक्ष को आपत्ति थी। ये विधेयक इसलिए पारित हो गए, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था या फिर उसने तार्किक रवैये का परिचय नहीं दिया। वह राज्यसभा में अक्सर ऐसा व्यवहार करता रहा जैसे उसे लोकसभा की गलतियों को ठीक करने का अधिकार मिल गया है। वह यह भी आभास कराता रहा कि देश की जनता ने मोदी सरकार को बहुमत देकर गलती कर दी है और इस गलती को सुधारने का दायित्व उस पर आ गया है। जब कभी वह ऐसा करने में नाकाम रहा तब उसने यह रोना रोया कि सरकार बहुमत के बल पर अपनी ही चला रही है। इसी के साथ यह मिथ्या धारणा बनाई जाने लगी कि विपक्ष तो कमजोर है।

विपक्ष को बेवजह दीनहीन बताकर एक तरह से उसकी कमजोरी को ही ढका जा रहा है। विपक्ष कमजोर नहीं, बिखरा हुआ और दिशाहीन अवश्य है। इसी सत्र को देखें तो विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि उसे किन मसलों पर एकजुट होना चाहिए। कुछ दल कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरना चाहते हैं तो कुछ पेगासस जासूसी मामले को लेकर। कई बार एक ही समय संसद में एक से अधिक मुद्दों पर हंगामा हो रहा होता है। अपने बिखराव पर विपक्ष खुद ही लगाम लगा सकता है। उसे केवल अपना बिखराव और अपनी दिशाहीनता को ही नहीं रोकना है, बल्कि तार्किक रवैया भी अपनाना है। आखिर इस बात का क्या मतलब कि जो कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थगित किए जा चुके हैं, उन पर संसद के भीतर और बाहर हंगामा मचाया जाए? कृषि कानूनों पर हंगामा मचाने वालों में सबसे आगे वह कांग्रेस है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव के अवसर पर जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में वैसे ही कानून बनाने का वादा किया था जैसे मोदी सरकार ने बनाए हैं। हालांकि सरकार इन कानूनों में संशोधन को तैयार है, लेकिन विपक्ष इन कानूनों को रद करने की वैसी ही अतार्किक मांग कर रहा है, जैसी किसान संगठन कर रहे हैं।

आखिर इस बात का क्या तुक कि विपक्ष किसी मसले पर चर्चा के लिए नोटिस भी दे और सदन में नारेबाजी भी करे? वह जितनी मेहनत किसी मसले पर चर्चा के लिए नोटिस देने में करता है, उससे अधिक विभिन्न मसलों पर नारेबाजी के लिए तख्तियां बनाने और उन्हें सदन में लहराने के लिए करता है। न जाने कितने सांसद ऐसे हैं जो अपनी सारी ऊर्जा इसी में खपा देते हैं कि उनकी तख्ती लोकसभा या राज्यसभा टीवी के कैमरे में कैद हो जाए। कैमरे इससे बचते हैं। इसीलिए जनता को वह बेहूदा दृश्य देखने को नहीं मिला जब तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ रहे थे।

संसद में हंगामा मचाने के प्रति विपक्ष की अतिरिक्त दिलचस्पी से यही लगता है कि उसका मकसद सदन की कार्यवाही ठप कराना होता है। निःसंदेह वह अपने इस मकसद में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे यह कभी नहीं लगता कि वह एक मजबूत विपक्ष है। वह जमाना बीत गया जब सदन की कार्यवाही बाधित होना बड़ी खबर बनती थी। ऐसी खबरें अब जनता का ध्यान भी मुश्किल से ही आकर्षित करती हैं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विवेक की शक्ति

मानव जीवन में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। ये कर्म मानव की विवेक शक्ति से ही संचालित होते हैं। सांसारिक जीवन में सामान्यजन जब अपने विवेक रूपी धर्म के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके आत्मा का पतन होता है। गलती के बाद जब मन धिक्कारता है तो आत्मग्लानि भी होती है। व्यक्ति का मन मति रूपी जननी के गर्भ में जाता है तो कुछ दिनों तक वह व्यक्ति आंतरिक पश्चाताप करता है, परंतु यह पश्चाताप ज्यादा दिन नहीं टिक पाता तो फिर गलतियों को दोहरा बैठता है। अपमान, दुत्कार, स्वाभिमान गिरवी रखकर मिली उपलब्धि व्यक्ति को भीतर ही भीतर खोखला और कमजोर करती है। मति की गति सकारात्मक है तो जीवन आनंदमय रहता है। वहीं विवेक नष्ट पर जो कदम उठते हैं वे अपमान और श्मशान की ओर ही ले जाते हैं।

महाभारत युद्ध के दौरान विवेक रूपी कृष्ण पंच ज्ञानेंद्रियों के स्वरूप पांडवों की रक्षा करते हैं। इसीलिए निंदनीय कर्म रूपी कौरव पांडवों के आगे घुटने टेकते हैं। व्यक्ति की मति ही व्यक्ति के जीवन गति को निर्धारित करती है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा और फिर उसी अनुरूप जीवन होगा। यहां अन्न का आशय खाद्य पदार्थ से न होकर सद्विचार और सात्विक चिंतन से लिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन पर उसके रहन-सहन, चिंतन-मनन और परिवेश आदि का पूरा प्रभाव पड़ता है।

आत्मा की कोई अद्भुत शक्ति और वजन तो है ही कि जब शरीर में आत्मा रहती है तो व्यक्ति पानी मे डूब जाता है और आत्मा निकल जाने के बाद पार्थिव शरीर डूबने के बजाय तैरता है। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हर व्यक्ति के जीवन में वैचारिक और मानसिक धरातल पर जन्म-मरण का चक्र चलता रहता है। व्यक्ति को इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए अपने विवेक और आत्मबल को खूब मजबूत बनाना चाहिए। उसी से आत्मा और शरीर के साथ समग्र व्यक्तित्व को शक्ति मिलेगी।

सलिल पांडेय

प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की स्थिति

सुधीर कुमार

अभी देश के केवल 22 फीसद स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जिसे बढ़ाना ही होगा

देश के स्कूलों में प्रौद्योगिकी संचालित शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश के केवल 38.54 फीसद स्कूलों में ही कंप्यूटर उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश के महज 13.59, मेघालय के 13.63, बंगाल के 13.87, बिहार के 14.19 और असम के 15 फीसद स्कूलों में ही कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध है। वहीं स्कूलों में इंटरनेट उपलब्धता के मामले में स्थिति और भी बुरी है। देश के केवल 22 फीसद स्कूलों में ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। वहीं केरल और दिल्ली के स्कूलों में क्रमशः 88 और 86 फीसद स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन दूसरी ओर त्रिपुरा में महज 3.85, मेघालय में 3.88 और असम में 5.82 फीसद स्कूलों में ही इंटरनेट कनेक्शन है। जाहिर है, तकनीकी शिक्षा और संचार की आधुनिकतम तकनीक से हमारे विद्यार्थी आज भी बहुत दूर हैं।

भविष्य की पढ़ाई के लिए तकनीकी साक्षरता और इंटरनेट कनेक्टिविटी दो अहम जरूरतें हैं। महामारी के कारण दुनियाभर में स्कूली शिक्षा बाधित हुई है। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया के 190 से भी अधिक देशों को स्कूलों के दरवाजे बंद करने पड़े। इसके बाद विकल्प के रूप में आनलाइन शिक्षा का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, लेकिन चिंता की बात है कि इस तरह की शिक्षा की पहुंच सभी तक नहीं हो पाई।

स्कूलों के बंद रहने से विश्व में 1.6 अरब स्कूली बच्चों में से केवल 10 करोड़ बच्चों की ही शिक्षा बाधित नहीं हुई। घर पर तकनीक की सुलभता की वजह से उनकी पढ़ाई में निरंतरता कायम है। इन बच्चों के लिए तकनीक ने घर और स्कूल की दूरी को पाटने का काम किया। तकनीक के जरिये बच्चे रोजाना कक्षाओं में शामिल होकर अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आनलाइन शिक्षा की पहुंच से दूर लाखों ग्रामीण बच्चों का भविष्य अधर में है। स्मार्टफोन की अनुपलब्धता और धीमे इंटरनेट ने उनके भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है।

देश के सरकारी स्कूलों में आनलाइन शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित होते हैं। उनके पास न तो स्मार्टफोन की सुविधा होती है और न ही इंटरनेट पैक खरीदने की हैसियत। ऐसे लाखों बच्चे चाहकर भी आनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने का दुष्परिणाम यह होगा कि इनमें से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के वे बच्चे जिनके पास संसाधनों का घोर अभाव है, वे आनलाइन शिक्षा के दौर में अपने सहपाठी से पिछड़ जाएंगे। पिछले डेढ़ साल से स्कूल बंद होने से बच्चों के पढ़ाई का क्रम टूटा है। जब स्कूल दोबारा खुलेंगे तो स्वाभाविक है कि कई बच्चों के लिए पढ़ाई में पुनः उसी प्रकार जुटना आसान नहीं होगा। ऐसे में सरकार को इन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए।

(लेखक बीएचयू में शोध अध्येता हैं)

मेलबाक्स

मध्यमार्ग ही समय की मांग

संपादकीय पेज पर प्रकाशित 'देश को चाहिए मुफ्तखोरी से मुक्ति' शीर्षक से लिखे आलेख में भरत झुनझुनवाला ने कई विचारणीय बिंदुओं पर प्रकाश डाला। पात्रता-आवंटन बनाम सशक्तीकरण को लेकर जारी बहस में लेखक ने भारत के संदर्भ में कई उदाहरण गिनाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जो खैरात बांटने की एक नई परिपाटी शुरू हो गई, जिसे अब मतदाताओं की ओर से एक मान्यता भी मिलती जा रही है, वह न केवल आम जन को अकर्मण्य बनाती है, बल्कि सरकारी खजाने को भी चोट पहुंचाती है। लेखक ने उचित ही कहा कि कुछ सरकारी खैरातों से निजी लाभ अवश्य हो सकता है, लेकिन उससे सार्वजनिक शुभ की अपेक्षित प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। याद रहे कि कोई भी सरकार चाहे किसी भी दल ही क्यों न हो, वह अपने पार्टी के कोष से नहीं, अपितु सरकारी खजाने से ही खैरात लुटाती है। यह भी सत्य है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और सरकारी खजाने की अपनी सीमा है। ऐसे में या तो उसका उपयोग समग्र विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए कर लिया जाए या फिर लोगों को निजी लाभ देने में, जो व्यापक रूप से अनुत्पादक होता है, उसमें लगा दिया जाए। मतदाताओं को भी इस पूरे गणित को समझकर परिपक्वता का परिचय देना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों द्वारा अपनाई जा रही ऐसी अस्वस्थ परंपरा पर विराम लगे। हालांकि भारतीय संदर्भ में लेखक का यह तर्क संदिग्ध लगता है कि सरकार लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें नकदी मुहैया कराए। ऐसा इसलिए, क्योंकि इससे उपलब्ध कराए गए धन के दुरुपयोग का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसलिए इसमें मध्यमार्ग ही श्रेयस्कर होगा। यानी सरकार जनता को खैरात की आदत न लगाए, लेकिन उनकी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करे, क्योंकि पात्रता की संकल्पना को रातोंरात सशक्तीकरण में रूपांतरित नहीं किया जा सकता।

जयंत मिश्रा, लखनऊ

राजनीति में समय बहुत बलवान

यह पत्र 'विपक्षी एका का भविष्य' के संदर्भ में है। विपक्षी दलों को यह अहसास हो गया है कि कांग्रेस देश के कुछ गिने चुनें राज्यों को छोड़कर अब बिल्कुल किनारे पर लग चुकी है और विशेषकर जिस तरह से नेतृत्व के मुद्दे पर पार्टी में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उससे कांग्रेस को दरकिनार करके अलग धड़ा बनाना ही एकमात्र विकल्प रह गया है। जिस तरह ममता बनर्जी ने भाजपा को शिकस्त दी है तो ऐसे में उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्हीं के आसपास समूचा विपक्ष घूमेगा और उनके नाम से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि यह इतना आसान होने वाला नहीं है, जितना आज की तारीख में लगता है। जैसा विदित है कि जिस तरह अचानक से राजनीतिक समीकरण बनते और बिगड़ते हैं तो कांग्रेस को बिना साथ लिए किसी भी समूह को कितनी सफलता मिलेगी, यह एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी अपने आप में एक बड़ी कद्दावर नेता हो सकती हैं, लेकिन क्या उनकी देशभर में एक राष्ट्रीय नेता की छवि है तो इस सवाल का जवाब नहीं ही होगा। और क्या कांग्रेस को किसी अन्य पार्टी का नेतृत्व स्वीकार होगा? अब भी अगला आम चुनाव लगभग तीन साल दूर है और इतना समय राजनीति में बहुत बड़ा समय होता है। इस बीच बहुत कुछ उलट-पलट संभव है।

बाल गोविंद, नोएडा

चौटाला से दुर्व्यवहार अनुचित

'अक्षम्य अपराध' शीर्षक से लिखे संपादकीय में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के साथ कृषि कानून विरोधी किसान धरनास्थल पर हुए दुर्व्यवहार की विवेचना की गई है। चौटाला को आंदोलन स्थल पर जाने से रोका जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह तो एक वयोवृद्ध नेता का अपमान है। चौटाला का कथन है कि वह तो राम-राम करने गए थे। आंदोलनकारी किसान नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि यदि चौटाला मंच पर जाकर राम-राम कर लेते तो कौन सा पहाड़ टूट जाता।

रणजीत वर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

107 मामले दर्ज किए गए पिछले पांच वर्षों के दौरान काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्तियां) और कर अधिनियम आरोपण, 2015 के तहत। यह जानकारी लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में दी।

डिजिटल मुद्रा

समय के साथ ताल मिलाने की जरूरत



संजय वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का एक प्रस्ताव पेश करते हुए बताया गया है कि इससे देश में नोट छापने का खर्च बचेगा और नकदी पर लोगों की निर्भरता घटेगी। देखा जाए तो अब भारत सहित विभिन्न देशों और उनके केंद्रीय बैंकों के लिए डिजिटल के साथ-साथ वर्चुअल या कहें कि क्रिप्टो करेंसी पर काम करने का वक्त आ गया है। अगर नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा डिजिटल हो गया तो नकली मुद्रा से लेकर आतंकवाद के आर्थिक पोषण और रिश्वतखोरी एवं बेनामी लेन-देन पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा। फिर भी कुछ सावधानियां बरतना आवश्यक है



रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल करेंसी के रूप में ई-रुपया का आइडिया पेश किया है। प्रतीकात्मक

जिस वक्त देश-दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर हो रखी हो और घटती कमाई के चलते आम जनता का हाल बेहाल हो, उस दौर में रुपये-पैसे की कोई चर्चा सुहावनी ही लगती है। ऐसी बातें सुनकर लगता है कि शायद सरकारों, उनकी आर्थिक संस्थाओं और पूंजीपतियों को कोरोना से त्रस्त लोगों का कोई ख्याल आया है। पर इधर जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की ओर से रुपये के इलेक्ट्रानिक चेहरे संबंधी एक प्रारूप की बात कही गई तो मन में सवाल पैदा हुआ कि इसका आम जनता की तकलीफों से भला क्या लेना-देना है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) का एक प्रस्ताव पेश करते हुए बताया गया है कि इससे देश में नोट छापने का खर्च बचेगा और नकदी (कैश) पर लोगों की निर्भरता घटेगी। नकली नोटों से जूझती अर्थव्यवस्था और बैंकिंग एवं भुगतान के तमाम डिजिटल उपायों में साइबर लुटेरों की सेंधमारी की हजारों घटनाओं के बीच रिजर्व बैंक के इस विचार पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो अब विभिन्न देशों और उनके केंद्रीय बैंकों के लिए डिजिटल के साथ-साथ वर्चुअल या कहें कि क्रिप्टो करेंसी पर काम करने का वक्त आ गया है।

यह कोरोना काल की विवशता है कि दुनिया भर में लोगों को अपना ज्यादातर कामकाज घर बैठे संपन्न करना पड़ा है। इसमें दफ्तरी कामकाज से लेकर कंपनियों की गतिविधियां, बैंकिंग, पढ़ाई और खरीदारी तक-सभी कुछ शामिल हैं। हालांकि बैंकिंग और खरीदारी जैसी आर्थिक गतिविधियां काफी पहले आनलाइन हो चुकी हैं, लेकिन इधर इनमें कई गुना तेजी आई है। इसके साथ ही साइबर सेंधमारी और लोगों के रुपये-पैसे आनलाइन चुराने की घटनाओं में भी भारी इजाफा हुआ है। इस विडंबना पर चाहें तो हम सिर धुन सकते हैं कि हमारे ही देश में लाखों लोग मजबूरी के चलते या फिर सुविधा की चाह में आर्थिक लेन-देन की जिस आनलाइन व्यवस्था से जुड़े, वहां उन्हें साइबर सेंधमारी से दो-चार होना पड़ा। कभी किसी के खाते से जमा रकम अचानक उड़ जाती है तो कभी एटीएम कार्ड की क्लोनिंग से उन्हें चूना लगा दिया जाता है। इस मामले में सरकारी और निजी, दोनों तरह की बैंकिंग व्यवस्थाएं उन्हें कोई खास दिलासा नहीं दे पाई हैं। यही नहीं, जब देश में पेटीएम, मोबीक्विक, अमेजन-पे और गूगल-पे जैसे निजी इंतजाम धड़ल्ले से भुगतान का प्रबंध कर रहे हैं, तब भी सरकार अपनी ओर से फूलप्रूफ आनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाने में हिचकती रही है। इसके अलावा दुनिया में बिटकाइन से लेकर डोजकाइन तक की क्रिप्टो करेंसियां चलन में आ चुकी हैं। हमारे देश में भी तमाम लोगों ने सरकारी बंदिशों के बावजूद इनमें निवेश कर रखा है और बीच के अरसे में इनके जरिये खूब चांदी कूटी है, लेकिन सरकार को इनका महत्व समझने और इसके मजबूत विकल्प तैयार करने में उलझन महसूस होती रही है। ऐसे में, अब जबकि रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल करेंसी के रूप में ई-रुपया यानी सीबीडीसी का आइडिया पेश किया है तब कह सकते हैं कि उसका यह कदम देर आयद-दुरुस्त आयद वाला है।

मुश्किल को आसान करे डिजिटल : लेकिन यह डिजिटल करेंसी क्या है और यह बिटकाइन जैसी वर्चुअल यानी क्रिप्टो करेंसी से कितनी अलग है? मोटे तौर पर यह रुपये का इलेक्ट्रानिक रूप होगा। यह व्यवस्था उसी तरह काम करेगी, जिस तरह मौजूदा पेटीएम आदि आनलाइन पेमेंट सिस्टम काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसे बरतने वाले लोग अपने स्मार्टफोन से ही ई-रुपये में भुगतान कर सकेंगे या पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि दुनिया में ऐसी पहली डिजिटल करेंसी चलाने का श्रेय बहामास को मिला है। वहां पिछले वर्ष यानी अक्टूबर 2020 में दुनिया की पहली सरकारी डिजिटल करेंसी लांच की गई थी। एक आकलन कहता है कि दुनिया के 86 प्रतिशत सरकारी बैंक इस समय डिजिटल करेंसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ताकि उनके यहां ऐसी मुद्रा लाई जा सके। दुनिया के करीब 14 प्रतिशत सरकारी बैंकों ने इसके लिए बाकायदा पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस सूची में शामिल है। चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी ई-युआन संबंधी पायलट प्रोजेक्ट 2020 में ही लांच कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब इसके बारे में काम शुरू करने की जरूरत इस आधार पर बताई है कि इससे तमाम मुश्किलें पैदा करने वाली नकदी पर लोगों की निर्भरता घटेगी। साथ में नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई पर होने वाला वह भारी-भरकम खर्च भी बचेगा, जो दिनोंदिन महंगा होता जा रहा है। कुछ और फायदे भी रिजर्व बैंक ने बताए हैं। जैसे-डिजिटल करेंसी के चलन में आने से नकद लेन-देन के सेटलमेंट में आसानी होगी। विदेशी मुद्रा के लेन-देन के मामले में टाइम जोन (मिसाल के तौर पर अमेरिका और भारत के वक्त में अंतर होने की स्थितियों में) अलग होने के बावजूद सेटलमेंट में कोई देरी नहीं होगी। हम अभी कागजी नोटों और धातुओं के सिक्कों पर टिकी अर्थव्यवस्था के पूरी तरह डिजिटल हो जाने की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय है कि अगर नकदी पर आधारित अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा डिजिटल हो गया तो नकली मुद्रा से लेकर आतंकवाद के आर्थिक पोषण और रिश्वतखोरी एवं बेनामी लेन-देन पर काफी हद तक अंकुश लग जाएगा।

निवेश का नया जरिया : यूं कागज और सिक्कों पर आधारित अर्थव्यवस्था में करेंसी के रूप-रंग को लेकर कई बदलाव पिछले दशकों में हुए हैं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के वजूद में आने पर हाथ में नकदी लेकर चलने की मजबूरी खत्म हो चुकी है। इसके अलावा प्रायः सभी बैंकों ने नेट-बैंकिंग की सुविधा अपने ग्राहकों को दे रखी है। हालांकि इसमें कई सुरक्षात्मक प्रविधान हैं। इसके लिए खाताधारकों को इंटरनेट से परिचित होना और नेट बैंकिंग के कायदों की जानकारी होना भी जरूरी है। ऐसे में आम खाताधारक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके मुकाबले आनलाइन पेमेंट गेटवे (सिस्टम) ज्यादा सुविधाजनक साबित हुए हैं। जैसे कि पेटीएम और गूगल-पे इत्यादि, लेकिन इनका इस्तेमाल भी मोबाइल इंटरनेट रखने वाले और अक्सर शहरी लोग ही कर पाते हैं। गांव-देहात में इनका प्रयोग बहुत सीमित है, लेकिन उपयोग से परे एक मुद्दा करेंसी (मुद्रा) के संचालन, रखरखाव और उनमें निवेश का भी है। यदि किसी मुद्रा में लेन-देन आसान है, उसके रखरखाव में किसी किस्म की धांधली की गुंजाइश नहीं है और उसमें निवेश का भी एक पहलू शामिल है-तो ऐसी मुद्रा की मांग स्वतः बढ़ जाती है। बिटकाइन जैसी क्रिप्टो या कहें कि वर्चुअल करेंसियों ने साबित किया है कि यदि उन्हें खरीद लिया जाए तो वे किसी शेयर या सोने में किए गए निवेश जैसी साबित हो सकती हैं। यह एक अपेक्षाकृत नई बात है, लेकिन सट्टेबाजी, मनीलांड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों और आतंकवाद के पोषण (टेरर फंडिंग) में इनके इस्तेमाल की गुंजाइश को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में वर्ष 2018 में ही क्रिप्टो करेंसी में लेन-देन को गैरकानूनी घोषित कर दिया था।

हालांकि बिटकाइन और डोजकाइन आदि मुद्राओं की खरीद-फरोख्त हमारे देश में छिटपुट तौर पर जारी है, लेकिन केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए भारत में इनका भविष्य तब तक अनिश्चित माना जा सकता है, जब तक कि खुद सरकार ऐसी मुद्रा नहीं ले आती है। कुछ वर्ष पहले भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बिटकाइन की तर्ज पर लक्ष्मीकाइन जारी करने की संभावना पर विचार किया गया था, लेकिन क्रिप्टो यानी कंप्यूटर पर सृजित मुद्राओं के खतरों को भांपते हुए इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया। इधर तो केंद्र ने वर्चुअल करेंसी पर पाबंदी लगाने का एक विधेयक भी तैयार किया है, जिसे इसी मानसून सत्र में पास कराने की तैयारी है।

क्रिप्टो करेंसी भी आवश्यक

बेशक सरकार को जाली करेंसी, साइबर धोखाधड़ी और ब्लैकमनी जैसी चीजों पर रोक लगाने के प्रबंध करने ही चाहिए। पर उसे दुनिया की चाल पर भी निगाह रखनी चाहिए। आज अगर सरकार ई-रुपये यानी डिजिटल करेंसी पर सहमत हो रही है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि एलन मस्क जैसे कारोबारी अपनी कंपनी-टेस्ला की कारों की खरीद-फरोख्त में बिटकाइन को स्वीकार करने को तैयार हैं।

वहीं कई देश हैं, जो अब धीरे-धीरे वर्चुअल करेंसी को मान्यता देने लगे हैं। यही नहीं, अब तक जिन देशों के पास तेल और अमेरिकी डालर जैसी विदेशी मुद्रा के बड़े भंडार होते थे, वे अमीर माने जाते थे। पर पिछले कुछ अरसे से यह मिथक टूटता लग रहा है। इसे असल में अब आभासी मुद्रा (डिजिटल, क्रिप्टो या वर्चुअल करेंसी) से चुनौती मिल रही है, जो 'क्रिप्टोमाइनिंग' तकनीक से पूरे विश्व में फैलती जा रही है।

आज की तारीख में बिटकाइन पर भी कुछ देशों में पाबंदी है, परंतु उसका कामकाज अभी भी जारी है, बल्कि उसकी जितनी कीमत दुनिया की किसी अन्य मुद्रा की नहीं है। दुनिया में जितनी भी मुद्राएं (करेंसी नोट आदि) हैं, उन पर किसी न किसी बैंक या सरकार का नियंत्रण है। बैंकों और सरकारों की साख और अर्थव्यवस्था की ताकत के हिसाब से उनकी मुद्राओं का मूल्य तय होता है। पर वर्चुअल यानी क्रिप्टो करेंसी इन सारे नियम-कानूनों से परे हैं। इन्हें न तो हकीकत में कागज या सिक्कों के रूप में मुद्रित किया अथवा ढाला जाता है और न ही इन पर किसी बैंक या सरकार का हक होता है। ऐसे में केंद्र सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि डिजिटल करेंसी की तरह ही वह बिटकाइन की तरह अपनी एक क्रिप्टो करेंसी भी तैयार करे।

लक्ष्मीकाइन के रूप में इसका एक विचार कुछ वर्ष पहले आ भी चुका है। कोशिश की जाए कि वह वर्चुअल करेंसी बिटकाइन जैसी सनसनी भले न पैदा करे, लेकिन वित्तीय लेन-देन का सुरक्षित, त्वरित और आसान तरीका जरूर बन सके। बात चाहे डिजिटल करेंसी की हो या वर्चुअल करेंसी की, मोबाइल-इंटरनेट से आसान भुगतान का एक विकल्प जनता को देना एक अच्छी पहलकदमी हो सकती है।

इन मुद्राओं के लेन-देन को सुरक्षित करने और इनमें लगी आम जनता की रकम को महफूज रखने की जो भी चुनौतियां हैं, उनसे उबरने के नए रास्ते खोजने ही होंगे, क्योंकि ये बदलते वक्त की मुद्राएं हैं। आगे का जमाना इन्हीं का है। अच्छा है कि अभी से इन्हें सावधानीपूर्वक बरतने के इंतजाम कर लिए जाएं।

खरी-खरी

मिलना एक शदीद पाठक का

प्रभाशंकर उपाध्याय

मैंने उसे सामानों की एक सूची पकड़ाई। उसने सूची को अपने काउंटर पर रखते हुए कहा-आपकी किताब हमें भी दीजिए पढ़ने के लिए। वह परचून का व्यापारी है और बीसियों बरस से मेरा सामान उसकी दुकान से ही आता रहा है। मैंने हैरत से पूछा-मेरी किताब पढ़ोगे तुम? तुम्हें तो सुबह से लेकर देर रात तक दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती। मेरा प्रश्न सुन वह मुस्कुराया-बाबूजी, मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, बाद में इस धंधे में कुछ ऐसा फंसा कि सब छूट गया, लेकिन अब जब आपकी किताब आई है तो उसे जरूर पढूंगा। कुछ दिन पूर्व मेरे व्यंग्य संग्रह के लोकार्पण का समाचार स्थानीय अखबारों में प्रकाशित हुआ। मुझे लगा कि उस समाचार को पढ़कर ही वह भावनाओं के वेग में बहा जा रहा है। सो यह कहकर बात टाल दी कि अगली बार जब सामान लेने आऊंगा तो किताब साथ अवश्य लाऊंगा, लेकिन जब उसने अगली बार दुकान की पेढ़ी चढ़ते ही किताब के बारे में पूछ लिया तो मैं समझ गया कि उसका वह ज्वार उतरा न था। मैंने फिर टाला-इस बार याद नहीं रहा।

उसके बाद मैं दो बार उसकी दुकान पर और गया। उसने हर बार तगादा किया और मैंने फिर भूल जाने का बहाना बनाया। आखिरकार एक दिन मैं पुस्तक समेत उसके सामने उपस्थित था। उसे पुस्तक देते वक्त मैंने आगाह किया-किसी को देना नहीं। मैं वापस लेने आऊंगा। वह बोला-चिंता न कीजिए। इसे तो मैं दिल-ओ-जान से संभाल कर रखूंगा। दिल और जान जैसे शब्द सुनकर मुझे भी आश्वस्ति हुई कि बंदे को साहित्यिक रुचि तो है, अतः पढ़ेगा जरूर। दो माह बीत गए। न उसने किताब के बारे में जिक्र किया और न मैंने पूछा। तीसरे मास मैंने खुद ही पूछ लिया-पढ़ ली किताब? जनाब बोले-नहीं, अभी तो आधी ही पढ़ी है। फिर एक महीना और गुजरा। एक दिन उसने मेरी किताब लौटा दी। मैंने पूछा-कैसी लगी यह किताब? उसने कहा-अजी, क्या शानदार किताब लिखी है आपने। मैंने पुस्तक के पन्ने पलटे। दरअसल उस किताब को देने से पूर्व मैंने उसके कुछ पृष्ठ हल्के से चिपका दिए थे और वे सारे पृष्ठ जस के तस चिपके हुए थे।

ट्वीट-ट्वीट

पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे और अंत में वे चार लोग बस यही कहेंगे कि 'राम नाम सत्य है।'
अरुण गोविल@arungovil12

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम को त्रिपुरा के एक होटल में नजरबंद कर दिया गया है, जहां वे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए कुछ जमीनी कार्य करने गए थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये जमीनी काम असल में था क्या?
अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

येदियुरप्पा के इस्तीफे के साथ ही कर्नाटक में सत्ता के सुगम हस्तांतरण का मंच तैयार हो गया। यह वही शख्स हैं जिन्हें राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने का श्रेय जाता है। इससे यही लगता है कि भाजपा में पद नहीं पार्टी ही सर्वोपरि है।
राहुल शिवशंकर@RShivshankar



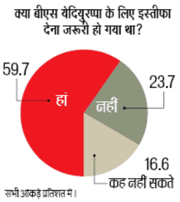
देश में जनसंख्या नीति को लेकर हो रही चर्चा के बीच इस तथ्य पर भी गौर किया जाए कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं को अधिक बच्चे पैदा करने के एवज में चर्च द्वारा नकदी प्रोत्साहन दिया जाता है। मेघालय से लेकर मिजोरम तक यही सिलसिला कायम है।
प्रो. शमिका रवि@ShamikaRavi

लहजे में बदजुबानी, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं...जिनके खुद के बहीखाते बिगड़े हैं...वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं।
अनुपम खेर@AnupamPKher

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या बीएस येदियुरप्पा के लिए इस्तीफा देना जरूरी हो गया था?



सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ममता बनर्जी विपक्षी एकता की धुरी बनने में सफल हो पाएंगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चुनकर भेजे आपने ऐसे हुल्लड़बाज,
संसद में आ बन गए वही कोढ़ में खाज।
वही कोढ़ में खाज लाज ना उनको आए,
हंगामा ही सिर्फ सदन में उनको भाए।
सोच रहे अब आप स्वयं अपना सिर धुनकर,
जाने कैसे लोग गए संसद में चुनकर।
- ओमप्रकाश तिवारी

हरियाणा डायरी

किसी के नहीं होते अराजक आंदोलनकारी



अनुराग अग्रवाल
स्टेट ब्यूरो चीफ, हरियाणा

अराजक तत्व कभी किसी के नहीं होते। तीनों कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले आठ माह से चल रहे आंदोलन में यह बात कई बार सच साबित हो चुकी है। इन आंदोलनकारियों ने हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके 87 साल के इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला को भी नहीं बख्शा। चौटाला कृषि कानूनों का विरोध कर रहे इन आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने जींद के खटकड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचे थे। वहां सतबीर पहलवान नाम के एक आदमी ने चौटाला पर उस समय पैर में डोगा (छड़ी) मारने का आरोप जड़ा जब चौटाला को बोलने के लिए माइक नहीं दिया गया। बुजुर्ग चौटाला डोगा मारने के आरोप से खासे आहत हैं। चौटाला के साथ दुर्व्यवहार की घटना उस स्थिति में हुई है जब उनके बेटे अभय सिंह चौटाला ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध करते हुए ऐलनाबाद विधानसभा सीट से त्यागपत्र दे रखा है। चौटाला ने यह कहकर मामले को ज्यादा तूल देना उचित नहीं समझा कि आंदोलन में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे तो कुछ माड़े। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। बुजुर्ग चौटाला के साथ हुए इस पूरे घटनाक्रम ने आंदोलन स्थलों पर बढ़ती जा रही अराजक लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना जरूरी कर दिया है।

टीकरी बार्डर से लेकर हरियाणा के आधा दर्जन से ज्यादा आंदोलन स्थल पर अमर्यादित आचरण की घटनाएं किसी से छिपी नहीं हैं। यह वही आंदोलन स्थल हैं, जहां पर मारपीट, दुष्कर्म और लड़ाई झगड़े की एक के बाद एक कई घटनाएं हो चुकी हैं। केंद्र एवं प्रदेश सरकार के संयम का ये आंदोलनकारी पिछले आठ माह से लाभ उठा रहे हैं, यूं कहिए कि अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। सरकार इन पर सिर्फ इसलिए ज्यादा सख्ती नहीं कर रही है, ताकि कहीं वे तिल का ताड़ न बना दें। भाजपा की इसी नरमी का फायदा आंदोलनकारी लंबे समय से उठा रहे हैं और किसी भी सत्तारूढ़ नेता के विरुद्ध नारेबाजी करने से लेकर उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ने और घेराव करने तक से नहीं चूक रहे हैं।



पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला अपने बेटे अभय चौटाला के चंडीगढ़ निवास पर। संजय घिल्डियाल

ओमप्रकाश चौटाला को माइक न देने की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चौटाला के साथ यह गलत आचरण उस स्थिति में किया गया, जब उन्होंने बार-बार कहा कि वह न तो मंच पर जाएंगे और न ही किसानों के बीच किसी तरह का भाषण देंगे, लेकिन माइक लेकर वह सिर्फ लोगों को राम-राम करना चाहते हैं। इस पर भी उन्हें माइक नहीं दिया गया। चौटाला जाते-जाते अपने साथ गाड़ी में रखे निजी माइक से लोगों को राम-राम बोल गए। किसान संगठनों से जुड़े ये आंदोलनकारी ताऊ देवीलाल, उनके बेटे ओमप्रकाश चौटाला और उनके भी बेटे अभय सिंह चौटाला के अपने प्रति भाव को समझ नहीं पाए। किसी भी समर्थन देने वाले व्यक्ति का ऐसा विरोध कहीं से वाजिब नहीं है। चौटाला पिछले दिनों गाजीपुर बार्डर पर भी गए थे। वहां उन्हें बड़े मंच पर भले ही न बैठाया गया हो, लेकिन राकेश टिकैत ने उन्हें पूरा सम्मान दिया। दूसरी तरफ ऐसे आंदोलनकारी भी हैं, जिनके अराजक होने की कोई सीमा नहीं है।

जींद के खटकड़ा टोल पर चौटाला और सतबीर पहलवान के बीच संवाद का जो वीडियो वायरल हुआ, वह सारी कहानी कह रहा है। चौटाला अपने पोते करण और सहायक के साथ खड़े हैं। शोर-शराबा चल रहा है। एक पतला-दुबला आदमी जिसका नाम सतबीर पहलवान बताया जाता है, वह बार-बार तुनक कर चौटाला पर हाथ फेंक रहा है। चौटाला उसे बात सुनने के लिए कहते हैं, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं होता। चौटाला माइक मांगते हैं। नहीं दिया जाता। कुछ घंटों के बाद सतबीर पहलवान का एक बयान आता है कि चौटाला ने उसके पैर में डोगा (छड़ी) मारी। इस घटनाक्रम का कोई न तो आडियो है और न ही वीडियो है। अगले दिन सतबीर पहलवान की कुछ राजनीतिज्ञों के साथ मंच साझा करते हुए फोटो वायरल होती है। यह फोटो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इस फोटो के आधार पर सतबीर पहलवान को कोई पुराना लोकदली, कोई जजपाई तो कोई कांग्रेसी बता रहा है। बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन आंदोलन में ऐसी अराजकता कतई उचित नहीं है।

पंजाब डायरी

विदेश की चाह में युवाओं ने पकड़ी गलत राह



इन्द्रप्रीत सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

पंजाब के बरनाला जिले के गांव कोठे गोबिंदपुरा के युवक लवप्रीत सिंह की खुदकुशी का मामला इन दिनों इतना सुर्खियों में है कि इसको लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तक को अपनी इमिग्रेशन पालिसी पर बयान देना पड़ा। मृतक लवप्रीत की सगाई 2018 में खुड्डी कलां निवासी बेअंत कौर से हुई थी। बेअंत कौर कनाडा चली गई थी। ससुराल पक्ष ने उसको कनाडा भेजने पर करीब 25 लाख रुपये खर्च किए थे। एक वर्ष उपरांत बेअंत कौर के कनाडा से वापस आने पर उसका लवप्रीत सिंह से विवाह हो गया। विवाह कर बेअंत कौर पुनः कनाडा चली गई। लवप्रीत सिंह को कनाडा बुलाने को लेकर वह टालमटोल करने लगी, जिस कारण लवप्रीत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा और आखिर 23 जून को अपने खेत में कीटनाशक दवा निगलकर खुदकुशी कर ली। अब विभिन्न सामाजिक संगठन बेअंत कौर को कनाडा से डिपोर्ट करवाने की मांग कर रहे हैं, जिसको भरपूर समर्थन मिल रहा है।

यह कोई पहला मामला नहीं है। जिस मानसिक पीड़ा से लवप्रीत गुजर रहा था, डेढ़ दशक पहले पंजाब की लड़कियां इसी मानसिक यातना का शिकार हो रही थीं, क्योंकि एनआरआइ दूल्हे पंजाब में लड़कियों के साथ शादी करते, उनसे अच्छी-खासी रकम दहेज के रूप में लेते और फिर उन्हें विदेश बुलाने के लिए टालमटोल करते रहते। सालों-साल लड़कियां यहां उनका इंतजार करती रहतीं। 2005 के आसपास ऐसे मामलों की बाढ़ आई हुई थी। आज समस्या वही है। बस प्रताड़ित होने वाले बदल गए हैं। इंटरनेशनल इंगलिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम यानी आइलेट्स करके विदेश जाने का ट्रेंड जबसे बढ़ा है तबसे लड़कियां इसका खूब फायदा उठा रही हैं। पंजाब के छोटे-छोटे शहरों तक में आइलेट्स सेंटर खुल गए हैं। जालंधर में ग्लोबल गुरु इमिग्रेशन सेंटर चलाने वाले रविंदर ग्रोवर बताते हैं कि आइलेट्स सेंटरों में पढ़ने वाले बच्चों में औसतन 65 फीसद लड़कियां हैं और 35 फीसद लड़के। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिन लड़कियों के अभिभावकों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर वे पढ़ने में ठीक हैं तो वे आइलेट्स कर लेती हैं। फिर उनके अभिभावक उन परिवारों की तलाश करते हैं, जो उनकी बेटी से शादी कर ले और फिर पढ़ाई व विदेश भेजने का सारा खर्च खुद उठा ले। ऐसी लड़कियों के साथ वे लड़के भी हवाई जहाज पकड़ लेते हैं, जो आइलेट्स में अच्छा नहीं कर पाए होते हैं। इनमें से कुछ बेअंत कौर जैसी होती हैं, जो विदेशी जमीन पर पैर रखते ही अपने पति से सारे ताल्लुक तोड़ लेती हैं।



लवप्रीत सिंह खुदकुशी मामले में रोष मार्च निकालकर उसकी पत्नी बेअंत कौर को कनाडा से प्रत्यर्पण कराने की मांग करते लोग। फाइल

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में अपनी इमिग्रेशन पालिसी में कोई सख्ती न बरतने की बात की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फ्राड तो लोगों के जागरूक होने पर ही रोके जा सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो के इमिग्रेशन नियमों को सख्त न करने के पीछे कारण और हैं। पिछले कुछ वर्षों से एक और बड़ा बदलाव देखने में आया है। पहले पंजाब से ग्रेजुएट होकर नौकरी की तलाश में युवा विदेश जाते थे। लेकिन अब बारहवीं के बाद ही स्टडी वीजा पर जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। यही कारण है कि पंजाब में डिग्री कालेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। हालांकि पंजाब से विदेश जाने का ट्रेंड नया नहीं है। पिछली सदी के आठवें दशक में वे लोग विदेश जाते थे जिनके पास खेती योग्य जमीनें नहीं थीं या फिर बहुत कम थीं। राज्य के दोआबा क्षेत्र से इसी कारण लोगों में विदेश जाने का ट्रेंड बहुत रहा। उन्हीं दिनों पंजाब में जमीनों का कंसोलिडेशन हुआ। तय हुआ कि 16 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रह सकेगी। बड़े-बड़े जागीरदारों से जमीनें लेकर भूमिहीन लोगों में भी बांटी गईं। अब पांच दशक बाद जब यही परिवार अपनी तीसरी पीढ़ी में प्रवेश कर गए हैं तो 16 एकड़ जमीन वाले लोगों के पास मात्र तीन से चार एकड़ जमीनें ही बची हैं, जो किसी भी तरह एक परिवार को पालने के लिए काफी नहीं हैं। लिहाजा नए मौकों की तलाश में हर परिवार अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता है, जरिया चाहे कोई भी हो। किसान परिवारों में जमीनें बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेजने के चलन के कारण ही फ्राड हो रहे हैं।

पिछले दिनों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के वाइस चेयरमैन एमपी पूनिया ने चंडीगढ़ में एक सेमिनार में कहा कि हमारी शिक्षा युवाओं को रोक नहीं पा रही है। रोजगार के अवसरों की कमी के चलते युवाओं का रुझान विदेश की ओर बढ़ रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र विभाग के पूर्व प्रमुख प्रो. मनजीत सिंह का कहना है कि विदेश में सभी कामों को एक जैसा ही देखा जाता है इसलिए युवाओं में स्टेटस कोई मैटर नहीं करता। पंजाब में युवा अपने खेतों में काम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन विदेशी धरती पर घंटों बेरियां तोड़कर उसकी पैकिंग करने में भी अपनी शान समझते हैं। उनका मानना है कि लवप्रीत जैसे मामलों के पीछे के असली कारणों को तलाशना होगा। लेकिन दुख की बात है कि किसी भी राजनेता या पार्टी के एजेंडे में हमारी युवा पीढ़ी नहीं है।

16500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में। इनमें से 3152 आलिया या उच्च स्तर के मदरसे हैं। प्रति वर्ष सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी में पास होने वाले छात्रों की संख्या 1.5 लाख है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 18 लाख है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 28 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

चिंतित करता हादसों का बढ़ता ग्राफ

उत्तराखंड में हादसों के बढ़ते ग्राफ पर चिंता के साथ ही चिंतन की भी जरूरत है। प्रदेश में इस साल छह माह में हादसों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 52.55 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल इसी अवधि में 432 दुर्घटनाएं हुई थीं, जो इस बार बढ़कर 659 हो गईं। इस दौरान मृतकों की संख्या 37 फीसद तो घायलों का आंकड़ा 47 फीसद बढ़ गया। यह भी सच है कि पिछले साल इस अवधि में लाकडाउन के चलते प्रदेश में वाहनों का आवागमन बंद था, वहीं इस बार संचालन अपेक्षाकृत अधिक रहा। बावजूद इसके इसमें भी दो राय नहीं कि प्रदेश में दुर्घटनाओं के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पहाड़ की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में हादसों की संख्या बढ़ी है। विशेषकर देहरादून, ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार दुर्घटनाओं के मद्देनजर ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहे हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि हादसों के पीछे मानवीय भूल ही अधिक जिम्मेदार है। पहाड़ हो या मैदान, दोनों इलाकों में तेज रफ्तार और सड़कों की खराब हालत हादसों को न्यौता देते प्रतीत हो रहे हैं। नियमों का पालन न किया जाना यातायात संचालन में सबसे बड़ी चुनौती है। रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस की ओर से समय-समय पर अभियान अवश्य चलाए जाते हैं, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखायी पड़ता। सड़कों के रखरखाव को लेकर भी अक्सर सवाल उठते रहे हैं। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा सीजन से पहले हर वर्ष डेंजर जोन को चिन्हित किया जाता है, लेकिन आज तक इनके ट्रीटमेंट को लेकर गंभीरता नहीं दिखायी दी।

> बढ़ती दुर्घटनाओं पर अंकुश के लिए यातायात नियमों को लेकर आम जन को जागरूक करने की जरूरत है। एजेंसियों को भी जिम्मेदारी का अहसास कराना होगा

इतना ही नहीं, मार्गों पर उभरे भूस्खलन जोन भी जिंदगी के लिए चुनौती बने हुए हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धाम के पास डाबरकोट और बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ ऐसे ही स्लाइडिंग जोन हैं। लंबा समय बीतने के बाद भी इनका उपचार नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि तंत्र इससे अनजान है, लेकिन लापरवाह रवैया जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। मसलन यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश में सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है। नियमानुसार परिषद की कम से कम एक बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित की जानी चाहिए। बावजूद इसके बामुश्किल साल में एक बार ही बैठक हो पा रही है। जिला सड़क सुरक्षा समितियों का हाल और भी खराब है। वर्ष में चार बैठकें तय होने के बावजूद एक बैठक भी हो जाए तो गनीमत है। सरकार को चाहिए कि हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात नियमों को लेकर आम जन को तो जागरूक करे ही, जिम्मेदार एजेंसियों को भी सक्रिय किया जाना चाहिए।

बिहार

मद्धिम न हो शिक्षा की लौ

राज्य सरकार कोरोना काल में भी शिक्षा के उन्नयन को गतिशील है। कोरोना के कारण डेढ़ साल से सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य प्रभावित चल रहा है। इस दौरान अधिकांश दिन स्कूल बंद रखने पड़े। पढ़ाई के प्रति अभिभावकों का रुझान और बच्चों की लगन कम न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं में दी जाने जा रही प्रोत्साहन राशि को इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है। बिहार ने हरेक को शिक्षित करने की मुहिम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में एक रोल माडल खड़ा किया है। इसका अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं।

पिछले दस-पंद्रह सालों में शिक्षा की रोशनी से हर गांव-घर को रोशन करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसने खासकर बालिका शिक्षा को काफी मजबूती प्रदान की है। गांव-देहात में यह परंपरा ठहर सी गई है कि बालिकाएं घर में चौका-बर्तन के लिए होती हैं। बड़े-बुजर्गों ने भी इस कुरीति से मुंह मोड़ लिया है। वे अब गांव से दूर पढ़ाई करने के लिए जाने पर अपने घरों की लड़कियों को रोकते-टोकते नहीं। हालांकि बड़ा योगदान सरकारी प्रोत्साहनों का ही है। सरकार की ओर से मुफ्त कापी-किताबें, शुल्क माफी, पोशाक और साइकिल के लिए राशि दी जा रही है। पचहत्तर फीसद हाजिरी पर छात्रवृत्ति देने का प्रविधान भी है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर भी पचहत्तर फीसद हाजिरी के नियमों में ढील देकर स्कालरशिप जारी रखना बड़ी राहत समान है। इसका लाभ प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत एवं अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस साल भी मिलेगा। पहली से 12वीं तक के तकरीबन दो करोड़ विद्यार्थियों को यह लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग में इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मंत्री की सहमति के बाद वित्त विभाग को इसे भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर अक्टूबर में बच्चों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पिछले वर्ष शिक्षा को प्रोत्साहन मद से बच्चों के खाते में 3,103 करोड़ रुपये भेजे गए थे। इस साल 3,676 करोड़ रुपये भेजे जाने हैं। सरकार का यह निर्णय पढ़ाई के प्रति गंभीर बच्चों के साथ ही अभिभावकों का हौसला भी बढ़ाएगा।



रंग ला रही बिहार सरकार की हरेक को शिक्षित करने की मुहिम। फाइल

> शिक्षा की बदौलत विकास की राह तय करने में जुटी राज्य सरकार की ओर से कोरोना काल में भी छात्रवृत्ति जारी रखना बड़ी राहत है

पंजाब

सबक भी मिले

अमृतसर में दशहरा पर्व के दौरान हुए जौड़ा फाटक रेल हादसे के बाद कई वादे किए गए। लंबे इंतजार के बाद इनमें से पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने का वादा पूरा होता हुआ दिख रहा है। पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से नौकरी का आफर लेटर भेज दिया गया है। अब नौकरी देकर इस घटना में जान गंवाने वालों के स्वजनों के जख्मों पर कुछ मरहम तो लगा दिया जाएगा, लेकिन इस घटना की जांच में इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति अथवा संस्था का आज तक पता न लगना इन्हें जरूर सालता रहेगा।

इस दर्दनाक घटना के बाद तीन स्तर पर जांच शुरू हुई, लेकिन कोई भी उचित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। स्थानीय प्रशासन, पंजाब सरकार और रेलवे ने अपने-अपने स्तर पर इस घटना की जांच करवाई थी। इनमें से एक जांच रिटायर्ड जज अमरजीत सिंह कटारी ने की थी। उन्होंने 21 महीने की जांच के बाद जो रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंपी थी, उसमें नगर निगम के चार अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था। हालांकि 2018 में जिस आयोजन के दौरान यह घटना घटी उसमें कुछ सियासी लोगों पर सवाल उठाए गए थे। यह किसी से छिपा नहीं है कि जौड़ा फाटक के पास जो आयोजन हुआ था, उसमें राजनीतिक निहितार्थ भी थे। ऐसे में इसकी निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी ही चाहिए। किसी भी घटना के पीड़ितों की मदद करना बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसी घटना के दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा देना भी उतना ही आवश्यक है। जांच में जितनी देरी होगी दोषियों के बच निकलने की संभावना उतनी ही प्रबल होती जाएगी। साथ ही उन कारणों का पता भी नहीं चल पाएगा, जिनके कारण इतनी बड़ी और दुखद घटना घटी।

दोषी चाहे जो भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। प्रदेश सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और जांच की गति तेज करनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस घटना में करीब साठ बेकसूर लोगों की जान चली गई थी और कइयों को ऐसे जख्म मिले थे जो संभवतः जीवन भर भरे नहीं जा सकते। ठोस जांच की आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि इससे असल कारण का पता चल पाएगा। इससे सबक सीखकर भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के पुख्ता प्रबंध भी किए जा सकते हैं।

> किसी भी घटना के पीड़ितों की मदद करना बेहद जरूरी है, लेकिन दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा देना भी आवश्यक है



अमृतसर रेल हादसे की है ठोस जांच की आवश्यकता। फाइल

बंगाल

बढ़ रही सरकारी नौकरी की चाहत

वर्तमान समय में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बना चुकी है। नौकरी-रोजगार के लिए लोग इस जिले से उस जिले, एक राज्य से दूसरे राज्यों में मारे-मारे फिर रहे हैं। कहीं नौकरी की थोड़ी सी भी उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो युवक-युवतियां टूट पड़ रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात हो तो भीड़ और बढ़ जा रही है। क्योंकि सरकारी नौकरी को अब भी बेरोजगार युवा और उनके परिजन आर्थिक सुरक्षा मानते हैं। ऐसा ही एक वाक्या कोलकाता में सामने आया है। महानगर के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में शवों को संभालने के लिए प्रयोगशाला सहायक, जिसे डोम भी कहा जाता है, उसके रिक्त छह पदों के लिए वैकेंसी निकली तो 8,000 आवेदक पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोम पद के लिए आवेदन करने वालों में इंजीनियर, स्नातक और परास्नातक कर चुके लोग भी शामिल हैं।

इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रेजुएट के साथ-साथ इंजीनियरिंग और परास्नातक कर चुके लोग तक बेरोजगार हैं और डोम के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि इस पद के लिए आवश्यक योग्यता महज आठवीं पास ही है। बावजूद इसके इंजीनियरिंग, परास्नातक और स्नातक करने वालों ने आवेदन किया है। यह बंगाल में बेरोजगारी की स्थिति बयां कर रही है। परंतु यहां सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है। क्या यह उन युवाओं को मिली शिक्षा के मानक पर सवाल नहीं है? यदि इंजीनियरिंग करने के बाद भी वे बेरोजागर हैं तो यह हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल है। क्या हमारे शिक्षण संस्थानों में सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए शिक्षा दी जा रही है? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

> कोलकाता में स्नातक और परास्नातक कर चुके लोग डोम के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, जबकि इस पद के लिए आवश्यक योग्यता महज आठवीं पास ही है

हमारे देश में नई शिक्षा नीति बनी है जिसमें स्कूल से ही बच्चों को इस लायक बनाने की योजना है कि वे नौकरी के पीछे नहीं, बल्कि स्वरोजगार के पीछे अधिक भाग सकें, परंतु इसमें भी बंगाल की तरह कुछ राज्य सरकारें सियासत ही देख रही हैं। यहां ममता सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आखिर इंजीनियर और पोस्टग्रेजुएट बच्चों को डोम की नौकरी के लिए क्यों आवेदन करना पड़ रहा है। यदि विपक्षी दल यह सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के माध्यम से राज्य में 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है और इससे 28 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो फिर आखिर कहां है निवेश और रोजगार? इसीलिए जरूरत ऐसी शिक्षा की है कि युवाओं को सरकारी या अन्य नौकरी के पीछे नहीं भागना पड़े।

त्वचा बनकर बर्न इंजरी को संक्रमण से बचाएगी पट्टी

जागरण विशेष

बैक्टीरिया सेलुलोज पट्टी करेगी अधिक जले मरीजों का रामबाण इलाज, जल्द दिलाएगी राहत

विक्सन सिक्रोड़िया • कानपुर

जलने पर मरीज के सामने सबसे बड़ा खतरा संक्रमण का होता है। कई बार संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि मरीज की जान पर बन आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आने वाले समय में जलने से घायल होने वाले मरीजों के घाव में संक्रमण नहीं फैलेगा और वह दोगुनी रफ्तार से ठीक भी होगा। एसीटोबैक्टर जाइलम बैक्टीरिया के सेलुलोज से बनी पट्टी जले हुए स्थान पर त्वचा की तरह चिपक जाएगी और संक्रमण नहीं फैलने देगी। फोरियर ट्रांसफार्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटीआइआर उपकरण) के परीक्षण में इस पट्टी के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

बैक्टीरिया के सेलुलोज से बनाई गई पट्टीः उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान (यूपीटीटीआइ) से टेक्सटाइल टेक्नोलाजी के पीएचडी छात्र आशुतोष पांडेय ने डीन एकेडमिक प्रोफेसर मुकेश सिंह के निर्देशन में बैक्टीरिया सेलुलोज से ऐसी मेडिकल पट्टी बनाई है जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति की तुलना में जलने वाले मरीज के घाव को जल्दी भरेगी।

उन्होंने बताया कि विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से निकलने वाले सेलुलोज को पट्टी में जेल की तरह लपेटकर उसे तैयार किया गया है। इस पट्टी को घाव पर बिना किसी दवा के लपेटा जाएगा। एक बार लपेटने के बाद घाव की बार-बार ड्रेसिंग करने की जरूरत भी नहीं होगी। यह मुख्य रूप से घाव को संक्रमण से सुरक्षित रखने का काम करेगी। वहीं, इससे घाव भी जल्दी ठीक होगा। इस पट्टी से जलने वाले मरीजों को बेहद राहत मिलेगी। वे जल्द ठीक होंगे।



विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से निकलने वाले सेलुलोज को जेल की तरह लपेटकर तैयार की गई है पट्टी • जागरण

घाव भरने तक त्वचा का काम करेगी



प्रो. मुकेश सिंह

प्रो. मुकेश सिंह ने बताया कि किसी भी व्यक्ति के जलने पर घाव भरने का समय निश्चित होता है क्योंकि नई त्वचा बनाने का कोई उपचार नहीं होता है। जलने के बाद त्वचा उस स्थान पर दोबारा निकलती है जिससे वह धीरे-धीरे घाव भरती है। सेलुलोज की पट्टी घाव को पूरी तरह ढक देती है। जब तक नई त्वचा नहीं आती और घाव नहीं भरता तब तक यह कृत्रिम त्वचा की तरह काम करती है जिससे संक्रमण नहीं फैलता है। नई त्वचा आने पर यह पट्टी खुद ब खुद निकल जाती है।

आइआइटी ने भी बनाई थी बैंडेज

इससे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) कानपुर के पीएचडी के पूर्व छात्र डा. तुषार देशपांडे ने माइक्रोपोरस इलस्टोमरिक थिन से बैंडेज तैयार की थी। इस बैंडेज की खासियत यह है कि इस पर कोई तरल पदार्थ नहीं टिकता है। इसके अलावा इस बैंडेज को ऐसे बनाया गया है जिससे घाव पर वेंटिलेशन होता रहे और जल्दी सूखे। इसमें घाव अन्य पट्टियों की तुलना में जल्दी ठीक होता है। इसे घाव जल्द ठीक होगा।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

एक समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग पर सरकार को नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 और क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट रूल 2012 के मुताबिक एक समान, गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन जनस्वास्थ्य अभियान की ओर से दाखिल याचिका पर वरिष्ठ वकील संजय पारिख की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया।

इससे पहले याचिका पर बहस करते हुए पारिख ने कहा कि विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट व सिफारिशों के बाद क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में आया था। इस कानून में इलाज के पैसे व इलाज के स्टैंडर्ड की गाइडलाइन तय है। पारिख ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। जन स्वास्थ्य सेवा में बहुत सी कमियां है। दवाइयां नहीं हैं। ढांचागत संसाधन नहीं है। पारिख ने क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट और रूल लागू करने और उन्हें अधिसूचित किए जाने की मांग की, ताकि लोगों को किफायती और स्तरीय इलाज मुहैया हो। पीठ ने बहस सुनने के बाद मामले में नोटिस जारी किया।

श्रद्धा का महासावन

जहां शिव हैं, वहीं शक्ति का वास

देवाधिदेव महादेव पतित पावनी गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हुए हैं। ऐसा सामर्थ्य केवल उन्हीं में है। सिर पर चंद्रमा धारण कर वह शीतलता के प्रतीक हैं। गले में सर्पों की माला, व्याघ्र के चर्म का आसन और नंदी की सवारी यानी जो अहितकारी है, उस पर शिव का नियंत्रण है। शिव से हमें मन, मस्तिष्क और इंद्रियों पर नियंत्रण की प्रेरणा मिलती है। शिव नृत्य, संगीत आदि ललित कलाओं के जनक हैं। अमंगलकारी शक्तियों की क्षति के लिए शिवोपासना जरूरी है। समग्र दृष्टि से शिव की उपासना कल्याण, सुख और निरोगी होने की कामना को पूर्ण करती है। भाव से की गई शिव स्तुति से सृष्टि का संरक्षण होता है। सृष्टि संरक्षित होगी तो मानव जीवन भी बचेगा। भक्त में अगर त्याग, समर्पण, सच्चाई व सदाचार है तो वह शिव की कृपा का पात्र स्वतः बन जाता है। हर व्यक्ति में दो तत्व होते हैं, जड़ और आत्म तत्व। जड़ तत्व तन, मन, विवेक व स्वभाव है, जबकि आत्म तत्व सत्य से जुड़ा है। जहां सत्य है, शिव वहीं होते हैं और जहां शिव होते हैं, वहीं शक्ति का वास है। शिव सच्चे मन से अपने दरबार में आने वालों के हमेशा करीब रहते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से उन्हें भोले भंडारी और भोले शंकर भी कहा गया है। त्रिदेवों में शिव के सिवा किसी के भी नाम के आगे भोला' शब्द नहीं लगता। भोला शब्द सिर्फ भगवान शिव को ही सुशोभित करता है। शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत भी। यह सृष्टि भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है और कल्प के अंत में उन्हीं में समा जाएगी।



स्वामी कैलाशानंद गिरि
आचार्य महामंडलेश्वर, श्रीपंचायती अखाड़ा निरंजनी

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

यूनेस्को की विश्व धरोहर में अब हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा भी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा को को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी। इससे पहले 13वीं शताब्दी में निर्मित तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को रविवार को विश्व धरोहर में शामिल किया जा चुका है।

अहमदाबाद से करीब 350 किलोमीटर दूर भचाऊ (कच्छ) के पास खडीर बेट में स्थित धौलावीरा पांच हजार साल से भी अधिक पुरानी सभ्यता का अवशेष है। पत्थरों को तराशकर बनाया गया किलानुमा भवन, अधिकारी व सभासदों के विशेष कमरे, स्नानागार व शौचालय आदि के अवशेष बताते हैं कि तत्कालीन सभ्यता कितनी उन्नत थी। सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रणोत्सव के जरिये कच्छ को विश्व फलक पर लाते हुए संस्कृति व विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके चलते ही आज यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व धरोहर में शामिल किया है। पहली बार 1967 में धौलावीरा चर्चा में आया। यहां 77 लाख लीटर पानी संग्रह की क्षमता वाले तालाब, स्नानागार आदि के अवशेष हैं। माना जाता है कि इस प्राचीन नगर में 50 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था थी। इसरो के पूर्व विज्ञानी डा. पीएस ठक्कर बताते हैं कि प्राचीन लोगों को अशिक्षित माना जाता है, लेकिन हड़प्पाकालीन सभ्यता उनके वैज्ञानिक एवं बेहतर कौशल का उदाहरण है।

धौलावीरा के साथ ही गुजरात में विश्व धरोहरों की संख्या चार हो गई है। इससे पहले 2004 में मध्य गुजरात के चांपानेर पावागढ़, 2014 में राण की वाव व 2017 में अहमदाबाद शहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है।

संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने ट्वीट किया, 'मुझे भारतवासियों से यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अब धौलावीरा के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 40वां स्थल शामिल हो गया है।



हड़प्पाकालीन शहर धौलावीरा। प्रेट्र

> बेहद खुश हूं। लोगों, खासकर इतिहास, संस्कृति व पुरातत्व में रुचि रखने वालों को यहां जरूर जाना चाहिए। मैं पहली बार धौलावीरा तब गया था जब छात्र था और झूम उठा था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में धौलावीरा की विरासत के संरक्षण व उद्धार का मौका मिला। हमारी टीम ने वहां पर्यटन को बढ़ावा देने वाली ढांचा के विकास के लिए भी काम किया है।
>
> -नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

'माननीयों के खिलाफ जांच व ट्रायल में देरी हुई तो अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई'

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़

- पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दी चेतावनी
- अमरिंदर सिंह व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामलों की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल

माननीय विधायकों, सांसदो और मंत्रियों के खिलाफ चल रहे मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जांच अधिकारियों को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि तेजी से ट्रायल व जांच नहीं की गई तो जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हाई कोर्ट ने यह आदेश पंजाब, हरियाणा व केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में दी गई जांच रिपोर्ट को देखने के बाद दिया।

हरियाणा सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि आइजी (अपराध) को माननीयों के खिलाफ मामलों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और राज्य में कोर्ट के आदेशानुसार तेजी से ऐसे मामलों की जांच हो रही है। पंजाब सरकार की तरफ से बताया गया कि आइजी (ला एंड आर्डर) संजय कुमार को नोडल आफिसर नियुक्त कर दिया गया है और सभी जिलों के डीसी और एसएसपी को इन सभी मामलों की जांच में तेजी लाए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। मंगलवार को पंजाब सरकार की तरफ से यह जानकारी एडिशनल एडवोकेट जनरल एसपीएस टिन्ना ने दी।

केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की जिला अदालत में आयकर, सुखपाल खैहरा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी के मामले चल रहे हैं। इन दोनों ने हाई कोर्ट से अंतरिम राहत ली हुई है। इन सभी मामलों में आगे क्या किया जा रहा है इसकी जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय और मांगा है।

सुनवाई के दौरान इस मामले में हाई कोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट रुपिंदर खोसला ने हाई कोर्ट को बताया कि हाल ही में पंजाब के एक विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के एक मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाई हैं, इन मामलों पर भी गौर किया जाना जरुरी है। सीबीआइ ने मंगलवार को इस मामले में जवाब देते हुए जानकारी दी है कि उसके पास पंजाब और हरियाणा के सांसदों व विधायकों के छह मामले चल रहे हैं। इनमे दो मामले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिले राम शर्मा, पंजाब के पूर्व विधायक राज खुराना और एक पंजाब के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह काहलों के खिलाफ हैं। ये केस लंबित हैं। इस पर हाई कोर्ट ने अब सीबीआइ चंडीगढ़ की विशेष अदालत से इन सभी केसों के स्टेटस की जानकारी मांग ली है।



पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। जागरण आर्काइव

पंजाब में 163 और हरियाणा में 68 केस पेंडिंग

हरियाणा सरकार पिछली सुनवाई पर बता चुकी है कि प्रदेश में पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ 68 केस लंबित हैं। इन मामलों में से 21 में ट्रायल चल रहा है और 44 में अभी जांच जारी है। इसके अलावा तीन मामलों को सीबीआइ को रेफर किए गए है। वहीं पंजाब सरकार पहले ही बता चुकी है कि उनके 96 पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ 163 मामले दर्ज हैं इन 96 में से चार मौजूदा, पांच पूर्व सांसद, 35 मौजूदा विधायक और 52 पूर्व विधायक शामिल हैं।

अब सेना में भी भर्ती हो सकेंगे यूपी मदरसा बोर्ड के छात्र

शोभित श्रीवास्तव, लखनऊ

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से पढ़ाई करने वाले छात्र अब सेना सहित विभिन्न सेवाओं में भर्ती हो सकेंगे। साथ ही वे विदेश में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला पा सकेंगे। यह इसलिए संभव होगा, क्योंकि यूपी मदरसा बोर्ड अब भारतीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड मंडल (कोब्से) में पंजीकरण कराने जा रहा है। इसमें पंजीकरण न होने के कारण अभी तक मदरसा बोर्ड के छात्र सेना के साथ ही केंद्र व अन्य राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे। पंजीकरण के बाद मदरसा बोर्ड को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैधानिकता मिल जाएगी।

कोब्से भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र संगठन है। राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड इससे संबद्ध हैं। कोब्से को भारत सरकार द्वारा 1979 से रजिस्टर्ड संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। यह हर प्रदेश के अधिकृत शिक्षा बोर्ड को अपने यहां पंजीकृत करता है। कोब्से में पंजीकरण होने से मदरसा बोर्ड के छात्र-छात्राओं को न सिर्फ केंद्र व अन्य राज्य सरकारों की नौकरियों के आवेदन में आसानी होगी, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके नए रास्ते खुल जाएंगे। विधान मंडल से पारित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद विधेयक 2004 के अधीन मदरसा बोर्ड का गठन 2007 में हुआ था। इसी अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार ने अशासकीय अरबी और फारसी मान्यता प्रशासन एवं सेवा विनियमावली 2016 बनाई। इससे प्रदेश में मदरसों का संचालन एवं प्रबंधन होता है। मदरसा बोर्ड की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट व सर्टिफिकेट की मान्यता प्रदेश में उच्च शिक्षा व सेवायोजन के लिए तो है लेकिन कोब्से में पंजीकरण न होने के कारण यहां के छात्र प्रदेश से बाहर नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं।

इसे देखते हुए उप्र मदरसा शिक्षा परिषद ने अपनी बोर्ड बैठक में कोब्से से मान्यता लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने कोब्से से मान्यता के लिए औपचारिकताएं पूरी कर आवेदन कर दिया है। उन्होंने आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम-2004, सेवा नियमावली 2016 तथा पाठ्यक्रम का विवरण भी भेजा है। कोब्से से मान्यता मिलने पर मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट का महत्व और बढ़ जाएगा।

ये प्रमुख लाभ मिलेंगे

- केंद्र सरकार व अन्य राज्यों की भर्तियों में कर सकेंगे आवेदन
- सेना व पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्ती में भी खुलेगी राह
- मदरसा बोर्ड की मार्कशीट व सर्टिफिकेट का सत्यापन होगा आसान
- खाड़ी देशों में भी पढ़ाई के लिए खुल जाएंगे रास्ते

अफगानिस्तान में जंग को रोज घुस रहे एक हजार पाक आतंकी

अफगान समस्या ▶ यूएन ने भी छह हजार पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों के होने की पुष्टि की

नाटो ने कहा, जंग में अफगान सेना का देंगे साथ

काबुल, एएनआइः अफगानिस्तान में पाकिस्तान से हर रोज एक हजार आतंकी अफगानिस्तान में घुसकर सरकारी सेना से जंग लड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है।

अफगानिस्तान की खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख रहमतुल्लाह राबिल ने कहा है कि एक हफ्ते पूर्व तालिबान ने सीमांत जिले स्पिन बोल्डक शहर पर कब्जा किया था। उसके बाद यहां से हर रोज पाक से एक हजार आतंकी अफगानिस्तान में घुस रहे हैं। राबिल ने अफगान सेना को आगाह किया, यदि स्पिन बोल्डक पर दोबारा कब्जा नहीं किया तो देश की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर खतरे में होगी। यहां से पाक के अन्य आतंकी संगठन भी तालिबान की वर्दी में दाखिल हो जाएंगे। पाकिस्तान में इन आतंकी संगठनों ने प्रशिक्षण और भर्ती दोनों का काम तेज कर दिया है। इसके लिए कई देश वित्तीय मदद दी जा रही है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) के छह हजार से ज्यादा आतंकी तालिबान के साथ अफगान सेना से लड़ रहे हैं। हिंसाग्रस्त देश में कई देशों और संगठनों के आतंकी सक्रिय हैं। इन विदेशी आतंकियों की संख्या 8 से 10 हजार के बीच है। इनमें से ज्यादातर मध्य एशिया, उत्तरी काकेशस क्षेत्र, पाकिस्तान और शिनजियांग से हैं। टीटीपी आतंकी मुख्य रूप से अफगानिस्तान के नानगरहर प्रांत में सक्रिय हैं।

इधर नाटो के महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग ने कहा है कि नाटो देश अफगानिस्तान सरकार का समर्थन जारी रखेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति अशरफ गनी से वार्ता कर उन्हें समर्थन देते रहने का भरोसा दिया।



सीमांत शहर स्पिन बोल्डक पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की आमद बढ़ गई है। (फाइल-इंटरनेट मीडिया)

कई जिलों से सेना ने तालिबान को खदेड़ा

एएनआइ के अनुसार, अफगान सेना ने बल्ख प्रांत के कालदर जिले को फिर अपने नियंत्रण में ले लिया है। टोलो न्यूज के अनुसार सेना ने निमरोज प्रांत के चखनसुर, बामियान प्रांत के साईघन और काहमर्द पर भी दोबारा कब्जा कर लिया है। कपिसा प्रांत में निजरब जिले पर कब्जा करने वाले आतंकियों को सेना ने खदेड़ दिया है। आइएएनएस के अनुसार अफगान सेना ने ताखर प्रांत की राजधानी तालुकान से तालिबान को भागने के लिए मजबूर कर दिया। यहां सेना ने 28 आतंकियों को ढेर कर दिया।

26 हजार फीट से नीचे उड़ानों पर अमेरिका ने लगाई रोक

एएनआइ के अनुसार, अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों के 26 हजार फीट से नीचे उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। यह निर्देश किसी भी विमान को तालिबान का निशाना बनाने से बचाने के लिए जारी किए गए हैं।

अमेरिका हर साल 400 करोड़ डालर देगा अफगान सरकार को

एपी के अनुसार, अफगान सरकार को वित्तीय सहायता के रूप में अमेरिका और नाटो देश 2024 तक हर साल 400 करोड़ डालर (करीब तीस हजार करोड़ रुपये) की मदद देंगे। इस धनराशि को अफगानिस्तान की सैन्य सुरक्षा पर खर्च किया जाएगा।

पाक में पश्तूनों का तालिबान के विरोध में प्रदर्शन

आइएएनएस के अनुसार,पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा,बलूचिस्तान प्रांत व कराची के कुछ हिस्सों में हजारों पश्तूनों ने तालिबान के खिलाफ अफगान सरकार के समर्थन में प्रदर्शन किया। पश्तूनों के ये प्रदर्शन इंटरनेट मीडिया पर भी छाए रहे।

पाकिस्तान के एनएसए और आइएसआइ प्रमुख का अमेरिका दौराः पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मोईद युसुफ और खुफिया एजेंसी आइएसआइ के प्रमुख जनरल फैज हमीद सोमवार को अमेरिका पहुंच गए, जहां उनकी शीर्ष अफसरों से अफगानिस्तान मुद्दे पर वार्ता होगी। इस बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि अफगानिस्तान में युद्ध का संचालन पाक सेना कर रही है।

स्पिन बोल्डक से लौटे चार पत्रकार गिरफ्तार : रायटर के अनुसार, अफगान प्रशासन ने स्पिन बोल्डक से लौटे चार स्थानीय पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। उन पर सेना के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप है। ये सभी स्थानीय पत्रकार हैं।

अब इराक में भी खत्म होगा अमेरिकी मिशन

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिका ने अफगानिस्तान के बाद अब इराक में भी सैन्य मिशन खत्म करने का एलान किया है। इस संबंध में एक समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कादिमी ने मुहर लगाई है। समझौते के तहत इराक में 18 वर्ष से जारी अमेरिकी सैन्य मिशन इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। हालांकि बाइडन ने यह साफ किया है कि इराक में मौजूद ढाई हजार अमेरिकी सैनिकों में से ज्यादातर की इस पश्चिम एशियाई देश में तैनाती बनी रहेगी, लेकिन वे सिर्फ सलाहकार और प्रशिक्षण देने की भूमिका में रहेंगे। बाइडन ने इसी माह यह एलान किया था कि 20 वर्षों से जारी अफगान मिशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा।

व्हाइट हाउस में सोमवार को बाइडन और मुस्तफा की बैठक हुई, जिसमें इस समझौते पर मुहर लगी। बाइडन ने पत्रकारों से कहा, 'इराक में हमारी भूमिका आइएस से मुकाबले में सहायक और प्रशिक्षक के तौर पर बनी रहेगी, लेकिन हमारा युद्ध अभियान इस वर्ष के बाद जारी नहीं रहेगा।' इधर, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने यह बताने से इन्कार किया कि इराक में कितने सैनिकों की तैनाती बनी रहेगी। उन्होंने सिर्फ इतना बताया, 'जरूरत के अनुसार यह संख्या तय होगी।'

वड़ा एलान

- अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन और इराकी पीएम मुस्तफा ने समझौते पर लगाई मुहर
- 18 वर्ष से जारी यह अमेरिकी मिशन साल के आखिर तक हो जाएगा समाप्त



व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात करते इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कादिमी। एएफपी

2003 में अमेरिका ने किया था हमला

मार्च, 2003 में अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने इराक पर हमला किया था। यह हमला उन आरोपों के आधार पर किया गया था कि तत्कालीन इराकी शासक सद्दाम हुसैन की सरकार के पास विनाशकारी हथियार हैं। इस हमले के बाद सद्दाम सत्ता से बेदखल हो गए थे, लेकिन ऐसे हथियार कभी बरामद नहीं हुए।

इस कारण खत्म हो रहा मिशन

रायटर के अनुसार, समझौते से इराकी सरकार को बल मिल सकता है, क्योंकि मुस्तफा को ईरान समर्थित सियासी दलों और संसदीय समूहों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो इराक में अमेरिकी सेना की भूमिका का विरोध करते हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया समूह भी यही चाहते हैं कि इराक से सभी अमेरिकी सैनिकों की तत्काल वापसी हो जाए। ये समूह इराक में अक्सर ही उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं, जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी है।

लेकिन आइएस का खतरा बरकरार

अमेरिका के लिए यह मिशन रणनीतिक तौर पर अहम है। इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के काफी कमजोर पड़ने के बाद भी खतरा बरकरार है। इराक व सीरिया में अब भी आठ से 16 हजार आइएस आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान है। वर्ष 2017 में इराक ने आइएस पर जीत का एलान किया था।

गृह युद्ध के आसार से पड़ोसी देशों में चिंता

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

▶ तालिबान का रवैया लंबे समय तक अफगानिस्तान को कर सकता है अस्थिर

▶ ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, चीन और भारत की चिंता समान

अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद वहां हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। कई जिलों और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तालिबान और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स (एएनएसएफ) के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय जानकार मान रहे हैं कि वहां हालात और खराब होंगे। भारत का भी आकलन है कि अगर तालिबान और अफगानिस्तान के मौजूदा प्रशासन के बीच शांति वार्ता नहीं होती है और सत्ता साझेदारी को लेकर सहमति नहीं बनती है तो आने वाले दिनों में गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। भारत ही नहीं अफगानिस्तान के सभी पड़ोसी देशों के साथ चीन भी इस आशंका से चिंतित हैं। इस चिंता का कितना असर इन देशों की कूटनीति पर पड़ता है यह भविष्य तय करेगा। अलग-अलग देशों की चिंताओं को लेकर भारत के कूटनीतिक जानकारों के आकलन पर दैनिक जागरण की खास रिपोर्ट-



चीन : सोमवार को चीन व पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। अमेरिकी सेना की वापसी से चीन अफगान में अपने लिए संभावना देख रहा है लेकिन वह वहां के हालात से चिंतित भी है। खास तौर पर वह तालिबान का समर्थन करने वाले कुछ आतंकी संगठन के उसके शिनजियांग प्रांत में इस्लामिक आतंकी संगठनों के साथ संपर्क को लेकर परेशान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया रिपोर्ट में इस बात को बताया गया है कि किस तरह से पश्चिम एशियाई देशों के कुछ आतंकी संगठन तालिबान व अलकायदा के साथ मिल कर चीन को निशाना बनाने की मंशा रखते हैं। यही नहीं तालिबान के आने से अफगानिस्तान की अस्थिरता का असर चीन-पाकिस्तान आर्थिक कारिडोर पर भी पड़ने की आशंका है। कूटनीतिक जानकार मान रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान के चश्मे से अफगानिस्तान का आकलन करने वाले चीन के सुर बदल गए हैं।



रूस : तीन दशकों में अफगान के हालात में 360 डिग्री का बदलाव आया है। तब रूस की सेना की वापसी का अमेरिका इंतजार कर रहा था और अब रूस अमेरिकी सेना की वापसी से उपजे हालात से निबटने की तैयारी में है। भारतीय कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि रूस अब तेजी से बिगड़ते हालात से चिंतित है। रूस अभी तक यह सोच रहा था कि तालिबान के आने के बाद वह अफगान में शरण लिए इस्लामिक स्टेट (आइएसआइएस-दवेश) आतंकियों का सफाया कर उसके इस्लामिक बहुल राज्यों में आतंक फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाम लगा लेगा। लेकिन अभी सूचना आ रही है कि आइएसआइएस दुश्मनी भुला कर तालिबान को मदद दे रहा है। रूस तालिबान व चेचन विद्रोहियों के बीच के संबंधों को लेकर भी वह सचेत है।

अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान की वापसी के बाद ईरान के भी बदले सुर



ईरानः अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने यह बयान दिया है कि अमेरिका को इतनी जल्दबाजी में सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहिए था। पिछले दो दशकों से अमेरिका पर अफगानिस्तान में दखल देने का आरोप लगाने और उसका लगातार विरोध करने वाले ईरान के रूख में यह बदलाव तालिबान के बढ़ते आक्रामक रवैये के बाद आया है। ईरान को यह डर फिर सताने लगा है कि जिस तरह से 30 वर्ष पहले तालिबान ने सत्ता में आने के बाद शिया समुदाय पर जुल्म किये थे, वैसा ही इस बार भी न करने लगे। तब बड़ी संख्या में शरणार्थी ईरान पहुंचे थे, आज भी साढ़े सात लाख अफगान शरणार्थी ईरान में हैं। ईरान को डर है कि फिर लाखों शरणार्थी वहां पहुंच सकते हैं।

बाजार के बर्बाद होने का डर



ताजिकिस्तानः अफगानिस्तान के साथ इसकी 1357 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। हाल ही में तालिबान ने इसकी सीमा पर शेर खान बंदर बार्डर पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान इस सीमा के आस पास के तकरीबन सारे जिलों पर कब्जा कर चुका है और कड़े इस्लामिक कानूनों को लागू करने की घोषणा भी कर दी है। यहां के ताजिक मूल के इस्लामिक आतंकी संगठन (आइआरपीटी) की पौध पहले से ही है जो तालिबान के शह से खतरनाक हो सकती है। ताजिकिस्तान अफगान के बाजार पर भी नजर रखे हुए है जो वहां की अस्थिरता से पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है।

तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी सक्रिय

तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तानः इन दोनों देशों की अफगानिस्तान के साथ लंबी सीमा है। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही इन दोनों ने अफगान सीमा पर भारी भरकम सैन्य बलों की तैनाती कर दी है। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के साथ तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी (इटीआइएम) के सैकड़ों लड़ाकों के होने की बात कही थी। पहले यह संगठन अल-कायदा के साथ था लेकिन तालिबान के मजबूत होते ही उसके आतंकी अब अफगानी सेना पर हमला कर रहे हैं। ये भी इसी चिंता में है कि एक अस्थिर और गृह युद्ध जैसी स्थिति वाला अफगानिस्तान उनके यहां कई तरह की समस्याओं को जन्म दे सकता है। पिछले दिनों ताशकंद में कनेक्टिविटी पर हुई बैठक में उक्त दोनों देशों ने अफगान के बिगड़े हालात के आर्थिक दुष्प्रभावों का मुद्दा उठाया था।

न्यूज गैलरी

सीसीपी की निगरानी से परेशान चीनी कवि ने की आत्महत्या

गौंगडोंग : एक चीनी कवि और विचारक ने राष्ट्रपति शी चिनफिंग के कार्यकाल में अत्यधिक निगरानी व जासूसी किए जाने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। चिनफिंग की नीतियों के आलोचक ली हुजी (62) ने गौंगडोंग के हुईजू शहर में एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। हुजी ने अपनी जान लेने से पहले आनलाइन एक सुसाइड नोट पोस्ट कर दिया था, जिसमें वह सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) के महासचिव शी चिनफिंग के कार्यकाल की निगरानी से बेहद परेशान थे। (एएनआइ)

उत्तर और दक्षिण कोरिया ने वार्ता के लिए हाटलाइन सेवा बहाल की

सियोल : उत्तर और दक्षिण कोरिया दोनों देशों में वार्ता के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हाटलाइन सेवा को फिर बहाल कर दिया गया है। उत्तर कोरिया ने इस सेवा को कई वर्षों पहले बंद कर दिया था। हाटलाइन सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच संबंधों की नई शुरुआत होने की उम्मीद है। (रायटर)

ईरान का इजरायल के जासूसों की गिरफ्तारी का दावा

तेहरान : ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि दक्षिणपूर्व में पानी को लेकर चल रहे प्रदर्शन के दौरान इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों का एक समूह पकड़ा गया है। इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। इन हथियारों को ये जासूस यहां प्रदर्शन की आड़ में इस्तेमाल करना चाहते थे। पकड़े गए जासूसों की संख्या नहीं बताई गई है। (एपी)

कैलिफोर्निया में फायरिंग, पुलिस अधिकारी सहित पांच की मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के कैलिफोर्निया के वास्को शहर में फायरिंग की एक घटना में पुलिस अधिकारी सहित पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में संदिग्ध हमलावर भी शामिल है। यह घटना उस समय हुई, जब एक हमलावर ने प्रवर्तन अधिकारी पर गोली चला दी। (आइएएनएस)

पाक पीएम के सहायक को कदानी कहने पर विधायक गिरफ्तार

लाहौर : पाकिस्तान में पाक प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक को कदानी (अहमदी समुदाय का) कहने पर एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया। यह विधायक इमरान की ही पार्टी के हैं। (प्रेट्र)

गुलाम कश्मीर में पाक सेना के खिलाफ बगावत

▶ चुनावी धांधली के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतरे, सुरक्षा बलों से भिड़े

▶ पाकिस्तान और इमरान मुर्दाबाद से गूंजी घाटी

मुजफ्फराबाद, एएनआइ : गुलाम कश्मीर (गिलगिट-बाल्टिस्तान) में चुनाव के दौरान सरकारी अराजकता और धांधली के कारण पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह हो गया है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जगह-जगह रास्ता जाम किया गया। सुरक्षा बलों से झड़प भी हुईं।

गुलाम कश्मीर में 25 जुलाई को हुए विधान सभा चुनाव में पाक में सत्तारूढ़ इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने जमकर धांधली की। इस धांधली और अराजकता में चुनाव आयोग और पुलिस से लेकर सेना तक सभी ने साथ दिया। इसके कारण मतदान के दौरान व्यापक पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुईं। इमरान की पार्टी के दो कार्यकर्ताओं की मौत के साथ ही सैकड़ों लोग घायल हो गए। चुनाव परिणाम में इमरान की पार्टी को 45 में से 25 सीटें हासिल हुईं। इसी के बाद पूरी घाटी में पाक सेना और सरकार के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। गुजरांवाला में कई स्थानों पर जनता और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुईं। गुस्साए लोगों ने टायर जलाकर सड़कों पर डाल दिए। कई स्थानों पर पथराव भी किया गया। विपक्षी दल पीएमएल-एन की प्रवक्ता मरयम औरंगजेब ने कहा कि अलीपुर छाता में तहरीक ए इंसाफ पार्टी के गुंडों ने हिंसा फैलाई और कार्यकर्ताओं पर हमले किए। यहां पुलिस और सेना ने गुंडों का ही साथ दिया।

सड़क जाम के दौरान सुरक्षा बलों से भिड़ते लोगों ने सेना और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां सेना के खिलाफ खुलकर बगावत हो गई है। पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरयम नवाज ने कहा है कि वह इन चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगी, जो गुंडागर्दी से हासिल किए गए हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उपाध्यक्ष शेरी रहमान ने कहा कि सुनियोजित साजिश और धांधली करके चुनाव परिणाम को चुराया गया है।

गुलाम कश्मीर के तथाकथित प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने कहा है कि विधान सभा चुनाव दिखावा रहा। इससे पहले पीएमएल-नवाज के नेता और प्रत्याशी चौधरी मुहम्मद इस्माइल गुज्जर ने कहा कि वह सरकार की इस धांधली के खिलाफ भारत से मदद लेंगे।

हिंदू लड़कियों को फर्जी कागजात से बनाया जा रहा मुस्लिम

▶ जबरन निकाह की शिकार रीना को मुक्त कराने के बाद खुला राज

▶ हिंदू लड़कियों के अपहरण को छिपाने के लिए पहले कराते हैं धर्म परिवर्तन

कराची, एएनआइ : पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन शादी रचाने के मामलों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना के बाद अब यहां नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को पहले जाली दस्तावेजों के माध्यम से मुस्लिम बनाया जाता है। उनके मां-बाप भी दस्तावेजों में मुस्लिम बता दिए जाते हैं और फिर जबरन शादी रचा ली जाती है।

ऐसा ही एक मामला सिंध प्रांत के बादिन जिले में आया है, जहां रीना मेघवार नाम की हिंदू लड़की को पहले फर्जी कागजात बनाकर मुस्लिम परिवार की लड़की बना दिया गया। उसके बाद एक मुस्लिम से निकाह कर दिया गया। माता-पिता की गुहार पर उच्च न्यायालय की जांच में सारा भेद खुल गया। बाद में पुलिस ने रीना को मुक्त कराया।

डान अखबार के मुताबिक रीना का अपहरण होने के बाद जब पुलिस में शिकायत की गई तो स्थानीय अदालत में अपहरण करने वालों ने रीना को डरा-धमकाकर बयान दर्ज करा दिया कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। इस शादी का वीडियो भी बनाया गया था। जो इंटरनेट मीडिया पर देखे जाने के बाद सारा भेद खुल गया। निकाह में रीना का नाम मरियम बताया गया था। शादी के लिए जो कागजात तैयार किए थे, उसमें माता-पिता भी मुस्लिम ही बताए गए थे।

रीना के वास्तविक माता-पिता ने फिर सिंध उच्च न्यायालय में अपील की। अदालत ने जब पुलिस से जांच कराई तो हकीकत सामने आ गई। रीना ने उच्च न्यायालय में बताया कि उससे निचली अदालत में जबरन बयान दर्ज कराया गया था।

भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोटा बुकर के लिए नामित

लंदन, प्रेट्र : भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजीव सहोटा इस साल के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार की काल्पनिक कथा की श्रेणी के अपने उपन्यास 'चाइना रूम' के लिए नामित हुए हैं। हालांकि सहोटा के लिए मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है क्योंकि उनके समेत इस साल 13 लोगों को नामित किया गया है जिसमें नोबेल विजेता काजू इशिगुरो और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर्स शामिल हैं।

40 वर्षीय संजीव सहोटा के बाबा-दादी 1960 में पंजाब से ब्रिटेन आ गए थे। वर्ष 2015 में भी सहोटा के उपन्यास 'द ईयर ऑफ रनअवेज' को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया जा चुका है। उन्हें वर्ष 2017 में साहित्य के लिए यूरोपीय यूनियन के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। संजीव सहोटा के उपन्यास 'चाइना रूम' को वर्ष 2020 के अक्टूबर और 2021 सितंबर के बीच ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित 158 अंग्रेजी उपन्यासों में से चुना गया है। बुकर पुरस्कार के जजों का कहना है कि दो कालों और महाद्वीपों के बीच के अंतर को 'चाइना रूम' उपन्यास में एक साथ गुथा गया है। आव्रजकों के अनुभवों पर आधारित इसके कथानक में बेहद रोचक मोड़ है। इस पीड़ा को बेहद सुलझे तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हुए दिखाया गया है। सहोटा ने बड़ी सहजता से इस बोझिल विषय को भी प्रेम, उम्मीद और विनोद से भर दिया है।



संजीव सहोटा की फाइल फोटो। इंटरनेट मीडिया

सहोटा के अलावा, बुकर पुरस्कार के नामित उपन्यासों में जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजू इशीगोरा की 'लारा एंड द सन', दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गैलुट की 'द प्रामिस', अमेरिकी लेखक रिचर्ड्स पावर की 'बिवाइल्डरमेंट' को भी नामित किया गया है। इस साल नामित किताबों में दो अमेरिकियों पेट्रीशिया लाकवुड की 'नो वन इज टाकिंग अबाउट दिस' और नाथन हैरिस की 'द स्वीटनेस आफ वाटर' भी शामिल हैं। 14 सितंबर को इनमें से छह किताबों का चयन होगा और विजेता की घोषणा लंदन में एक समारोह के दौरान तीन नवंबर को होगी।

वैक्सीन की वैश्विक असमानता दूर करने के लिए प्रभावी तंत्र की जरूरत : भारत

▶ सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में कोविड-19 की स्थिति के प्रस्ताव 2565 पर चर्चा की

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : भारत ने कोविड-19 टीकों की वैश्विक असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी तंत्र की जरूरत पर जोर दिया है। भारत ने कहा, वायरस के स्वरूप में और बदलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान की आवश्यकता है। इसके लिए वैश्विक समुदाय के साथ वह अपना 'कोविन' मंच साझा करने को तैयार है।

फ्रांस की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बंद कमरे में कोविड-19 की स्थिति के प्रस्ताव 2565 पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ट्विटर पर लिखा, सुरक्षा परिषद में कोविड-19 पर चर्चा में उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि की हैसियत से कहा, टीके की वैश्विक असमानता को दूर करने के लिए प्रभावी तंत्र और वायरस के स्वरूप में और बदलाव को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान की जरूरत है। टीके को लेकर लोगों की गलतफहमियों को दूर करने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही भारत ने कोविन मंच की पेशकश भी की। कोविड रोधी टीकाकरण के लिए कोविन भारत का प्रौद्योगिकी मंच है। ज्ञात हो, इस माह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोविन को एक खुले साधन के तौर पर तैयार किया जा रहा है ताकि यह सभी देशों के लिए उपलब्ध हो। फरवरी में सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 प्रस्ताव को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस डे रिविरे ने ट्विटर पर कहा कि प्रस्ताव 2532 को अपनाने के एक साल के बाद सुरक्षा परिषद ने कोविड स्थिति पर बैठक की।



संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए। प्रेट्र

अगस्त में समग्र रुख अपनाएगा भारत : तिरुमूर्ति ने कहा,भारत अगले माह अगस्त में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्रता का रुख अपनाते हुए नौसैनिक सुरक्षा, साझा समृद्धि और अन्य सुरक्षा हितों का विशेष ध्यान रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति में नौसैनिक सुरक्षा हमेशा से सबसे अहम रही है।

आतंकवाद रोधी भूमिका में की सराहना : न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद जैसे खतरनाक मुद्दे पर बेहद अहम भूमिका निभाई है। कूटनीतिक तरीके से संघर्ष बचाने और आतंकवाद की रोकथाम की कोशिशें हुई हैं।

सैंगपो नदी पर चीनी परियोजनाओं से भारत-बांग्लादेश पर पड़ेगा असर

▶ भारत व बांग्लादेश में जल स्तर और उससे संबंधित बातों को लेकर खतरा

बीजिंग, एएनआइ : चीन में यारलुंग सैंगपो नदी पर पनबिजली परियोजना बनाने को लेकर निचले नदी क्षेत्र वाले देशों की नदी परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई गई है। भारत और बांग्लादेश में ताजे पानी का यह अहम स्रोत है।

ब्रह्मपुत्र के ऊपरी इलाकों में बहने वाली यारलुंग सैंगपो नदी का बहाव दक्षिण-पूर्वी कैलास पर्वत से लेकर तिब्बत स्थित मानसरोवर तक है। यह निचले इलाकों में दक्षिणी तिब्बत घाटी से होते हुए उतरती है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में उतरने से पहले ग्रैंड कैनन दर्रे से गुजरती है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह प्रभावित होगा। यह नदी बांग्लादेश में उतरने पर जमुना कहलाती है। भारत में पूर्वोत्तर के दोनों राज्य और बांग्लादेश में आकर यारलुंग सैंगपो तब ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में बनने वाले कई छोटी-बड़ी पनबिजली परियोजनाओं के चलते भारत और बांग्लादेश में जल स्तर और उससे संबंधित अन्य बातों को लेकर खतरा मंडरा रहा है।

टोरंटो के थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फार राइट्स एंड सिक्योरिटी (आइएफएफआरएएस) ने आग्रह किया कि पनबिजली बांधों को बिना ऊपरी धाराओं और निचली धाराओं के ईको-सिस्टम के बारे में विचार किए बनाने की तैयारी है। इन क्षेत्रों में बांध बनाए जाने से आसपास और सुदूर क्षेत्रों में अहम आर्थिक और पर्यावरण संबंधी संकट खड़ा हो जाएगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपने फायदे के लिए यारलुंग सैंगपो नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना पूरा नियंत्रण चाहता है। इससे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्भर राज्य अरुणाचल प्रदेश व असम और बांग्लादेश पर राजनीतिक और पर्यावरण के क्षेत्र में बेहद बुरा असर पड़ेगा।

चीन का भारतीय चालक दल वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अनौपचारिक रोक से इन्कार

बीजिंग, प्रेट्र : चीन ने मंगलवार को इस बात से इन्कार किया कि भारतीय चालक दलों वाले व्यापारिक जहाजों पर अनाधिकृत तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि संबंधित विभागों से विचार-विमर्श के बाद यह स्पष्ट हो गया कि चीन ने कभी भी ऐसे प्रतिबंध लगाए ही नहीं थे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट असंगत है।

हाल ही में आल इंडिया सीफेयरर एंड जनरल वर्क्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मांग करते हुए कहा था कि भारत सरकार हजारों भारतीय नाविकों की नौकरियों की रक्षा करे क्योंकि कंपनियां उन्हें चीन की ओर जाने वाले जहाजों के लिए नियुक्त नहीं कर रही हैं। इससे पहले दो भारतीय जहाजों का मार्ग बदल दिया गया था क्योंकि चालक दल के सदस्यों को बदलने के लिए उन्हें चीनी बंदरगाहों पर कई महीनों का इंतजार करना पड़ता था।

जन्म चीन में, परवरिश लंदन में, पदक कनाडा के लिए

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक में इन दिनों महिला एथलीट हर दिन कोई ना कोई कीर्तिमान रच रही हैं। ऐसी ही एक एथलीट हैं कनाडा की तैराक मैगी मैकनिल। उन्होंने जैसे ही स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, वैसे ही वह इंटरनेट मीडिया पर छा गईं। खास बात यह है कि उनका जन्म चीन में हुआ, परवरिश लंदन में, लेकिन पदक उन्होंने कनाडा के लिए जीता।


मैगी मैकनिल • एपी

चीन में मैगी के जन्म के बाद उनके माता-पिता ने उन्हें अनाथालय में छोड़ दिया था। यहीं से मैगी की किस्मत ने मोड़ लिया और उन्हें कनाडाई दंपती एडवर्ड मैकनील और सुसान मैकनेयर ने गोद ले लिया। यह कनाडाई दंपती मूल रूप से लंदन के निवासी थे और कुछ समय बाद ही वे मैगी को लेकर लंदन चले गए। लंदन में ही मैगी की परवरिश हुई और वहीं उन्होंने तैराकी सीखी।

ओलिंपिक की 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 21 वर्षीय मैगी ने 55.59 सेकेंड के साथ कनाडा को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। संयोग से स्वर्ण पदक के मुकाबले में उन्होंने अपने जन्म देश चीन की झांग युफेई (55.64 सेकेंड) को हराया।

चीनी योजना का शिकार बनी थीं मैगी : दरअसल पिछली सदी के नौवें दशक में चीन ने देश की बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए एक संतान योजना लागू कर दी थी। इसका शिकार बेटियां हुईं, क्योंकि लड़के की चाहत में चीनी दंपती पहली संतान के रूप में होने वाली लड़की की भ्रूण हत्या करवा देते थे या फिर जन्म के बाद ही उन्हें अनाथालय में छोड़ आते थे। मैगी भी इसी योजना का शिकार बनी थीं।


इजरायली खिलाड़ी तोहार बत्बल • रायटर

इजरायल के प्रतियोगी से लड़ने के बजाय खिलाड़ी ने छोड़ दिया ओलिंपिक

टोक्यो, एपी : टोक्यो ओलिंपिक में इजरायल के खिलाड़ी का सामना करने से एक और खिलाड़ी ने मना कर दिया। सूडान के जूडो खिलाड़ी मुहम्मद अब्दुलरसूल ने इजरायल के खिलाड़ी तोहार बत्बल से लड़ने से इन्कार कर दिया है और ओलिंपिक से खुद ही बाहर हो गया। दरअसल 73 किलोग्राम वर्ग में मुहम्मद अब्दुलरसूल को इजरायल के तोहार बत्बल का सामना करना था। वहीं अब्दुलरसूल को पहले राउंड में अल्जीरिया के खिलाड़ी फ़ेतही नूरीन का सामना करना था मगर फ़ेतही ने भी इजरायली खिलाड़ी तोहार बत्बल से लड़ने की संभावना के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि अफ्रीकी विजेता को इसके बाद अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति ने प्रतिबंधित कर दिया और वापस भेज दिया। नुरीन ने खेलने से मना करने के बाद कहा था कि हमने ओलिंपिक तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है लेकिन फलस्तीनियों का मुद्दा इस सब से बड़ा है। हालांकि अभी तक इसकी जानकारी नहीं है कि अब्दुलरसूल ने ओलिंपिक क्यों छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि सूडान के इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्ते हैं।

तीन घंटे तक समंदर में तैरी युसरा, अब लिया ओलिंपिक में भाग

टोक्यो : 100 मीटर स्पर्धा में जैसे ही सीरिया की युसरा मर्दानी ने शरणार्थी ओलिंपिक टीम से भाग लिया उनके संघर्ष की कहानी फिर चर्चा का विषय बन गई। सीरिया से रियो ओलिंपिक और उसके बाद फिर टोक्यो ओलिंपिक तक के सफर में उन्होंने कई पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना किया। 2016 रियो ओलिंपिक के दौरान युसरा 17 साल की थी। तब सीरिया में गृहयुद्ध चल रहा था। वह तीन घंटों तक खुले समंदर में तैरती रहीं और डूबती बोट में से लोगों को बचाती रहीं। फिर वह ग्रीस से लेकर जर्मनी तक पैदल भी गईं। इन समस्याओं से पार पाते हुए उन्होंने 100 मीटर बटलफलाई स्पर्धा में भाग लिया। हालांकि वह पिछली बार की तरह इस बार भी पदक पर कब्जा जमाने में असफल रहीं। >>


युसरा मर्दानी • ट्विटर

ओलिंपिक से बाहर हुईं जापान की नाओमी ओसाका

टोक्यो : चार बार की ग्रैंडस्लैम विजेता जापान की नाओमी ओसाका का सफर खत्म हो गया है। ओसाका को चेक गणराज्य की मारकेटा वोंद्रोसोवा, जो कि 2019 फ्रेंच ओपन के उप विजेता भी हैं। उन्होंने तीसरे दौर में 6-1, 6-4 से ओसाका को हरा दिया। नाओमी के बाहर होने के साथ ही, ओलिंपिक में डब्ल्यूटीए सिंगल्स रैंकिंग में शामिल शीर्ष तीन खिलाड़ी पदक की दौड़ से बाहर हो गई हैं। दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी आस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी, स्पेन की सारा सोरिब्स टोरमो से हार कर पहले ही बाहर हो चुकी हैं। बेलारूस की नंबर-तीन आर्यना सबलेंका भी बाहर हो चुकी हैं। अमेरिका की नंबर-चार सोफिया केनिन और कनाडा की नंबर-पांच खिलाड़ी बियांका आंद्रेस्कू ने ओलिंपिक में भाग नहीं लिया है, जिसके चलते यूक्रेन की नंबर-छह रैंक वाली एलिना स्वितोलिना अब ड्रा में सबसे अव्वल रैंकिंग वाली खिलाड़ी हैं। >>


नाओमी ओसाका • एपी

रूपिंदर के दो गोल से जीता भारत

- स्पेन को 3-0 से हराया
- सिमरनजीत का एक गोल

पदक तालिका

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
जापान	10	3	5	18
अमेरिका	9	8	8	25
चीन	9	5	7	21
आरओसी	7	7	4	18
ग्रेट ब्रिटेन	4	5	4	13
द. कोरिया	3	2	5	10
आस्ट्रेलिया	3	1	5	9
कनाडा	2	3	3	8
फ्रांस	2	2	3	7
जर्मनी	2	0	3	5
भारत	0	1	0	1

नोट : भारत तालिका में 39वें स्थान पर है।

टोक्यो, प्रेट्र : ड्रैगफ्लिकर रूपिंदर पाल सिंह (15वें और 51वें मिनट) के दो गोल की बदौलत भारत ने मंगलवार को यहां ओलिंपिक की पुरुष हाकी स्पर्धा में जोरदार वापसी की। पिछले मैच में आस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी शिकस्त झेलने वाली भारतीय टीम ने पूल-ए में मंगलवार को अपने तीसरे मैच में दुनिया की नौवें नंबर की टीम स्पेन को 3-0 से हराया। भारत की ओर से एक अन्य गोल सिमरनजीत सिंह (14वें मिनट) ने किया। भारत अपने अगले मैच में गुरुवार को गत चैंपियन अर्जेंटीना से भिड़ेगा।

मनप्रीत सिंह की अगुआई वाली भारतीय टीम शुरुआती 10 मिनट में गेंद को अधिक समय तक अपने कब्जे में रखने में सफल रही। स्पेन ने 12वें मिनट में पहला पेनाल्टी कार्नर हासिल किया, जो बर्बाद चला गया। पहले क्वार्टर के अंतिम लम्हों में भारत ने हमले तेज किए। टीम को इसका फायदा भी मिला, जबकि स्पेन के रक्षण की कमजोरी का फायदा उठाकर अमित रोहिदास के पास पर सिमरनजीत ने गोलकीपर क्विको कोर्टेस को छकाकर गोल दाग दिया। भारत को अंतिम मिनट में लगातार तीन पेनाल्टी कार्नर मिले। तीसरे पेनाल्टी कार्नर पर हरमनप्रीत के शाट पर गेंद स्पेन के डिफेंडर से टकराई और भारत को पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे रूपिंदर ने गोल में बदल दिया।

स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में भारतीय रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाया और अधिकांश समय खेल भारतीय हाफ में खेला गया। स्पेन को दबाव की रणनीति का फायदा तीसरे क्वार्टर में तीन पेनाल्टी कार्नर के रूप में मिला, लेकिन भारतीय रक्षा पंक्ति ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। दो गोल की बढ़त के बाद भारतीय टीम चौथे और अंतिम क्वार्टर में रक्षात्मक खेल दिखाकर संतुष्ट थी। भारत को 51वें मिनट में मैच का चौथा पेनाल्टी कार्नर मिला, जिसे रूपिंदर ने गोल में बदलकर भारत को 3-0 से आगे कर दिया जो निर्णायक स्कोर साबित हुआ। स्पेन ने 53वें मिनट में लगातार तीन पेनाल्टी कार्नर मिले, लेकिन ड्रैगफ्लिकर पाउ क्युमादा भारतीय रक्षा पंक्ति को भेदने में नाकाम रहे। स्पेन को अंतिम मिनट में एक और पेनाल्टी कार्नर मिला, लेकिन इस बार भी श्रीजेश ने क्युमादा के प्रयास को नाकाम कर दिया।



जीत के बाद खुश रूपिंदर पाल सिंह • रायटर

पदक से एक जीत दूर लवलीना

भारतीय महिला मुक्केबाज ने नेदिन एपेट्ज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही बोरगोहेन का पदक हो जाएगा पक्का

टोक्यो, प्रेट्र : पहली बार ओलिंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन (69 किग्रा) ने यहां जर्मनी की अनुभवी नेदिन एपेट्ज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मंगलवार को रिंग में उतरने वाली एकमात्र भारतीय मुक्केबाज लवलीना ने प्री-क्वार्टर फाइनल में अपने से 12 साल बड़ी एपेट्ज को 3-2 से हराया। अब वह ओलिंपिक में पदक जीतने से एक जीत ही दूर हैं। वह शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में ताइवान की नीन चेन-चेन से भिड़ेंगी और इसे जीतकर ही उनका पदक पक्का हो जाएगा।

लवलीना और नेदिन ओलिंपिक में पदार्पण कर रही थी और लवलीना भारत की नौ सदस्यीय टीम से अंतिम आठ में जगह बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनीं। तनाव भरे मुकाबले में 23 साल की लवलीना ने शानदार जज्बा दिखाया और बेहद करीबी अंतर से जीत दर्ज करने में सफल रहीं। मुक्केबाजी स्पर्धा में क्वालीफाई करने वाली जर्मनी की पहली महिला मुक्केबाज 35 साल की एपेट्ज दो बार विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता और पूर्व यूरोपीय चैंपियन हैं। लवलीना विश्व चैंपियनशिप में दो और एशियाई चैंपियनशिप में एक बार की कांस्य पदक विजेता हैं। असम की लवलीना ने शुरुआती दौर में आक्रामक खेल दिखाया लेकिन, इसके बाद रणनीति बदलते हुए इंतजार करने का फैसला किया। इस रणनीति ने काम किया लेकिन जर्मन मुक्केबाज ने अपने सटीक मुक्कों से कई बार लवलीना को परेशान किया। लवलीना ने बायें हाथ से दमदार मुक्के बरसाकर अपना पलड़ा भारी रखा। एपेट्ज जर्मनी के मुक्केबाजी जगत में बड़ा नाम हैं। वह न्युरोसाइंस में पीएचडी कर रही हैं जिसे ओलिंपिक की तैयारी के लिए उन्होंने एक साल के लिए रोक दिया था। उन्होंने पिछले साल यूरोपीय क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाकर ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई किया था।



प्री-क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान लवलीना • एपी

शरत की हार के साथ टेटे में भारतीय चुनौती समाप्त


मैच के दौरान शरत कमल • रायटर

टोक्यो, प्रेट्र : अपने अनुभव, कौशल और जज्बे का अच्छा नमूना पेश करने के बावजूद भारतीय स्टार अचंता शरत कमल मंगलवार को यहां चीन के मौजूदा ओलिंपिक और विश्व चैंपियन मा लांग से 1-4 से हार गए जिससे भारत की टोक्यो ओलिंपिक खेलों की टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चुनौती भी समाप्त हो गई। अपना चौथा ओलिंपिक खेल रहे 39 वर्षीय शरत ने तीसरे दौर के इस मैच में अपने मजबूत प्रतिद्वंद्वी को पहले तीन गेम में कड़ी चुनौती दी लेकिन, आखिर में उन्हें 46 मिनट तक चले मैच में 7-11, 11-8, 11-13, 4-11, 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। शरत और मनिका बत्रा मिक्स्ड डबल्स में पहले ही बाहर हो गए थे। मनिका भी महिला सिंगल्स में तीसरे दौर से आगे बढ़ने में नाकाम रही थी। जी साथियान और सुतीर्था मुखर्जी भी अपने सिंगल्स मैचों में शुरू में ही हार गए थे।

सात्विक और चिराग जीत के बावजूद नाकआउट से बाहर

टोक्यो : सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन पुरुष डबल्स ग्रुप-ए के अपने तीसरे मैच में बेन लेन और सीन वेंडी की ब्रिटेन की जोड़ी को हराया लेकिन, इसके बावजूद नाकआउट में जगह बनाने में नाकाम रहे। सात्विक और चिराग की दुनिया की 10वें नंबर की जोड़ी ने लेन और वेंडी की दुनिया की 18वें नंबर की जोड़ी को 44 मिनट तक चले मुकाबले में 21-17, 21-19 से हराकर ग्रुप में दूसरी जीत दर्ज की। वहीं एक और मुकाबले में चीनी ताइपे की यैंग ली और ची लिन वैंग की तीसरे नंबर की जोड़ी ने मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजय सुकामुल्जो की इंडोनेशिया की नंबर एक जोड़ी को 21-18, 15-21, 21-17 से हरा दिया जिससे सात्विक और चिराग महाकुंभ से बाहर हो गए। भारत, इंडोनेशिया और चीनी ताइपे तीनों जोड़ियों ने दो-दो जीत दर्ज की थी लेकिन, चीनी ताइपे और इंडोनेशिया की जोड़ियां ग्रुप चरण में बेहतर अंतर के कारण शीर्ष दो स्थान पर रहते हुए नाकआउट में पहुंचने में सफल रही।


चिराग शेट्टी • एपी

निशाने पर निशानेबाज

- सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी ने किया निराश
- एनआरएआइ कोचिंग सदस्यों की पूरी टीम में करेगा बदलाव

टोक्यो, प्रेट्र : ओलिंपिक निशानेबाजी में एक बार फिर शीर्ष खिलाड़ियों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) ने कोचिंग सदस्यों को पूरी तरह से बदलने का वादा किया। रियो ओलिंपिक की तरह टोक्यो में भी भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। भारत के रिकार्ड 15 निशानेबाजों ने इन खेलों का टिकट कटाया था लेकिन, कोई नहीं जीत सका। अब टीम में गुटबाजी की खबरें भी सामने आ रही हैं।

एनआरएआइ के प्रमुख रनिंदर सिंह ने कहा, 'निश्चित रूप से प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं है और मैंने कोचिंग और सहयोगी सदस्यों में बदलाव की बात कही है।' निशानेबाज आइएसएसएफ विश्व कप के अपने शानदार प्रदर्शन को ओलिंपिक में दोहराने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे निशानेबाजों को इन बड़े मौकों के लिए तैयारी करने में कुछ कमी है, क्योंकि स्पष्ट रूप से उनमें प्रतिभा है और हमने इसे यहां भी देखा है। महासंघ और अन्य संबंधित हितधारकों ने खेलों के लिए निशानेबाजों को तैयार करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया।' मनु भाकर का जूनियर राष्ट्रीय कोच जसपाल राणा के साथ मनमुटाव होने के बाद भारत के पूर्व निशानेबाज और कोच रौनक पंडित उन्हें प्रशिक्षित कर रहे थे। सिंह ने कहा कि एनआरएआइ उन दोनों के बीच चीजों को सुलझाने की कोशिश की थी।


मिक्स्ड टीम स्पर्धा में हार के बाद निराश मनु भाकर और सौरभ चौधरी • प्रेट्र

क्वालीफिकेशन से ही बाहर सौरभ और भाकर

भारत को मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं से पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। सौरभ चौधरी और मनु भाकर की जोड़ी को 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन, क्वालीफिकेशन के पहले चरण में शीर्ष पर रहने के बाद दूसरे चरण में वे लय में नहीं दिखे और आखिर में सातवें स्थान से संतोष करना पड़ा। अभिषेक वर्मा और यशस्विनी सिंह देसवाल की एक अन्य भारतीय जोड़ी इस स्पर्धा के पहले चरण में 564 अंक के साथ 17वें स्थान पर रहने के कारण शुरू में ही बाहर हो गई। भारत की दो जोड़ियों ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी हिस्सा लिया था लेकिन, वे क्वालीफिकेशन के पहले चरण से भी आगे नहीं बढ़ पाई। इलावेनिल वालारिवान और दिव्यांश सिंह पंवार की जोड़ी 626.5 अंक बनाकर 12वें तथा अंजुम मोदगिल और दीपक कुमार की जोड़ी 623.8 अंक बनाकर 29 जोड़ियों के बीच 18वें स्थान पर रही। ओलिंपिक में पहली बार मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं को शामिल किया गया है।

कर्माकर बोले, अब मैं इसे आपदा कहूंगा : परिणामों से निराश जायदीप कर्माकर और हीना सिद्धू जैसे जाने-माने निशानेबाजों और ओलिंपियन ने ट्वीट कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। लंदन ओलिंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूकने वाले कर्माकर ने ट्वीट किया कि अब मैं इसे आपदा कहूंगा! यह निशानेबाजी में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी और इसके लिए किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए। मैं निराश हूं? सभी निराश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निराश कौन है? कृपया अनावश्यक ट्रोल और अपमान से बचें। उनमें से कुछ असफल रहे और आलोचना का सामना करेंगे और यह हर प्रदर्शन करने वाले के जीवन का हिस्सा है।' कर्माकर ने कहा कि टीम के कम उम्र वाले (किशोर) निशानेबाजों को बच्चा कह कर उन्हें कमजोर नहीं आंका जाना चाहिए।

निराशा | सिमोन ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देकर नाम लिया वापस

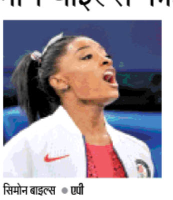
गत चैंपियन सिमोन बाइल्स फाइनल से हटीं

टोक्यो, एपी : अमेरिका को अपनी धुरंधर जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स के बाहर होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति) ने टोक्यो ओलिंपिक की महिला जिम्नास्टिक टीम स्पर्धा में अमेरिकी दबदबे को तोड़कर स्वर्ण पदक जीत लिया। आरओसी ने अजेय मानी जा रही अमेरिकी टीम को 3.5 के अंतर से हराया, जो काफी बड़ा अंतर है।

चार राउंड में आरओसी की व्लादिस्लावा उराजोवा, विक्टोरिया लिस्टुनोवा और एंजेलिना मेलनिकोवा ने कुल 169.528 अंक हासिल किए, जिसमें गत चैंपियन टीम अमेरिका को 166.096 के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा, क्योंकि उनकी खिलाड़ी बाइल्स ने मानसिक बीमारी के चलते अपना नाम स्पर्धा के बीच में ही वापस ले लिया। वही ग्रेट ब्रिटेन की टीम ने 164.096 के अंकों के साथ कांस्य पदक जीता।

अमेरिका की टीम में बाइल्स के लिए तब मुसीबतें खड़ी हुईं, जब बाइल्स अभ्यास के समय ही वाल्ट में दो और आधा ही ट्विस्ट कर सकीं। इसके बाद एक और आधा ट्विस्ट करने के बाद वह फिर से गलतियां दोहराने लगीं और 13.733 का स्कोर करने के बाद उन्होंने नाम वापस ले लिया।

इससे एक दिन पहले ही रूस की पुरुष टीम ने भी इस स्पर्धा का फाइनल जीता था। डोपिंग प्रकरण के कारण रूस ओलिंपिक में अपने देश के नाम, ध्वज या राष्ट्रगीत का प्रयोग नहीं कर सकता है।


सिमोन बाइल्स • एपी

13.766 का वाल्ट स्कोर बाइल्स ने स्पर्धा में हटने से पहले किया, जो उनका ओलिंपिक में अब तक का सबसे न्यूनतम स्कोर है

> मैंने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हमें अपने दिमाग और शरीर की रक्षा करनी है, ना कि केवल बाहर जाकर वह करना है जो दुनिया हमें करते देखना चाहती है।
>
> **सिमोन बाइल्स**, अमेरिकन जिमनास्ट

2010 के बाद जिमनास्ट की प्रमुख स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक हासिल नही कर पाया है अमेरिका

4 स्वर्ण पदक जिमनास्ट में सिमोन बाइल्स ने 2016 रियो ओलिंपिक में अपने नाम किए थे

मनिका के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : टोक्यो ओलिंपिक के दौरान राष्ट्रीय कोच सौम्यदीप राय से मदद लेने के मनिका बत्रा के इन्कार को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ (टीटीएफआइ) ने अनुशासनहीनता करार देते हुए कहा कि अगले महीने कार्यकारी बोर्ड की बैठक के दौरान उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राष्ट्रमंडल खेल 2006 की टीम स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त राय टोक्यो में चार सदस्यीय टीम के साथ अकेले कोच हैं। मनिका अपने निजी कोच सन्मय परांजपे को लेकर गई हैं लेकिन, उन्हें प्रतियोगिता स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। टीटीएफआइ के महासचिव अरुण कुमार बनर्जी ने कहा, 'यह अनुशासनहीनता है। उन्हें अपने मैचों के दौरान राष्ट्रीय कोच को कोर्ट के पास बैठने की अनुमति देना चाहिए थी, जैसा बाकी खिलाड़ियों ने किया। राय भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से हैं और अब जाने माने कोच हैं। कार्यकारी बोर्ड की आनलाइन बैठक जल्दी ही होगी।'

भारत के आज के मैच

तीरंदाजी (व्यक्तिगत स्पर्धा)
खिलाड़ी : • तरुणदीप राय, सुबह 7:31 बजे से • प्रवीण जाधव, दोपहर 12:30 बजे से • दीपिका कुमारी, दोपहर 2:14 बजे से

बैडमिंटन : • महिला सिंगल्स, सुबह 7:30 बजे से • **खिलाड़ी** : पीवी सिंधू • पुरुष सिंगल्स, दोपहर 2:30 बजे से • **खिलाड़ी** : बी साई प्रणीत

हाकी : • महिला टीम, पूल-ए, सुबह 6:30 बजे से, बनाम ब्रिटेन

रोइंग : • पुरुष लाइटवेट डबल्स स्कल्स सेमीफाइनल, सुबह 8:00 बजे से • **खिलाड़ी** : अर्जुन लाल जाट और अरविंद

सेलिंग : • पुरुष स्किफ 49ईआर रेस 1, सुबह 8:35 बजे से • **खिलाड़ी** : केसी गणपति और वरुण ठक्कर

मुक्केबाजी : • महिला, अंतिम-16, दोपहर 2:33 मिनट से • **खिलाड़ी** : पूजा रानी

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

पदक के साथ लौट सकते हैं मुक्केबाज

विजेंद्र सिंह कलम से



ओलिंपिक खेल अभी तक हमारे लिए मिले-जुले रहे। मीराबाई चानू के भारोत्तोलन में जीते गए रजत पदक ने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। अन्य कई खेलों में निराशा भी हाथ लगी, लेकिन फिर हमने भारतीय हाकी टीम को आस्ट्रेलिया से मिली शिकस्त से वापसी करते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज करते भी देखा। जिस तरह लवलीना ने मंगलवार को जर्मनी की नेदिन एपेट्ज के खिलाफ 3-2 से जीत दर्ज की, उससे भी मैं काफी प्रभावित हुआ। उन्होंने अपना अंदाज कुछ बदला, ताकि स्कोरिंग पर ध्यान लगाया जा सके। अगर उन्हें ओलिंपिक पदक जीतना है तो एक और कड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत दर्ज करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा।

अपने पहले मुकाबले में प्रभावशाली जीत दर्ज करने के बाद एमसी मेरी काम का सामना अब इनग्रिट वेलेंसिया से होगा। कोई कारण नहीं है कि मेरी काम इस मुकाबले में जीत दर्ज ना कर सकें, हालांकि यह मुकाबला बेहद शानदार होगा। सिमरनजीत कौर एक और प्रतिभाशाली महिला मुक्केबाज हैं। अच्छा होगा अगर भारतीय खिलाड़ी टोक्यो में अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान ना देकर सिर्फ अपने मुकाबलों पर ध्यान केंद्रित करें। तीन ओलिंपिक खेलों में हिस्सा लेने के अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि दल के अन्य सदस्य पदक जीतते हैं या नहीं, इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना सारा ध्यान इस बात पर लगाता कि मुझे क्या करने की जरूरत है। लाइटवेट वर्ग में मनीष कौशिक ने ल्यूक मैक्कोरमैक के खिलाफ अच्छी फाइट लड़ी, लेकिन स्पिलिट फैसले में उन्हें हार मिली। एरबिएक टुओहेता के खिलाफ आशीष कुमार की हार ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अब पुरुष मुक्केबाजी में सिर्फ अमित पंघाल ही भारतीय चुनौती पेश करने के लिए बाकी रह गए हैं। उन्हें 2016 के रजत पदक विजेता कोलंबिया के युबेरजेन मार्टिनेज का सामना करना है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्री क्वार्टर फाइनल में जीत अमित को ही मिलेगी।

मुक्केबाजी और कुश्ती टीमों में कुछ पदक के साथ देश लौटने की प्रतिभा और क्षमता दोनों है। मैं बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के मुकाबलों को लेकर भी काफी उत्साहित हूं। (टीसीएम)

दैनिक जागरण
सप्तरंग
सेहत भरे जीवन का
बुधवार, 28 जुलाई, 2021



कोरोना को हराना है

जिंदगियां बचाने के लिए अथक प्रयास आवश्यक

करीब 18 महीनों से कोरोना से सुरक्षा के हरसंभव कदम उठाने के बावजूद अभी तक हम महामारी से बचाव के प्रारंभिक चरण में ही हैं। हालांकि टीकाकरण शुरू होने के कारण अति निश्चिंत हो जाना और ढीला रवैया अपनाना साबित हो सकता है बड़ा खतरा...



इन दिनों



डा. पूनम खेत्रपाल सिंह,
क्षेत्रीय निदेशक, डब्ल्यूएचओ,
दक्षिण-पूर्व एशिया

विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में हाल के महीनों में सार्स-कोव-2 संक्रमण में निरंतर वृद्धि देखी गई है। इस साल अप्रैल और मई में हफ्ते दर हफ्ते इस क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। कुछ क्षेत्रों में तो टेस्ट पाजिटिविटी दर 40 फीसद से भी अधिक पाई गई। कई सदस्य देशों में कोरोना के गंभीर वैरिएंट मिले हैं और संभव है कि संक्रमण तेजी से बढ़ने में इनकी भी भूमिका हो। पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 के खिलाफ युद्ध में नाजुक क्षण पर है। कोई देश सुरक्षित नहीं है। सब खतरे की जद में हैं।

सुरक्षा उपायों का हो पालन: अब प्रश्न उठता है कि इस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सबसे पहले, उन सब जनस्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को आक्रामक रूप से लागू करना चाहिए जो प्रभावी साबित हुए हैं और जो नए वैरिएंट के खिलाफ हमें सबसे सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें शारीरिक दूरी का पालन, हाथ धोना और मास्क का सही इस्तेमाल बेहद कारगर हैं। वेंटिलेशन, टेस्टिंग, कांटैक्ट ट्रेसिंग एवं आइसोलेशन- ये सभी वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने, जिंदगियां बचाने और महामारी को कम करने में प्रभावी हैं। हमें निश्चित तौर पर तीन डब्ल्यू यानी वियर मास्क (मास्क पहनना), वाश हैंड (हाथ धोना) और वाच डिस्टेंस (शारीरिक दूरी बनाए रखना) का पालन करना चाहिए। इसी के साथ हमें तीन सी यानी क्राउडेड प्लेस (भीड़भाड़ वाली जगह), क्लोज कांटैक्ट सेटिंग (नजदीकी) और कंफाइंड एंड एनक्लोज्ड स्पेस (बंद जगहों) से भी बचना होगा।

कसनी होगी कमर: अब दूसरा कदम, स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता पर नजर रखना और उसमें विस्तार करना है। जिससे चाहे कितना भी केसलोड हो, यह जनता की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। संक्रमण के मामले बढ़ने की स्थिति में आक्सीजन एवं बेड समेत स्थान, कर्मचारी और आपूर्ति बढ़ाने के लिए चरणबद्ध योजना पर सक्रियता से अमल होना चाहिए और विभिन्न सुविधाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं भी सही ढंग से चलती रहनी चाहिए ताकि जरूरतमंदों तक ये सेवाएं पहुंचती रहें। यह इस क्षेत्र में महामारी से निपटने के प्रमुख बिंदुओं में से प्रमुख है।

हर जरूरत हो पूरी: राष्ट्रीय परिनियोजन और टीकाकरण योजनाओं में परिभाषित प्राथमिक समूहों का टीकाकरण इसका तीसरा कदम है। आपूर्ति से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों के बीच देशों को टीके की उपलब्ध डोज का इस्तेमाल प्राथमिकता वाले समूहों की सुरक्षा में करना चाहिए, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। केवल टीकाकरण ही महामारी को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यह स्वीकार करते हुए भी टीकाकरण को बढ़ावा मिलते रहना चाहिए। यह भी जरूरी है कि जिन देशों के पास वैक्सीन की डोज अधिक मात्रा में है, वे उन्हें कोवैक्स सेवा के साथ साझा करें। कोवैक्स का लक्ष्य वर्ष 2021 के अंत तक विश्व स्तर पर निम्न और मध्यम आयवर्ग वाले देशों को टीके की दो अरब डोज की आपूर्ति करना है।

सबके साथ से बनेगी बात: जाहिर है किसी भी व्यक्ति या समुदाय को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। दुनियाभर में कोविड-19 ने उन समूहों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया जो सामाजिक और आर्थिक कारणों से संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। यह स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि अक्षम्य भी है। इस क्षेत्र के सभी देशों में कोविड-19 से जुड़े फैसले लेते समय समानता को जरूर ध्यान रखना चाहिए। फिर बात चाहे जांच एवं उपचार की हो या सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा की, हमें सख्त कदम उठाने होंगे। महामारी की शुरुआत से ही डब्ल्यूएचओ ने इस क्षेत्र के अपने सदस्य देशों को अहम दिशानिर्देश एवं समर्थन दिया है। इसके तहत हाल के महीनों में हजारों आक्सीजन कंसंट्रेटर, लाखों रेस्पिरेटर मास्क और सहायक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। कोविड-19 टूल्स एक्सलरेटर के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों को लगातार कई जीवनरक्षक लाभ मिल रहे हैं। यह अब तक के इतिहास में सबसे तेज व सर्वाधिक समन्वय वाली सफल वैश्विक सहयोग व्यवस्था है, जिससे कोविड-19 की जांच, इलाज और टीके के मामले में विकास, उत्पादन बढ़ाने और समान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिली।

केवल एकजुटता और क्षेत्रव्यापी संकल्प के माध्यम से ही हम इस संक्रमण को कम करने, नई लहर के लिए तैयार होने और इसे थामने में सक्षम हो सकते हैं। उन सभी के लिए साक्ष्य आधारित उपचार और तकनीक ला सकते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जीवन और आजीविका दोनों दांव पर हैं। हमें सतर्क रहना होगा और अथक प्रयास करने होंगे।

भरोसे की न टूटे डोर

अफवाह और गलत जानकारियों से खतरा और बढ़ता है। यह संक्रमण के प्रसार को बढ़ा सकती हैं और इसके प्रकोप को तेज या और लंबा कर सकती हैं। इनसे भ्रम की स्थिति बन सकती है और समाज में भरोसा टूटने का खतरा हो सकता है। किसी भी महामारी से निपटने में इस भरोसे की भूमिका बहुत अहम होती है। यहां हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कोई भी जानकारी साझा करने से पहले उसके स्रोत की पुष्टि करें और सुनिश्चित करें कि जानकारी विश्वसनीय है। उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी के वाहक बनें। इन जानकारियों को डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट व इंटरनेट मीडिया अकाउंट और राष्ट्रीय एवं स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों के माध्यम से आनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।





शिशुओं में कोरोना से लड़ने की ताकत जगाएं स्तनपान से

विश्व स्तनपान सप्ताह 1-7 अगस्त



डा. मंजुलिका बाजपेयी
वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कानपुर

कोरोना संक्रमण के दौर में नन्हें व नवजात शिशुओं का खयाल रखना भी है एक चुनौती। इसके लिए उन्हें स्तनपान कराना जरूरी है ताकि बेहतर विकास के लिए न सिर्फ उन्हें जरूरी पोषण मिल सके, बल्कि रोगों से लड़ने की ताकत भी मजबूत हो। मां के स्वास्थ्य के लिए भी यह समान रूप से जरूरी है। कोरोनाकाल में स्तनपान के विषय में कई तरह की भ्रांतियों ने जन्म लिया है, जिनकी हकीकत समझना जरूरी है, क्योंकि शिशु के लिए मां का दूध है अमृत...

कोविड-19 वायरस शिशुओं को अपना निशाना बनाने में नाकाम रहा है, यह बेहद सुकून की बात है, पर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देना जरूरी है और यह संभव है सुरक्षित स्तनपान से। मां का दूध शिशु के लिए संपूर्ण पोषण होता है। यह वायरस या बैक्टीरिया से बचाव के लिए उनमें एंटीबाडीज बनाता है साथ ही यह अस्थमा व एलर्जी का खतरा भी कम करता है। शिशु के जन्म के छह माह तक उसे सिर्फ मां का दूध प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद स्तनपान के साथ ही फार्मूला दूध या अन्य तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए।

कोरोना पाजिटिव हों तो भी कराएं स्तनपान: चूंकि कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में यदि मां में कोरोना संक्रमण के लक्षण नजर आएं या कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट आए तो कई बार भ्रांतियों की वजह से वे शिशु को स्तनपान कराना बंद कर देती हैं, पर वास्तव में स्तनपान जारी रखने पर ही बीमारी से बचाव सुनिश्चित होता है। स्तनपान से शिशु में वायरस का संक्रमण होने का खतरा नहीं है। मां के दूध में कोरोना का वायरस नहीं पाया गया है। मां में कोरोना के लक्षण दिखें तो सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए शिशु को स्तनपान अवश्य कराएं। शिशु को गोद में लेने व स्तनपान से पूर्व हाथों को साबुन व पानी से 20 सेकंड तक धोएं। मास्क लगाने के बाद ही शिशु को हाथों में लें। जब भी शिशु के नजदीक जाएं तो हाथों को सैनिटाइज करें व मास्क अवश्य लगाएं।

मां का टीकाकरण: कोविड से बचाव के लिए नवजात शिशुओं की मां के टीकाकरण में कोई खतरा नहीं है। इसी प्रकार गर्भवती स्त्रियों को भी टीका अवश्य लगवाना चाहिए। टीकाकरण के जरिए मां कोविड से सुरक्षित रहेगी तो शिशु भी संक्रमण से मुक्त रह सकेगा। शिशु का कोविड टीकाकरण संभव नहीं है, लेकिन मां के दूध से प्राप्त होने वाली एंटीबाडीज से उसे रोगों से लड़ने की ताकत अवश्य मिलती है। यदि मां को कोरोना संक्रमण हुआ हो तो इलाज के दौरान उसके शरीर में वायरस से लड़ने वाली एंटीबाडीज निर्मित होती हैं। यही एंटीबाडीज मां के दूध के जरिए शिशु तक पहुंचती हैं। टीकाकरण के कुछ समय बाद मांएं शिशु को स्तनपान करा सकती हैं।

मां के लिए भी आवश्यक है स्तनपान कराना: स्तनपान कराना न सिर्फ शिशु, बल्कि मां के लिए भी फायदेमंद है। विशेषकर कोरोनाकाल में इसकी अहमियत बढ़ जाती है। मां कोरोना पाजिटिव है और अगर वह स्तनपान नहीं कराती है तो ब्रेस्ट में इंफेक्शन और इनफ्लेमेशन हो सकता है जो सेप्टिसीमिया उत्पन्न करके कोरोना संक्रमण को और खतरनाक बना सकता है। इसलिए कोरोना पाजिटिव हों तो खासतौर पर स्तनपान अवश्य कराएं। सामान्य परिस्थिति में भी स्तनपान कराना मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्तनपान न कराने से यूट्रस में इंफेक्शन होने का खतरा भी उत्पन्न होता है। स्तनपान कराने से न सिर्फ इससे बचाव सुनिश्चित होता है, बल्कि मां और शिशु में एक खास भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा होता है। शिशु में एक ओर जहां सुरक्षा का बोध उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी ओर मां के शरीर में कई हारमोंस रिलीज होते हैं जो यूट्रस को प्रसव पूर्व का आकार प्राप्त करने में मदद करते हैं। स्तनपान की प्रक्रिया गर्भाधारण के फलस्वरूप मां के बढ़े वजन को घटाने में सहायक होने के साथ ही स्तन कैंसर, ओवेरियन कैंसर व ओस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम करता है। स्तनपान के दौरान मां के शरीर में रिलीज होने वाले हारमोंस उसे सेहतमंद रखने के साथ ही तनाव व चिंताओं से मुक्त रखते हैं।

प्रस्तुति: कीर्ति सिंह

एंटीआक्सीडेंट व प्रोटीन युक्त आहार

नवजात शिशु की मां के आहार में अक्सर आम घरों में घी व गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों को तरजीह दी जाती है, लेकिन कोरोनाकाल में संक्रमण से बचाव में आहार की अहमियत को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ ही एंटीआक्सीडेंट युक्त फलों व मेवों को विशेषरूप से शामिल करना चाहिए। इससे मां को स्वास्थ्यलाभ होने के साथ ही उसके दूध की गुणवत्ता बेहतर होगी, जिससे शिशु स्वस्थ रहेगा और उसे रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी।



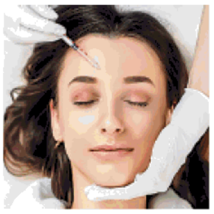
भारतीय चिकित्सा का गौरव है प्लास्टिक सर्जरी

काम की बात



डा. राकेश कुमार खजांची
सीनियर कास्मेटिक सर्जन, मेदांता दि मेडिसिटी, गुरुग्राम

भारतीय चिकित्सा पद्धति में सर्जरी का इतिहास बेहद पुराना है। भारतीयों ने ही प्लास्टिक सर्जरी का हुनर विदेशी चिकित्सकों को सिखाया। बावजूद इसके, आज भी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर अधिकांश लोगों में तमाम भ्रांतियां व्याप्त हैं...



आज भी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर भ्रांति है कि यह केवल उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए है जो इसकी मदद से अपनी सुंदरता में इजाफा कर सकते हैं, जबकि प्लास्टिक सर्जरी का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। दरअसल, अन्य चिकित्सकों की भांति प्लास्टिक सर्जन किसी खास अंग के स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि पूरे शरीर के लिए जिम्मेदार होता है। प्लास्टिक सर्जरी किसी भी अंग की आवश्यकता हो सकती है। इसके अंतर्गत जन्मजात, इंफेक्शन, दुर्घटना, कैंसर या जल जाने के कारण नष्ट या विकृत हुए अंग को दोबारा ज्यादा से ज्यादा असली रूप में लाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शिशुओं के होंठ और तालू की सर्जरी, जन्मजात अविकसित अंगुली, अंगूठा, कान आदि को ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी आज एक बड़ी कारगर तकनीक है। इसी क्रम में आग लगने से जल गए शरीर को बचाने, ठीक करने और दोबारा सुचारू रूप से काम करने लायक बनाने में सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है तो वहीं कैंसर के इलाज में सर्जरी के माध्यम से ही कैंसर प्रभावी हिस्से (प्रमुख तौर पर मुंह, स्तन कैंसर में) को अलग करके दोबारा सामान्य बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि कैंसर से ठीक होने के उपरांत आपरेशन के कारण रोगी का जीवन किसी तरह नकारात्मक तौर पर प्रभावित न होने पाए।

माडर्न सर्जरी से बढ़ा यकीन: प्लास्टिक सर्जरी दो हिस्सों में विभाजित है। पहला, एस्थेटिक सर्जरी और दूसरा, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। एस्थेटिक सर्जरी में सर्जन पहले से सामान्य अंग को और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इन दिनों एस्थेटिक सर्जरी का चलन काफी बढ़ चुका है। हालांकि हमारे देश में अधिकांशतः रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। माइक्रोसर्जरी ने आधुनिक सर्जरी की दुनिया में बेहतर करने का मौका दिया है। इसके अंतर्गत सर्जन एक मिलीमीटर लंबाई की रक्त वहिकाओं को जोड़ने की कला में भी सफल हो चुके हैं। इस कौशल में सर्जन कटी हुई अंगुलियों और हाथों को फिर से जोड़ने और ऊतकों को स्थानांतरित करने में सक्षम हो चुके हैं। इससे कई अंग जो अन्यथा बेकार हो जाते, वे दोबारा काम करने लायक सुरक्षित कर लिए जाते हैं।

इसी तरह डायबिटीज के साथ जी रहे लोगों के लिए तो प्लास्टिक सर्जरी ने बड़ा योगदान दिया है। दरअसल, डायबिटीज के करीब 25 प्रतिशत मरीज जीवनकाल में फुट अल्सर की तकलीफ झेलते हैं। इनमें से 50 प्रतिशत मामलों में यह समस्या गंभीर हो जाती है तो 20 प्रतिशत मामलों में अंग विच्छेदन तक करना पड़ता है। अधिकांशतः यह स्थिति न्यूरोपैथी की वजह से भी आ जाती है जिसके चलते पैरों में संवेदना का पता नहीं लगता और वक्त के साथ तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि पैरों का आकार बदलने लगता है। शरीर का वजन उठाने में असमर्थता के चलते यह समस्या बढ़ने लगती है। ऐसे में प्लास्टिक सर्जन पैरों के अल्सर की सर्जरी कर इस स्थिति को खत्म कर देते हैं। कुल मिलाकर हमें प्लास्टिक सर्जरी के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को बदलने की जरूरत है।

हेल्थ फाइल

शरीर के लिए जरूरी है कैल्शियम

मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र व अच्छी सेहत के लिए भोजन में कैल्शियम को शामिल करें। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होने के साथ कई अन्य समस्याएं भी आने लगती हैं...



मनुष्य के शरीर का आधार हड्डियां हैं और हड्डियों के निर्माण में अहम भूमिका है कैल्शियम की। हड्डियों से संबंधित लगभग हर बीमारी की वजह होती है हमारे आहार में कैल्शियम की कमी। यह कमी शरीर में एक दिन में नहीं, बल्कि लगातार खानपान में लापरवाही के चलते पर्याप्त मात्रा में शरीर को कैल्शियम न मिलने के कारण बीमारियों के रूप में सामने आती है। आमतौर पर लोगों को मानना है कि सिर्फ दूध या दही का सेवन करने से शरीर को कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। इससे शरीर को कैल्शियम तो मिलता है, पर उतनी मात्रा में नहीं, जितना कि उचित पोषण के लिए शरीर को चाहिए। कैल्शियम के कम होने का प्रारंभिक लक्षण हड्डियों में दर्द, जकड़न, थकान, मांसपेशियों में खिंचाव आदि के रूप में दिखाई पड़ता है। कमर का झुक जाना, पिंडलियों में अचानक असहनीय दर्द होना, बालों का झड़ना, दांतों में संक्रमण, नाखूनों का फटना आदि समस्याएं शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम न मिलने से होती हैं। यदि 30 वर्ष से पहले ही हड्डियों से जुड़ी किसी तरह की समस्या होती है तो काफी संभावना है कि इसकी वजह कैल्शियम की कमी ही है।

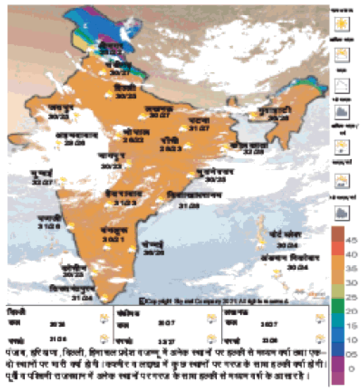
स्तनपान कराने वाली महिलाओं में जोड़ों की बीमारियां या थकान की मूल वजह कैल्शियम की कमी ही होती है। इनके शिशुओं में भी कैल्शियम की कमी के कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। महिलाओं व पुरुषों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आस्टियोपोरोसिस बीमारी का कारण भोजन में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम को शामिल न करना है। इसकी कमी से हड्डियां एक-दूसरे से अच्छी बांडिंग नहीं बना पाती हैं। इससे इनके टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक इसकी कमी ऐसी बीमारियों की वजह भी बनती है, जिनका उपचार भी लंबे समय तक कराना पड़ता है। विटामिन डी के साथ मिलकर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाले कैल्शियम की कमी से व्यक्ति बार-बार बीमार भी पड़ने लगता है।

कई शोधों से यह बात साबित हो चुकी है कि ब्लड प्रेशर, कई प्रकार के कैंसर, बालों का झड़ना, कोलेस्ट्राल के स्तर का असंतुलित होना आदि कैल्शियम की कमी से ही होता है।

ओनली माई हेल्थ.काम

इनमें है प्रचुर मात्रा में कैल्शियम

- दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों को भोजन का हिस्सा बनाएं।
- हरी और पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम का बेहतर स्रोत हैं।
- केला, संतरे का जूस और खट्टे फलों का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए।
- सोयाबीन से बनी चीजें और कार्न फ्लैक्स में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
- मूंगफली, सूरजमुखी, मटर आदि कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं।





भारत में पहली बार पहचान के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल

वर्ष 1858 में आज ही पहचान के लिए भारत में फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल हुआ था। बंगाल में तैनात ब्रिटिश अधिकारी सर विलियम जेम्स हर्शेल ने एक सौदे के समय दस्तावेज पर व्यवसायी की अंगुलियों के निशान लिए थे।





भूकंप से चीन में करीब ढाई लाख लोगों की चली गई जान

वर्ष 1976 में आज ही चीन में सुबह 3:42 बजे 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें करीब ढाई लाख लोगों की मौत और सात लाख से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कई जगह सड़कें, घर, पुल सभी टूट गए थे। बीजिंग में स्थित तांगशान शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था।

एक हत्या ने दुनिया को पहले विश्व युद्ध में झोंक दिया

1914 में आज ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 28 जून, 1914 को आस्ट्रिया-हंगरी के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की सर्बियाई शख्स ने हत्या कर दी थी। इसके बाद आस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का एलान कर दिया। इसके बाद दुनिया के कई देश अपने-अपने गुटों के समर्थन में आ गए, जिसमें केंद्रीय शक्तियों और मित्र देशों के बीच युद्ध हुआ। 11 नवंबर, 1918 तक चले युद्ध में लाखों लोगों की मौतें हुईं। मित्र देशों की जीत हुई। इस युद्ध के परिणामस्वरूप कई देशों की सीमाएं बदल गईं।



इधर-उधर की

छह साल पहले गायब बिल्ली माइक्रोचिप से मिली

मैसाच्युसेट्स, एजेंसी : तकनीक के चलते सभी काम संभव हो गए हैं। अमेरिका के मैसाच्युसेट्स से आई खबर इसी बात की बानगी है। यहां छह साल पहले घर से लापता हुई बिल्ली माइक्रोचिप की मदद से वापस मिल गई। इसकी मालकिन मार्गरेट कुडज्मा ने इसे चमत्कार बताया। उन्होंने कहा, 2015 में वह गायब हो गई थी। उसकी तलाश में जगह-जगह पोस्टर लगाए, अखबारों में विज्ञापन दिए, इंटरनेट मीडिया पर कैंपेन चलाए, पर वह नहीं मिली। मैं पिछले हफ्ते उस समय हैरान रह गई, जब एक डाक्टर ने मुझे फोन कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बिल्ली में लगी एक माइक्रोचिप से मेरी जानकारी जुटाई थी। एक परिवार बिल्ली की देखभाल कर रहा था जो उसके कान में परेशानी के बाद उसका इलाज कराने क्लीनिक लाया था।



बिल्ली को इलाज के लिए क्लीनिक लाया गया था। इंटरनेट मीडिया

टीबी से बचाव के लिए मिलेगा नया टीका

अध्ययन ▶ बैक्टीरिया के प्रति इम्यून सेल की प्रतिक्रिया का मिला नया विवरण

अन्य संक्रामक रोगों के इलाज में भी मिलेगी मदद

न्यूयार्क, एएनआइ : टुबर्क्यलोसिस यानि टीबी के इलाज को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक नए अध्ययन से बड़ी उम्मीद जगी है। शोधकर्ताओं ने इसके इलाज के लिए एक नए टीके की रणनीति का मार्ग प्रशस्त किया है। विज्ञानियों ने इसका विश्लेषण किया है कि टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से प्रतिरक्षी कोशिकाएं (इम्यून सेल्स) किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। इसके आधार पर अन्य संक्रामक रोगों से भी लड़ने में मदद मिल सकती है।

इसकी अत्याधुनिक तकनीक का विकास डाक्टर डेविड रसेल लैब में किया है। इस शोध का विस्तृत विवरण 22 जुलाई को जर्नल आफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है। रसेल लैब वर्षों से यह पता लगाने में जुटा है टीबी पैदा करने वाला माइकोबैक्टीरियम टुबर्क्यलोसिस (एमटीबी) किस प्रकार से संक्रमित करता है और उसके बाद वह किस प्रकार से रोगी की कोशिकाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इस संबंध में लैब ने अपने नवीनतम नवोन्मेष में दो एनालिटिकल टूल्स को संयोजित किया है। इसमें एक 'रिपोर्टर' एमटीबी बैक्टीरिया है, जिसमें विभिन्न रंगों की चमक होती है और यह उपलब्ध वातावरण पर निर्भर करता है। दूसरा, सिंगल-सेल आरएनए सिक्वेंसिंग (एससीआरएनए-सिक्वे) है, जो रोगी के मैक्रोफेगस सेल्स (एक प्रकार का इम्यून सेल) का आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बनाता है।

रसेल ने बताया कि प्रयोग के दौरान चूहे को रिपोर्टर एमटीबी बैक्टीरिया से संक्रमित कराने के बाद चूहे के फेफड़े का अध्ययन किया। इसमें यह पता लगाया गया कि किस मैक्रोफेगस ने एमटीबी की वृद्धि (रेड ग्लोइंग बैक्टीरिया) को प्रोत्साहित किया या किसने एमटीबी को बढ़ने से रोकने (ग्रीन ग्लोइंग बैक्टीरिया) का काम किया। दोनों संक्रमित मैक्रोफेगस को छांट कर उन्हें सिंगल-सेल आरएनए सिक्वेंसिंग एनालिसिस से गुजारा गया। जिसमें दोनों के अलग ट्रांसक्रिप्शनल प्रोफाइल मिले।

मैक्रोफैगस सिंगल-सेल सिक्वेंसिंग डाटा की तुलना रिपोर्टर बैक्टीरिया फेनोटाइप से करने पर पाया कि बैक्टीरिया की फिटनेस और होस्ट सेल के ट्रांसक्रिप्शनल प्रोफाइल में मुकम्मल सहसंबंध हैं। ग्रीन बैक्टीरिया के मैक्रोफेगस ने बैक्टीरिया की वृद्धि को हतोत्साहित किया, जबकि रेड बैक्टीरिया के जीन को बैक्टीरिया की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला पाया गया। पहले के अध्ययन में एल्वीअलर मैक्रोफेगस (एएम) की पहचान सहयोगात्मक तथा ब्लड मोनोसाइट से निकले मैक्रोफेगस (आइएम) को एमटीबी के संक्रमण के नियंत्रक के रूप में की गई। लेकिन रसेल का कहना है कि यह बहुत सामान्य और सरलीकृत बात है। कुछ एएम सेल एमटीबी की वृद्धि को नियंत्रित करता है, जबकि कुछ आइएम सेल बैक्टीरिया के लिए सहायक थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये दोनों इम्यून सेल चूहे और इंसानों के फेफड़े के नमूनों में मौजूद होते हैं।



बेहतर होगा टीबी का निदान। फाइल फोटो

इम्यून सेल रिस्पांस में सुधार लाने वाले यौगिक की तलाश

रसेल ने बताया कि विश्लेषण से पता चला कि जब इन कोशिकाओं को एमटीबी या वैक्सीन स्ट्रेन से गुजारा गया तो रोग के नियंत्रण या उसके फैलने की क्रियाविधि पर काफी गहरा असर था। इस नई जानकारी के आधार पर इलाज का एक नया तरीका विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसे यौगिकों की तलाश की जा रही है, जो इम्यून सेल के रिस्पांस में सुधार ला सके। यदि ऐसे यौगिक मिल जाते हैं तो उनका इस्तेमाल एमटीबी रोधी के तौर पर किया जा सकता है और नई वैक्सीन बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।



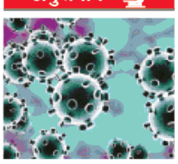
जंगल की आग बुझाने का नया तरीका...

जंगलों में लगी आग को बुझाने में आमतौर पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार इसके लिए हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब बड़े बैलून के सहारे ऐसे स्थानों पर आग बुझाने का एक नया तरीका निकाला गया है। इसी क्रम में दक्षिण पूर्वी फ्रांस के मार्सेल में कैप्टिव बैलून सेट की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। एएफपी

कोरोना के प्रभावी इलाज की खुली राह

अनुसंधान

कोरोना वायरस (कोविड-19) से मुकाबले के लिए प्रभावी उपचार की तलाश में निरंतर शोध किए जा रहे हैं। इसी कवायद में जुटे शोधकर्ताओं को बड़ी सफलता मिली है। उनकी इस खोज से कोरोना महामारी के खत्म होने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कोरोना पीड़ितों के नमूनों में पाए गए वायरल प्रोटीन में ऐसे अहम ड्रग-बाइंडिंग पाकेट की पहचान की है, जिससे इस वायरस के खिलाफ ज्यादा प्रभावी उपचारों के विकास की राह खुल सकती है। कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, इससे सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन के विकास की उम्मीद बढ़ी है। इसके जरिये कोरोना महामारी खत्म हो सकती है। प्रोटीओम रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित किए गए अध्ययन में कोरोना वायरस की 27 प्रजातियों और हजारों कोरोना पीड़ितों के नमूनों में वायरल प्रोटीन का विश्लेषण किया गया है। इसी में कोरोना के प्रोटीन से जुड़े इन बेहद सुरक्षित पाकेट की पहचान की गई। नई दवाओं में इन्हें साधा जा सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि वायरल प्रोटीन की थ्री-डी संरचना के जरिये ड्रग-बाइंडिंग पाकेट की पहचान की जा सकती है। हालांकि समय के साथ वायरस अपने प्रोटीन पाकेट में बदलाव कर सकता है। इस बदलाव से दवाओं का असर नहीं हो पाता है। उन्होंने बताया कि कुछ ड्रग-बाइंडिंग पाकेट प्रोटीन संबंधी काम के लिए इतने अनिवार्य होते हैं कि उनमें बदलाव नहीं हो सकता। ये पाकेट वायरसों में आमतौर पर समय के साथ संरक्षित हो जाते हैं। इसे निशाना बनाकर कोरोना से मुकाबला किया जा सकता है। -प्रेट्र



ड्रग बाइडिंग पाकेट की हुई पहचान। फाइल फोटो

फिल्म रिव्यू

कामेडी के चक्कर में खो गया मुद्दा

★★★

मिमी

प्रमुख कलाकार : कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, सई ताम्हणकर, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक
निर्देशक : लक्ष्मण उतेकर
अवधि : दो घंटे 12 मिनट
प्रसारण प्लेटफार्म : नेटफ्लिक्स और जिओ सिनेमा



राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित मराठी फिल्म 'मला आइ व्हायचय!' से प्रेरित 'मिमी' 30 जुलाई को नेटफ्लिक्स और जिओ सिनेमा पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे चार दिन पहले ही 26 जुलाई की शाम रिलीज कर दिया गया। बताया गया है कि ऐसा कृति सैनन को उनके जन्मतिथि (27 जुलाई) पर सरप्राइज देने के लिए किया गया।

खैर, कहानी है राजस्थान में रहने वाली मिमी (कृति सैनन) की, जो डांस परफॉर्मेंस के लिए शहर में मशहूर है। उसे मुंबई जाकर फिल्मों में हीरोइन बनना है। उसे पैसों की जरूरत है, ताकि वह फोटोशूट करा पाए। एक अमेरिकी जोड़ा सरोगेट मदर (किराये की कोख) की तलाश में भारत आता है। उन्हें मिमी पसंद आ जाती है। विदेशी जोड़े को शहर घुमाने वाला ड्राइवर भानु (पंकज त्रिपाठी) मिमी को सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार कर लेता है। डाक्टर बताती है कि मिमी की कोख में जो बच्चा है, वह मानसिक रूप से विकलांग हो सकता है। अमेरिकी जोड़ा बच्चे को मिमी की कोख में छोड़कर चला जाता है। क्या मिमी बच्चे को जन्म देगी या हीरोइन बनने के सपने को पूरा करेगी? इस मुद्दे पर फिल्म बनाने को लेकर निर्देशक लक्ष्मण उतेकर का प्रयास अच्छा है, लेकिन फिल्म की कहानी ही मात खा जाती है। फिल्म भले ही कामेडी ड्रामा हो, लेकिन मुद्दा गंभीर है। ऐसे में गंभीर दृश्यों में जो बात होनी चाहिए, वह नहीं दिखती। छोटे शहर की लड़की का सरोगेसी के लिए आसानी से मान जाना, माता-पिता का गर्भवती बेटी को आसानी से अपना लेना वास्तविकता से परे लगता है। हर इमोशन में फिल्म तेजी से भागती नजर आती है। शुरुआत में सरोगेट मदर्स का डीलर फोन पर अमेरिकी जोड़े से बात करता है, लेकिन बार-बार मां बनने की वजह से शारीरिक तौर पर कमजोर हो चुकीं सरोगेट मदर्स को लेकर विदेशी जोड़ा दिलचस्पी नहीं दिखाता। इस मुद्दे पर बात करने के बजाय फिल्म आगे बढ़ जाती है। रंगभेद, जातिवाद जैसे कई मुद्दों को कामेडी के लिए मसालों की तरह फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, जो हंसाने में असफल होते हैं।

कृति सैनन का अभिनय कहानी को हर मोड़ पर संभालता है। पंकज त्रिपाठी अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। मिमी के माता-पिता के किरदार में सुप्रिया पाठक और मनोज पाहवा का काम अच्छा है। फिल्म का डायलॉग 'बच्चा तो अंदर भी जिंदा होता है, बड़ा होता है, खाता है, हाथ पैर चलाता है, मुझे तो लगता है कि हमारी बातें भी सुनता है। फिर उसे बाहर मारना गलत और अंदर मारना सही, ऐसा क्यों। उसे अंदर ही क्यों नहीं अपना लेते हैं लोग...' सोचने पर मजबूर करता है। फिल्म का गाना परम सुंदरी डिजिटल पर बड़े पर्दे का जादू जगाता है।

-प्रियंका सिंह

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

लगता था कि टीवी में से लोग मुझे देख सकते हैं : मृणाल



मृणाल ने टीवी से की थी शुरुआत। इंस्टाग्राम

बचपन से जुड़ी कई यादें होती हैं, जिसके बारे में बाद में सोचकर हंसी आती है। सुपर 30 फिल्म की अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने भी एक लाइव चैट के दौरान बचपन की यादें साझा की। उन्होंने बताया कि जब मैं छोटी थी, तब मैं शाट्स पहनकर घर में घूमा करती थी। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा कि तुम घर में शाट्स पहनकर घूम रही हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है टीवी पर जो एंकर न्यूज पढ़ रही है, वह तुम्हें देख सकती हैं। मैं इतनी डर गई कि मैंने तुरंत घर में लगे पर्दे को अपनी ओर खींच लिया। मुझे लगा वाकई में टीवी में से मुझे लोग देख सकते हैं। दरअसल, टीवी से कई यादें जुड़ी हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब मुझे टीवी देखने की इजाजत नहीं थी। तब फिल्में शनिवार और रविवार को दिखाई जाती थी, उन फिल्मों को देखने के लिए मुझे सोमवार से शुक्रवार तक सिर्फ पढ़ना पड़ता था। मैं इंतजार करती थी कि कब मेरी परीक्षाएं खत्म होंगी और मैं पूरे दिन टीवी देख पाऊंगी। मेरे माता-पिता हमेशा कहते कि पढ़ाई करो, लेकिन मुझे जिस चीज से दूर रखा गया, मैं उसी के करीब पहुंच गई।

मुश्किल दिनों में परिवार से सबसे ज्यादा मदद मिलती है : सुप्रिया पाठक

उतार-चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन उतार-चढ़ाव के दौरान इंसान कैसे खुद को संभालता है, उसी से उसका व्यक्तित्व निखरकर सामने आता है। हिंदी सिनेमा में बीते करीब चार दशकों से सक्रिय अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का मानना है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, लेकिन हर शख्स को उससे उठकर आगे आना चाहिए। दैनिक जागरण से बातचीत में सुप्रिया ने कहा, 'हर इंसान की जिंदगी में उतार-चढ़ाव आता है और हर इंसान को मुश्किलों से उठकर आगे आना चाहिए। इसके लिए आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। मेरी जिंदगी में भी बहुत उतार-चढ़ाव आए। मेरी जिंदगी ऐसे कई मौके आए, जब मुझे लगा कि अब क्या होगा? क्या यह मेरे करियर का अंत है? ऐसे में नकारात्मक ख्यालों से दूर रहना सबसे जरूरी होता है। इसमें आपका परिवार आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। आपके स्वजन आस-पास होते हैं, वह आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आप उनके साथ अपने हर अनुभव सहजता से साझा कर सकते हैं। मेरे मुश्किल दिनों में मेरे बच्चों और परिवार से सबसे ज्यादा मदद मिली। हम सबने एक साथ मिलकर बुरे वक्त का सामना किया। इसके अलावा मैं ईश्वर की शक्ति में भी विश्वास करती हूं, वह विश्वास मुझे हर मुश्किल से उठकर खड़े होने में बहुत मदद करता है।' सुप्रिया हालिया रिलीज फिल्मों मिमी और तूफान में नजर आईं।



हालिया रिलीज फिल्म तूफान और मिमी में नजर आईं सुप्रिया। इंटरनेट मीडिया

सिद्धार्थ मल्होत्रा से तुलना होने पर अभिषेक बच्चन ने दिया कुछ ऐसा जवाब

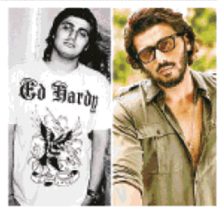
जब फिल्मों के रीमेक बनते हैं, तो कई बार मूल फिल्म के कलाकारों के काम से रीमेक फिल्म के कलाकारों की तुलना होती है। उसी किरदार को दूसरे कलाकार ने कैसे निभाया है, उस पर चर्चा होती है। ऐसा ही कुछ हुआ अभिषेक बच्चन के साथ भी। दरअसल, अभिषेक ने फिल्म एलओसी : कारगिल फिल्म में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया था। अब वह किरदार सिद्धार्थ मल्होत्रा विक्रम बत्रा की बायोपिक शेरशाह में निभा रहे हैं। ऐसे में दोनों की तुलना लाजमी है। अभिषेक के प्रशंसकों को उनका काम सिद्धार्थ से बेहतर लगा। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, 'शेरशाह का ट्रेलर शानदार है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए कोई मलाल नहीं है। वह शानदार अभिनेता हैं, बढ़िया काम किया है। लेकिन बुरा मत मानिए, मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन ने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल एलओसी : कारगिल फिल्म में उनसे बेहतर किया था। वह उनसे ज्यादा एनर्जेटिक थे, खासतौर पर ये दिल मांगे मोर और दुर्गा माता की जय जैसे डायलॉग्स में।' इस पर अभिषेक ने जवाब में हाथ जोड़े हुए इमोजी पोस्ट की। साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म एलओसी : कारगिल का निर्देशन जे पी दत्ता ने किया था।



एलओसी : कारगिल फिल्म में अभिषेक निभा चुके हैं कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार। इंस्टाग्राम

पहले मैं बहुत मोटा, बहुत परेशान था : अर्जुन कपूर

इंसान को अपनी हर परिस्थिति को स्वीकार कर हर पल का आनंद उठाना चाहिए। अभिनेता अर्जुन कपूर ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर साझा की गई अपनी तस्वीर से कुछ यही बातें कहने की कोशिश की। यह तस्वीर अर्जुन की दो तस्वीरों से बनी है, जिसमें एक पुरानी तस्वीर है, जब अर्जुन काफी मोटे हुआ करते थे और फिल्मों में नहीं आए थे। दूसरी तस्वीर वर्तमान की है, जिसमें वह काफी फिट और तंदुरुस्त हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'पहले मैं बहुत मोटा और बहुत परेशान था.. नहीं, नहीं यह उस किस्म की पोस्ट नहीं है। इसे सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूं कि मुझे अपनी जिंदगी के हर पड़ाव से प्यार है। उन दिनों में और अब भी मैंने जीवन के हर पड़ाव पर अपनी जिंदगी जी है और हर पल का जश्न मनाया है। सभी की तरह जिंदगी में मेरा भी काम अभी प्रगति पर है। मेरी मां ने मुझसे कहा था कि आपके जीवन का हर पड़ाव एक सफर है, जिस पर आप हमेशा लगातार काम करते रहेंगे। अब मैं उनकी बातों का मतलब अधिक गहराई से समझता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं खुद को बेहतर बनाने की दिशा में हर दिन काम कर रहा हूं।' अर्जुन आगामी दिनों में भूत पुलिस और एक विलन रिटर्न्स जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।



मोटापे से लेकर फिटनेस तक का सफर फोटो में दिखाया अर्जुन ने। इंस्टाग्राम

कोरोना काल में शूटिंग पर बढ़े खर्च की एक बानगी डार्लिंग्स फिल्म के मामले में दिख रही है। यहां 100 लोगों की टीम के लिए होटल का एक हिस्सा बुक करना पड़ा है ताकि सब बायो बबल में रह सकें।

पांच सितारा होटल में रुकी है डार्लिंग्स की टीम



‹‹ डार्लिंग्स से निर्माता बनी हैं आलिया • जागरण आर्काइव

कोरोना काल में निर्माताओं के लिए शूटिंग करना महंगा होता जा रहा है। इस बढ़ी लागत का सामना नई-नई निर्माता बनीं आलिया भट्ट को भी करना पड़ रहा है। शाह रुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और आलिया भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शन्स मिलकर डार्लिंग्स फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। आलिया अपनी पहली फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क हैं। वह कोरोना महामारी के इस माहौल में अपने टीम मेंबर्स का पूरा ख्याल रख रही हैं। खबरों के मुताबिक, आलिया ने अपनी फिल्म के 100 टीम मेंबर्स को मुंबई के एक पांच सितारा होटल में ठहराया है। सभी लोग बायो बबल (इसमें पूरी टीम को बाहरी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होती है) में रहें, इसके लिए होटल के एक बड़े हिस्से को दूसरे लोगों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। डार्लिंग्स का शेड्यूल पहले 50 क्रू मेंबर्स के साथ शुरू हुआ था, लेकिन कुछ सीन्स के लिए और 50 जूनियर आर्टिस्ट की जरूरत थी। दो बार कोरोना टेस्ट के बाद उन्हें भी फिल्म में शामिल कर लिया गया। अब इन 100 क्रू मेंबर्स के साथ जहां इनडोर की शूटिंग होटल में ही हो रही है, वहीं आउटडोर शूटिंग मुंबई के अंधेरी इलाके में चल रही है। आउटडोर शूटिंग के लिए जो गाड़ियां टीम को दी गई हैं, उन्हीं में उन्हें लोकेशन तक पहुंचना होता है। सैनिटाइजेशन के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है, जो साफ-सफाई का खास ध्यान रखती है। जाहिर है कि सामान्य की तुलना में खर्च बढ़ गया है। फिल्म में आलिया के अलावा शेफाली शाह और विजय वर्मा भी अहम भूमिकाओं में हैं। डार्लिंग्स की शूटिंग इसी महीने शुरू हुई है।

रूद्र में मुझे ग्रे किरदार बहुत ज्यादा पसंद आया



डिजिटल प्लेटफार्म पर पदार्पण करने के लिए तैयार हैं अजय देवगन • इंस्टाग्राम

डिजिटल प्लेटफार्म सिनेमा के फार्मूले से हटकर न सिर्फ निर्माताओं को नए प्रयोग करने के मौके दे रहा है, बल्कि सिनेमा के सुपरस्टार्स भी इस प्लेटफार्म पर फिल्मों में बनी अपनी छवि से अलग प्रयोग कर रहे हैं। अभिनेता अजय देवगन भी आगामी वेब सीरीज रूद्रः द एज आफ डार्कनेस से डिजिटल प्लेटफार्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं। यह साल 2010 में शुरू हुए ब्रिटिश शो लूथर का भारतीय रूपांतरण होगा। अजय का कहना है, 'जब मैंने गौरव बजाज (प्रेसिडेंट और हेड, स्टार इंडिया) के कहने पर मूल शो देखा तो मुझे वह बहुत पसंद आया। मुझे यह इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसके किरदार रियलिस्टिक (वास्तविक) हैं। हर शख्स के व्यक्तित्व में थोड़े-बहुत ग्रे शेड्स होते हैं। मुझे रूद्रः द एज आफ डार्कनेस में अपने किरदार की यही चीज सबसे ज्यादा पसंद आई।' अजय ने एक वर्चुअल कांफ्रेंस में यह बात कही। इस कांफ्रेंस में अजय के साथ शबाना आजमी, कुणाल कपूर, कीर्ति कुल्हारी, शेफाली शाह, प्रतीक गांधी, रिचा चड्ढा और सिद्धार्थ सूर्यनारायण जैसे कलाकार भी जुड़े थे।

फुकरे 3 के न किरदार बदलेंगे, न स्क्रिप्ट बदलेगी

कोरोना काल में कई निर्माताओं ने फिल्मों की लोकेशन और स्क्रिप्ट में बदलाव किए हैं। हालांकि निर्देशक और लेखक मृगदीप सिंह लांबा का कहना है कि उन्होंने फुकरे 3 की स्क्रिप्ट और लोकेशन में कोई बदलाव नहीं किया है। दैनिक जागरण से बातचीत में मृगदीप कहते हैं कि स्क्रिप्ट और लोकेशन में कोई बदलाव न करना पड़े, इसलिए हमने फिल्म की शूटिंग को आठ से नौ महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। जो लिखा है, उसी स्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी फिल्म के साथ-साथ जो फिल्में बंद हुई थीं, उनकी शूटिंग फिर से शुरू हो गई है। हमें उम्मीद है कि हम जिन जगहों पर फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, वहां हमें इजाजत मिल जाएगी। फुकरे की शूटिंग ज्यादातर आउटडोर ही होती आई है। दिल्ली फिल्म का सबसे बड़ा किरदार है। वहां जाकर अगर शूट न कर पाएं, तो कोई फायदा नहीं है। फिल्म को इतने समय तक रोकना आसान नहीं है। जहां फिल्म के किरदारों में बदलाव की बात है, तो फिल्म के किसी भी प्रसिद्ध किरदार फिर चाहे वह चूचा हो या भोली पंजाबन उनमें बदलाव करना, न करना एक रिस्क ही है। फुकरे और फुकरे रिटर्न्स फिल्म के बाद यह जनता के किरदार बन चुके हैं। वह जानते हैं कि यह किरदार किस परिस्थिति में कैसे बर्ताव करेंगे। फिर भी एक नई कहानी को कहने की कोशिश करेंगे। तीसरे पार्ट में तीन गुना मजा दर्शकों को मिलेगा।



रिचा चड्ढा फिल्म में फिर दिखेंगी भोली पंजाबन के किरदार में • इंस्टाग्राम

जातिवाद के मुद्दे पर प्रकाश डालती है फिल्म '200'



फिल्म 200 में सैराट फिल्म की अभिनेत्री रिंकू राजगुरु भी दिखेंगी • इंस्टाग्राम

इन दिनों फिल्म निर्माता वास्तविक घटनाओं और कहानियों को फिल्मों के तौर पर स्क्रीन पर दिखाने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। अब सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों में फिल्म 200 का नाम भी जुड़ गया है। डिजिटल प्लेटफार्म जी5 के लिए बन रही यह फिल्म साल 2004 में नागपुर में करीब 200 महिलाओं द्वारा की गई भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव की हत्या पर आधारित है। इस घटना में करीब दो सौ महिलाओं ने कोर्ट परिसर में ही अक्कू यादव को मार डाला था। फिल्म में अभिनेता अमोल पालेकर, वरुण सोबती, इंद्रनील सेनगुप्ता और अभिनेत्री रिंकू राजगुरु अहम भूमिकाओं में होंगे। सारेगामा फिल्म्स द्वारा बनाई जा रही इस फिल्म का निर्देशन सार्थक दासगुप्ता करेंगे। इस फिल्म के बारे में सारेगामा फिल्म्स के वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ आनंद कुमार ने कहा, 'यह फिल्म वास्तविक और प्रासंगिक विषय पर आधारित एक सशक्त कहानी है। यह हमारी न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाती है। हमें उम्मीद है कि यह फिल्म समाज में जातिवाद और न्याय व्यवस्था की कमियों पर एक नई बहस छेड़ेगी।' इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है।